चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

30 दिसंबर 2013–05 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

लोकपाल क़ानून

अन्ना के संघर्ष का परिणाम

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

रालेगण सिद्धी में अन्ना हजारे ने नौ दिनों तक अनशन किया. इस अनशन के साथ साथ जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता देश के कई शहरों और क़स्बों में धरना–प्रदर्शन व अनशन करते रहे. नेशनल मीडिया में उन्हें दिखाया नहीं गया, लेकिन क्षेत्रीय अख़बारों और टीवी चैनलों ने स्थानीय आंदोलनों को जमकर दिखाया. देशभर में दो सौ से ज्यादा जगहों पर अन्ना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे. सरकार को लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि 2011 की तरह अगर नेशनल मीडिया ने अलग–अलग शहरों के बारे में ख़बरें दिखानी शुरू कीं तो इस बार का आंदोलन पिछली बार से ज्यादा बड़ा बन सकता है. चार राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी. साथ ही यह संसद का आख़िरी सत्र था. अन्ना पहले से ही पत्राचार के माध्यम से इतनी दलीलें इकट्ठी कर चुके थे कि लोकपाल बिल पास न करने का कोई बहाना सरकार के पास बचा नहीं था.

जो लोकपाल बिल पास हुआ है, उसके बारे में यह भ्रम फैलाया गया कि यह एक कमज़ोर बिल है. इससे चूहे भी नहीं पकड़े जा सकते. यह एक मिथ्या है, जिसका पर्दाफ़ाश उस दिन ही हो जाएगा, जिस दिन से लोकपाल की संस्था अपना काम शुरू करेगी.

अन्ना के आंदोलन और लोकपाल बिल के पास होने से सबसे ज्यादा नुक़सान आम आदमी पार्टी का हुआ है. उन्हें अन्ना से नाराज़ होने का हक़ है. अफ़वाह फ़ैलाने का हक़ है और जिन लोगों ने अन्ना का साथ दिया, उन्हें अपशब्द कहने के लिए भी माफ़ किया जाना चाहिए.

अन्ना ने नौ दिनों तक लगातार अनशन किया. आख़िरी दो दिनों में उनकी तबियत बिगड़ने लगी थी. उनकी किडनी पर असर पड़ने लगा था. अन्ना का संघर्ष और त्याग की रणनीति ने रंग दिखाया और संसद में लोकपाल बिल पारित हो गया. लोकसभा में बिल के पारित होते ही अन्ना ने अपना अनशन तोड़ा. कई लोगों को यह विश्वास नहीं था कि लोकपाल बिल पास हो पाएगा. लोकपाल बिल पास होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको बताते हैं.

अन्ना की तैयारी पक्की थी. उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस लोकसभा के भंग होने से पहले लोकपाल बिल पास करा के रहेंगे. उन्होंने इसके लिए कई महीने पहले से प्रधानमंत्री से पत्राचार शुरू किया. और सरकार के जबाव का इंतज़ार भी किया. उन्होंने हर चिट्ठी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनका वादा याद दिलाया. बार–बार उन्होंने उनके द्वारा लिखे पत्र भेजकर अनशन छोड़ने का आग्रह याद दिलाया, साथ ही 27 अगस्त 2011 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की याद दिलाई. इन पत्रों के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अन्ना को चिट्ठी लिखी. पहले वर्षाकालीन सत्र में लोकपाल बिल लाने का आश्वासन मिला, लेकिन सरकार ने बिल पेश नहीं किया. दरअसल, लोकपाल बिल 27 दिसंबर 2011 को ही लोकसभा में पारित हो चुका था. यही बिल 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका. वैसे भी यह एक कमज़ोर बिल था. इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया. इस कमेटी में सभी दल के सदस्य थे. इसके चैयरमैन कांग्रेस पार्टी के सत्यव्रत चतुर्वेदी थे. कमेटी में भाजपा नेता अरुण जेटली भी थे. सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर गहन चिंतन किया और एक नया बिल तैयार किया, जिसे 23 नवंबर 2012 को वापस राज्यसभा में भेज दिया. यह बिल तब से राज्यसभा में लटका पड़ा था. इसी बात को लेकर अन्ना लगातार पत्र में लिख रहे थे कि अब देर करने की ज़रूरत नहीं है. इसे फौरन पास कर दिया जाए. सत्र पर सत्र बीतता चला गया, लेकिन सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया. चूंकि, बिल में बदलाव किया गया था, इसलिए इस नए बिल को राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में भी पास होना था. लोकसभा चुनाव से पहले यह आख़िरी सत्र था, इसलिए अन्ना ने इस समय को चुना और प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखकर बता दिया कि वो शीतकालीन सत्र के पहले दिन से फिर से अनशन पर बैठेंगे, ताकि इस बिल को पास किया जा सके.

अन्ना ने पहले यह कहा था कि वो रामलीला मैदान में अनशन करेंगे, लेकिन एक महीने पहले उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फ़ैसला बदला और अपने गांव रालेगण सिद्धी के यादव बाबा मंदिर में अनशन करने का फ़ैसला किया. 2011 में जब अन्ना ने अनशन किया था तो लोग स्वत: सड़कों पर उतरे थे. लेकिन अन्ना ने 2013 में सात राज्यों का दौरा किया. इन राज्यों में अन्ना की जनतंत्र यात्रा हर ज़िले में गई. जिसकी वजह से जनतंत्र मोर्चा का संगठन पूरी तरह अन्ना के साथ खड़ा था. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के हर ज़िले में अन्ना के साथ आंदोलन करने के लिए लोग मिल गए. संसद का जब सत्र शुरू हुआ, तब लोकपाल बिल संसद की कार्रवाई के एजेंडे में नहीं था. लेकिन जैसे ही अन्ना ने अनशन शुरू किया और देश में धरना–प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ तो सरकार ने फ़ौरन लोकपाल बिल को एजेंडे में शामिल किया. सरकार ने कहा, वह इसी सत्र में लोकपाल बिल पास करेगी. लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई. समाजवादी पार्टी लोकपाल बिल के विरोध में खड़ी हो गई. पार्टी ने कहा कि वो संसद चलने नहीं देगी. राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया. इस बीच राहुल गांधी ने आगे बढ़कर देश को यह आश्वासन दिया कि किसी भी क़ीमत पर लोकपाल बिल पास किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि वो बिना बहस के भी लोकपाल बिल पास करने पर तैयार है. लेकिन समाजवादी पार्टी टस से मस नहीं हुई. उनका विरोध इस बात को लेकर था कि अगर दो सौ करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पीएम की कुर्सी के क़ाबिल कौन 04

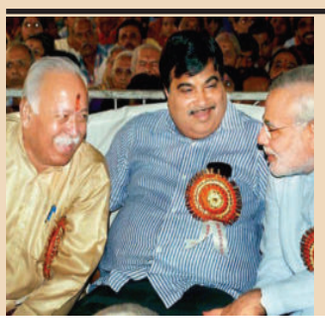

संघ ने संभाली उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान 05

दंगा पीड़ितों के पुर्नवास का संकट 07

साई की महिमा 12

अन्ना के संघर्ष का परिणाम

पृष्ठ एक का शेष

प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता है तो देश में कोई ईमानदार नहीं है. समाजवादी पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री को लोकपाल क़ानून के दायरे से बाहर रखा जाए. वैसे उनकी योजना यह थी कि वो लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा करेंगे और संसद को चलने नहीं देंगे. अगर लोकसभा और राज्यसभा चलेगी ही नहीं, तो बिल भी पास नहीं हो पाएगा.

पिछली बार अनशन के दौरान एक ग़लती हुई थी कि अन्ना हजारे की टीम की तरफ़ से किसी ने राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित नहीं किया था. अनशन के मंच से और मीडिया में टीम अन्ना के लोग लगातार सासदों को गालियां देते रहे. उन्हें भ्रष्ट, मूर्ख, स्वार्थी और अनपढ़ कहते रहे. संवादहीनता की स्थिति में सारी पार्टियां अन्ना के विरोध में खड़ी हो गईं. इस बार चौथी दुनिया के प्रधान संपादक और अन्ना के प्रशंसक संतोष भारतीय जी ने दूसरी योजना बनाई. अनशन की शुरुआत से वो अन्ना के साथ रालेगण सिद्धी में थे. लेकिन बिल पास न होने का ख़तरा मंडराता देख वो दिल्ली लौट आए. इसके कई फ़ायदे हुए. एक तरफ़ मीडिया में अफ़वाहें फैल रही थीं. इस अफ़वाह को फ़ैलाने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अहम रोल रहा. हर टीवी चैनलों ने एक भ्रम स्थिति पैदा कर दी. संतोष जी ने हर टीवी चैलनों पर बहस में हिस्सा लेकर इस भ्रम की स्थिति को साफ़ किया. सही बात लोगों व पार्टियों के सामने आई. जिसके बाद राहुल गांधी का बयान आया और भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति साफ़ हो गई कि दोनों ही पार्टियां लोकपाल पास कराना चाहती हैं. अब सिर्फ़ समाजवादी पार्टी का विरोध बच गया था. उन्होंने समाजवादी पार्टी के दो नेताओं से संसद के अंदर ही मुलाक़ात की और उन्हें इस बिल के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन मांगा. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल ने संतोष जी को यह आश्वासन दिया कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हम अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे. इसके बाद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह से बात की. समाजवादी पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि वो हंगामा करके बिल को रोकने के बजाए सदन से वाक-आउट करेंगे. इस तरह दोनों सदनों में बहस के बाद लोकपाल बिल पास किया गया और अन्ना ने नौ दिन का अनशन ख़त्म किया.

जो लोकपाल बिल पास हुआ है, उसके बारे में यह भ्रम फ़ैलाया गया कि यह एक कमज़ोर बिल है. इससे चूहे भी नहीं पकड़े जा सकते. यह एक मिथ्या है, जिसका पर्दाफ़ाश उस दिन ही हो जाएगा जिस दिन से लोकपाल की संस्था अपना काम शुरू करेगी. इस विषय पर सबसे ज्यादा चिंतित आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है. समझने वाली बात यह है कि इस पार्टी का जन्म ही लोकपाल लाने के लिए हुआ था. अब जब यह पास हो गया है, तो वो इस बिल की नुक़्ताचीनी में लगे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच पर किसी का दबाव काम करेगा या नहीं. यह भ्रम फ़ैलाया जा रहा है कि सीबीआई को स्वायत्ता नहीं दी गई है. यह अर्धसत्य है. इसका साधारण सा जवाब है कि वर्तमान बिल में जांच को स्वायत्ता दी गई है. असलियत यह है कि इस बिल में अभियोजन निदेशालय का गठन होने का प्रावधान है. सीवीसी की रेकमेंडेशन पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति होगी. यहां तक कि यह भी साफ़ किया गया है कि लोकपाल द्वारा रेफर किए गए केसों की जांच करने वाले अधिकारियों का तबादला बिना लोकपाल की मर्ज़ी के न हो सकेगा. जिस केस की जांच लोकपाल के तहत होगी, उसमें शामिल सीबीआई अधिकारी सरकार के अधीन नहीं होंगे और न ही कोई निर्देश लेंगे. सीबीआई ऐसे मामलों में सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकपाल के प्रति ज़िम्मेदार होगी. दूसरा भ्रम लोकपाल की नियुक्ति को लेकर है. जो पुराना बिल था उसमें लोकपाल की नियुक्ति एक कमेटी करेगी, जिसके सदस्य उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के नेता, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, क़ानून और गृहमंत्री होंगे. लेकिन अब जो बिल पास हुआ है उसमें इसे बदल दिया गया है. अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट के जज और न्यायविद होंगे. कहने का मतलब यह कि पहले जो प्रक्रिया थी, उसमें सरकार अपने हिसाब से लोकायुक्त को नियुक्त कर सकती थी, लेकिन अब सेलेक्शन कमेटी में सरकारी पक्ष बहुमत में नहीं है, इसलिए यह उम्मीद करनी चाहिए कि लोकपाल का चुनाव निष्पक्ष होगा. वैसे जो लोग इस बिल को कमज़ोर बता रहे हैं, उनके जनलोकपाल में तो हास्यास्पद तरीक़े से मैगसेसे अवार्ड के विजेता को भी सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाने का प्रावधान था.

समझने वाली बात यह है कि सरकार ने एक लोकपाल बिल तैयार किया था जो सचमुच कमज़ोर था. लेकिन सेलेक्ट कमेटी में गहन चिंतन के बाद जो लोकपाल बिल तैयार किया गया है, वह अलग है. यह कारगर लोकपाल बिल है. यह ऐसा लोकपाल बिल है, जिसे लागू करने में ज्यादा परेशानी नहीं है. एक बार यह काम करना शुरू करे, तब ही कमियों का भी पता चलेगा. अगर कोई कमियां सामने आईं तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश है. जो भी सुधार होना है वह भी संसदीय प्रक्रिया से ही होगा. लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी तरह दूसरे लोग इस ज़िद पर अड़े रहे कि उनका ही लोकपाल मज़बूत है, बाक़ी सब जोकपाल है तो वो लोकतांत्रिक तरीक़े से अपनी मनमर्ज़ी का लोकपाल बनाने को आज़ाद हैं. लेकिन जिस बिल को अन्ना ने मान लिया, जनरल वी के सिंह ने मान लिया, किरण बेदी ने मान लिया, जस्टिस हेगड़े ने भी मान लिया, ऐसे बिल को जोकपाल बताकर अरविंद बिल की खिल्ली नहीं उड़ा रहे, बल्कि संसद और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने वाले विश्वसनीय लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं.

वैसे केजरीवाल का विरोध लाजिमी भी है. अब वो अन्ना की तरह आंदोलनकारी नहीं हैं. अरविंद एक पार्टी के सुप्रीमो हैं. ऐसी पार्टी, जिसका जन्म ही जनलोकपाल के मुद्दे पर हुआ. अब उनके हाथ से यह मुद्दा निकल गया तो नाराज़गी तो वाजिब है. 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अलग पार्टी बना ली. पार्टी बनाने के लिए यह दलील दी गई कि आंदोलन के ज़रिए देश को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सशक्त लोकपाल नहीं दिया जा सकता है. अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का मानना है कि चुनावी राजनीति के ज़रिए वो विधानसभाओं और लोकसभाओं में अपने लोगों को भेजेंगे और जब संसद में उनका बहुमत हो जाएगा तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी जन-लोकपाल क़ानून बनाएगी. दो रास्ते, दो विचार और दो नेता. एक तरफ़ अन्ना हैं जो यह कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ़ प्रजातांत्रिक आंदोलन के ज़रिए हो सकता है. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल व्यवस्था का हिस्सा बनकर व्यवस्था बदलने की रणनीति को सही मानते हैं. जबकि इतिहास गवाह है कि जो भी लोग व्यवस्था का हिस्सा बने वो व्यवस्था को बदल नहीं सके. हिंदुस्तान में वामपंथी पार्टियां एक सटीक उदाहरण हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद यह तय किया था कि वो चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगी और व्यवस्था परिवर्तन करेंगी. लेकिन 65 साल बीत गए और वामपंथी पार्टियों ने कई राज्यों में राज भी किया. लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य भी भेजे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का उनका सपना, सपना ही रहा. समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास तो वामपंथी पार्टियों की तरह कोई समग्र विचारधारा भी नहीं है. केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन उनके सामने भविष्य का कोई नक्शा नहीं है. जनतंत्र मोर्चे की भूमिका संभवत: अब ख़त्म होती नज़र आ रही है. अब अन्ना को नये आंदोलन के लिए नया संगठन बनाना चाहिए.

आज अन्ना के आंदोलन और लोकपाल बिल के पास होने से सबसे ज्यादा नुक़सान आम आदमी पार्टी का हुआ है. उन्हें अन्ना से नाराज़ होने का हक़ है. अफ़वाह फ़ैलाने का हक़ है और जिन लोगों ने अन्ना का साथ दिया, उन्हें अपशब्द कहने के लिए भी माफ़ किया जाना चाहिए. यह इसलिए क्योंकि इन लोगों ने उनके हाथ से उनका सबसे बहुमूल्य मुद्दा छीना लिया है. अन्ना ने अपने त्याग और संघर्ष से लोकपाल का महासंग्राम जीता है. 2011 के आंदोलन के बाद अरविंद और उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया. जनतंत्र मोर्चे के ज़रिए उन्होंने देश में फिर से एक आंदोलन को शून्य से शुरू किया. देश भर की यात्रा की. लोगों को जागरूक किया. और जब मौक़ा आया तो उन्होंने अनशन किया और देश को लोकपाल दिलाने में सफल हुए. कई लोग भारत को समझने में ग़लती करते हैं. भारत की राजनीति और यहां का प्रजातंत्र यांत्रिक नहीं, बल्कि यह एक सजीव चेतना है. यहां चुतर चालाक और अतिबुद्धिमान राजनेता की कोई अहमियत नहीं है. यह देश हमेशा से त्याग को पूजता रहा है. गांधी हों, जयप्रकाश हों या फिर अन्ना, ऐसे लोगों से जो भी कटराएगा, जनता उनके घमंड को चूर-चूर कर देगी. ■

manish@chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 43
दिल्ली, 30 दिसंबर 2013–05 जनवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

उच्चपदों पर रिक्तियां

दिलीप चेरियन

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जैसी बिना प्रमुखों के चलने वाली हवाई संस्थाओं की संख्या में इज़ाफ़ा होता जा रहा है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) भी जल्दी ही इस सूची में शामिल होने जा रही हैं. पहली दो संस्थाएं पिछले एक साल से बिना किसी प्रमुख के कार्य कर रही हैं. डीजीसीए और एएआई जैसे संस्थान भी इस महीने के अंत में प्रमुख-विहीन होने वाले हैं. डीजीसीए के प्रमुख अरुण मिश्रा को गृह कैडर बंगाल या विदेशी एसांइनमेंट पर देश के बाहर भेजा जा सकता है. इसी तरह एएआई के अध्यक्ष वी पी अग्रवाल अपने पांच साल का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद सेवा विस्तार किए जाने की बाट जोह रहे हैं. मिश्रा की पोस्ट पर बड़ी दिलचस्पी से आंख गड़ाए लोगों में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) रोहित नंदन भी शामिल हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह का कहना है कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है! ■

नेतागिरी के इशारे

यह कहा जाता है कि नौकरशाह मौसमी घटनाओं के बेहतरीन छात्र होते हैं, ख़ासकर बदलती हवाओं के. सिर पर मंडराते चुनावों के मद्देनज़र ये नेताओं से ज्यादा उपयुक्त चालें चल रहे हैं. हाल ही में पूर्व गृह सचिव आर के सिंह और पूर्व पेट्रोलियम सचिव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं, उनके इस क़दम की वजह से दिल्ली के नौकरशाही गलियारे में कइयों की भौंहें तन गईं. सूत्रों का कहना है कि दोनों के बिहार से लोकसभा के चुनाव लड़ने की संभावना है. लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ और नौकरशाहों की भी नेतागिरी की ओर रुख़ करने की संभावना है जिनमें से साफ़ तौर पर एक नाम यूनाइटेड किंगडम की पूर्व राजनयिक जौमिनी भगवती का है. 1976 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भगवती केंद्रीय वित्त मंत्रालय और वाशिंगटन में विश्व वैंक में भी काम कर चुकी हैं. वह बेल्जियम,लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में भारत की राजदूत भी रह चुकी हैं. ■

बाबू नहीं हिलेंगे

केंद्र की यूपीए सरकार के लिए सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के अंतर्गत केंद्रीय विभागों की जानकारी लोगों के साथ साझा करना कठिन हो रहा है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय विभागों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रपति सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी शामिल थे. डीओपीटी ने यह स्वीकार किया है कि सभी की प्रतिक्रिया बहुत ही दयनीय है. अधिकांश विभाग तो डीओपीटी को अनुपालन रिपोर्ट (कॉम्पलिएंस रिपोर्ट) भेजने में असफल रहे. सूत्रों का कहना है कि डीओपीटी के निदेशक संदीप जैन ने सभी विभागों के लिए एक और मेमो जारी किया है और यह बताने को कहा है कि उन्होंने क़ानून के तहत पारदर्शिता लागू करने के लिए किस तरह दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है. ज़ाहिर तौर पर डीओपीटी के सचिव एस के सरकार ने इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है. लेकिन क्या प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी? इस पार दांव न लगाएं! ■

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

रंजन स्थानांतरित

1993 बैच केएजीएमयू कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में स्थांतरित किया जा सकता है. वह अभी पुलिस (ईओडब्ल्यू) के संयुक्त आयुक्त हैं.

मोहन इंटरपोल में शामिल

1992 बैच के एजीएमयू कैडर के आईपीएस अधिकारी और पुलिस (लाईसेंसिंग) के संयुक्त आयुक्त मदन मोहन ओबरॉय को सिंगापुर के इंटरपोल इकाई में शामिल किया गया है.

विजय का स्थानांतरण

2005 बैच के एजीएमयू कैडर के आईपीएस अधिकारी और गोवा के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह को दिल्ली स्थांतरित किया गया है.

मीनाक्षी श्रम मंत्रालय से जुड़ीं

1984 बैच की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज अधिकारी मीनाक्षी गुप्ता को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है. उनका पद संयुक्त सचिव स्तर का होगा. यह नया पद सृजित किया गया है.

अनिल भारत सरकार में शामिल

1996 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अनिल कुमार जल्द ही भारत सरकार के अंतर्गत उपमहानिरीक्षक के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं. उनके नाम पर की गृह मंत्रालय में चर्चा चल रही है. ■

यह देश पिछले लगभग ढाई वर्षों के दौरान जनलोकपाल के इस आंदोलन के उतार–चढ़ाव का साक्षी बना. जब देश में लोकपाल की बात होनी शुरू हुई, तब अन्ना हजारे 32 वर्ष के थे. जब लागू हुआ तो 76. चव्वालीस वर्ष के इस संघर्ष ने कई दौर देखे हैं. लोकपाल कितना कारगर होगा. इसकी परिणति क्या होगी. यह सवाल शायद उठें. लेकिन इस सफलता ने हमें जो ताक़त दी, उसे और मज़बूत करना अब हमारी ज़िम्मेदारी है.

ढाई वर्ष के भीतर

मुकाम पर पहुंचे एक आंदोलन की कहानी

समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश की जनता के क़रीब तीन वर्षों के संघर्ष के बाद आख़िरकार जब देश की संसद ने लोकपाल बिल पास किया, तो बरबस ही कड़े संघर्ष के दौर की कई यादें ताज़ा हो गईं. जब देश की जनता अपनी रोज़मर्रा की पेरशानियों से जूझ रही थी, जब युवा पीढ़ी क्रिकेट, सिनेमा और फैशन में मशगूल थी और भ्रष्टाचार का घुन देश को छलनी कर रहा था, एक बूढ़े ने देश की आत्मा झकझोरा और परिवर्तन के लिए जनता का आह्वान किया, तो जनता उसके पीछे चल पड़ी. जनता के आने की आहट से डरी सरकार ने तमाम चालें चलीं, पैंतरे बदले, लेकिन आख़िरकार उसे लोकपाल बिल पास करना पडा. अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल के लिए चले आंदोलन पर एक नज़र...

नीरज सिंह

दो अप्रैल 2011. देश का हर नागरिक धोनी ब्रिगेड की तरफ उम्मीद लगाए बैठा था. देश 28 साल बाद एक बार फिर देश क्रिकेट विश्व कप हासिल करने जा रहा था. इस देश में क्रिकेट को धर्म के तौर माना जाता है, समझा जाता है. इसलिए यह ख़ुमारी जो दिन में उतर जाए, यह तो संभव ही नहीं है. लेकिन इस बार ऐसा होना था. पांच अप्रैल को टीवी पर छोटी–सी ख़बर चली कि समाजसेवी अन्ना हजारे ने जंतर–मंतर अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया. जितनी छोटी–सी जगह मीडिया ने इस ख़बर को दी थी, उससे यह विश्वास झलकता था अन्ना का शायद विश्व कप हासिल करने की ख़ुशी जितना ख़ुमार न पैदा कर पाए. अनशन के पहले दिन की शाम से ही देश कई भागों में बंटने लगा. एक हिस्सा था, जो खाए–अघाए की श्रेणी में आता है और अपने एयरकंडीशंड ड्राइंग रूम में बैठकर नीतियां तय करता है, उसे यह आंदोलन दो दिन में ख़त्म होता दिखाई दे रहा था. दूसरे वर्ग के लिए यह पिकनिक के तौर पर था कि चलो घूम आएंगे और देखेंगे के अपने राज्य में पांच मंत्रियों के इस्तीफा का कारण बना यह व्यक्ति हक़ीक़त में दिखता कैसे हैं. तीसरा वर्ग वह था, जो तरुणाई के दौर में था. जिसने गांधी को नहीं देखा था. जेपी के आंदोलन को नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि गांधी के पास इतना जनसमर्थन था कि उनके लिए कहा जाता है कि *चल पड़े जिधर दो डग, मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर.* जेपी के समय का उत्साह भी उसने सुना था, जब केंद्रीय सत्ता को चुनौती देते हुए नारा लगता था कि *सिंहासन खाली करो कि जनता आती है.* वह वर्ग अन्ना की इस मुहिम में एक बार उस दौर की वापसी देख रहा था. वह जंतर–मंतर पर मौजूद था.

आने वाले कुछ महीनों में जिस आंदोलन की लहरें पूरे देश को अपने ज़द में लेने वाली थीं, उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी लंबे समय से पर्दे के पीछे से तैयार की जा रही थी और उसकी मुख्य भूमिका में थे अन्ना हजारे. जनलोकपाल बिल के मसौदे को लेकर 1 दिसंबर 2010 को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस हुई. लेकिन तब मसौदे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि देश पिछले 42 सालों से लोकपाल कानून बनने और लागू करने की ख़बरों से आजिज़ आ चुका था. इस विषय पर सरकार की अगंभीरता को देखते हुए जनवरी 2011 के आख़िर में देश और विदेश के 52 शहरों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक मार्च निकाला गया. अन्ना हजारे भी इसमें शामिल थे. अब धीरे–धीरे भ्रष्टाचार की इस मुहिम को लेकर अन्ना हजारे की कोशिशों पर देश की नज़रें जाने लगी थीं. इसी कड़ी में 31 जनवरी को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अन्ना की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई. मांग थी कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ काम करने के लिए एक मज़बूत संस्था का गठन किया जाए, एक मज़बूत लोकपाल का गठन किया जाए, जिसे अन्ना हजारे ने नाम दिया जनलोकपाल.

ख़ैर, राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन में शामिल होने की प्रतिबद्धता की उम्मीद न तो किसी ने की ही थी और उन्होंने अन्ना की चिट्ठी पर चुप्पी साधकर इस उम्मीद को ग़लत होने भी नहीं दिया. राजनीतिक दलों के अनुत्साह को देखते हुए अन्ना हजारे ने फरवरी में प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर उनसे जनलोकपाल बिल पर कमेटी बनाने की मांग की और उसमें सिविल सोसाइटी के लिए बराबर की हिस्सेदारी मांगी, यानी पांच सदस्य सरकार के और पांच सिविल सोसाइटी के. इन पत्रों में अन्ना ने मांग नहीं माने जाने पर अप्रैल पांच से अनशन पर बैठने के अपने फ़ैसले के बारे में भी बताया था. एक–दूसरे को पत्र भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा. दोनों पक्ष एक–दूसरे को पत्र लिखते रहे. प्रधानमंत्री और अन्ना की मुलाकात भी हुई, मगर बात नहीं बनी. अन्ना अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार अपनी ज़िद पर.

चार अप्रैल को अन्ना हजारे और उनके उस दौर के सहयोगियों ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और देश को यह सूचना दी कि चूंकि सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जनलोकपाल जैसे किसी क़ानून को बनाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए अब अन्ना हजारे जनता की अदालत में जाएंगे और पांच अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे. छह तारीख़ की शाम तक देश के मीडिया और देश की बड़ी आबादी के कई अंदेशे ग़लत साबित होने लगे. अंदेशा कि आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में भला इस आंदोलन के लिए वक्त कौन निकाल पाएगा? अंदेशा कि लोग रविवार के दिन पिकनिक स्पॉट की शक्ल ले चुका जंतर–मंतर का मैदान क्या इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाएगा कि सरकार इस ओर अपना ध्यान दे? लोगों का उत्साह इन सभी अंदेशों का जवाब था. शाम ढल रही थी, लोग अपने घरों को जा रहे थे. एक मशहूर टेलीविजन एंकर ने जंतर–मंतर पर अपने मां–बाप के साथ लगभग तीन वर्षीय बच्ची से पूछा–बेटा यहां क्यों आए हो? बच्ची ने तोतली भाषा में जवाब दिया, भष्टाचाल मिताने. लोग जागने लगे. हर कोई अपने से ही यह सवाल पूछने लगा कि जंतर–मंतर नहीं गए तो क्या किया? भीड़ अब गिनती का दायरा पार करने लगी. मीडिया ने अपना तंबू वहीं गाड़ दिया. ओवी बैन लग गई. और हर तरफ बस इन्हीं तस्वीरों ने क़ब्ज़ा कर लिया *मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना. वी वांट जन लोकपाल.*

इस तस्वीर का कैनवास बड़ा हो रहा था. मुंबई के आज़ाद मैदान से लेकर बेंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी और देश के अन्य हिस्से तक. बड़े दिनों बाद गांधी टोपी फिल्मों के पर्दे से बाहर आई, जिस पर लिखा था मैं भी अन्ना. एक पल के लिए इन तस्वीरों पर यक़ीन करना आसान नहीं था. जनसैलाब की यह तस्वीर सरकार भी देख रही थी. सरकार और टीम अन्ना के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया था. इधर अलग–अलग बौद्धिक वर्ग के बीच भी बंटवारा हो गया था. बौद्धिक वर्ग को यह समस्या थी कि कैसे एक कम पढ़ा लिखा आदमी, और तो और वह अंग्रेजी बोलना भी नहीं जानता, भला वह कैसे इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व बन सकता है. धूमिल की एक कविता है कि *एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है. एक तीसरा आदमी भी है. जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है. वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है. मैं पूछता हूं. यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है.* उस तीसरे आदमी के बारे में बताने में इस देश की संसद हमेशा विफल रही है. अन्ना हजारे उसी तीसरे आदमी के बारे में जानना चाह रहे थे जो रोटी बनाने वाले और रोटी बेलने वाले के हक़ पर क़ब्ज़ा किए बैठा है. लेकिन देश की संसद इस बार लंबे समय तक मौन नहीं रह पाई.

सरकार चारों तरफ़ से घिर रही थी. भ्रष्टाचार के आरोपों से हलकान. जंतर–मंतर में जुटने वाली भीड़ जिस तरह से राजनीतिक वर्ग और ख़ासकर सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगा रही थी, सरकार उससे घबराने लगी थी. इसी दौर में कई सरकारी संदेशवाहक पैदा हो गए. कुछ संदेशवाहक ऐसे भी थे, जो अन्ना के भी साथ थे और सरकार के भी. स्वामी अग्निवेश का नाम उसी लिस्ट में शामिल है. अन्ना इन सबको परख रहे थे. आख़िर में सरकार झुकी और और बिल तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई, जिसमें पांच सरकारी और पांच टीम अन्ना के सदस्य रखे गए. जनता जीत के जश्न में थी. सबके मन में यही भावना थी, हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी. यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसके हम साक्षी बन रहे हैं. 'लोकतंत्र की जीत, पीपल्स विक्टरी' के नारे पांच तारीख़ से ही गूंज रहे थे, उनकी आवाज़ अब और बढ़ गई थी. अन्ना ने सरकार को 15 अगस्त तक बिल पास करने को कहा.

उसी दौर में लोगों ने अन्ना से सवाल पूछा कि अगर यह आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, तो क्या आप दूसरे महात्मा हैं? अन्ना ने अपने चिर–परिचित शालीन अंदाज़ में जवाब दिया कि मैं तो महात्मा गांधी के चरणों की धूल भी नहीं हूं. लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने इस देश पर बड़े एहसान किए हैं. हम देशवासी इस देश के गौरव को दोबारा हासिल करने के लिए उस एहसान का कुछ अंश भी चुका दें, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं. सरकार ने जब अन्ना की मांगों को माना, तभी यह सुगबुगाहट हुई कि यह सरकार इतनी जल्दी इस बात के लिए कैसे राजी हो गई. और सरकार की नीयत पर तभी से शक था. बहरहाल, संयुक्त समिति की बैठकें हुईं. जो पूर्वानुमान था हुआ भी वही. सरकार के मंत्रियों और सिविल सोसाइटी के बीच बैठक तो हुई, लेकिन किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई. शुरू से लग रहा था कि बात बननी ही नहीं है. अन्ना ने एक बार फिर घोषणा की कि अगर मानसून सत्र में लोकपाल बिल पास नहीं कराया गया तो 16 अगस्त से वे फिर से अनशन करेंगे.

16 अगस्त 2011 की सुबह देश के लिए सामान्य सुबह नहीं थी. क्योंकि आज हर कोई सुबह उठकर ही कुछ कर–गुज़रने की तैयारी में था. दिल्ली के हर रास्ते राजघाट की ओर जा रहे थे, क्योंकि अन्ना राजघाट पर गांधी जी की समाधि के दर्शन कर जनलोकपाल की अपनी लड़ाई को एक बार फिर शुरू करने वाले थे. हल्की बारिश हो रही थी. क्या होने वाला है, आमजन को पता नहीं था. लेकिन ख़ासजन को सब पता था और पूरी तैयारी थी. अन्ना घर से निकलते ही गिरफ़्तार कर लिए गए. टीवी के पर्दे पर लोगों के गुस्से की उभरती तस्वीरें. लोगों का हुजूम और जनता का उन्माद यह बताने के लिए काफ़ी था कि अब अवाम भ्रष्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ जाग गई है. यह सब कुछ स्वचालित था, प्रेरित नहीं. सैकड़ों की संख्या में लोग अन्ना को ले जा रही गाड़ी के साथ हो लिए थे. अन्ना चाहते थे कि उनके अनशन को आंदोलन की शक्ल मिले और सरकार ने आंदोलन शुरू होने के पहले ही उन्हें गिरफ़्तार करके एक और बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया. अन्ना शायद जानते थे कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने अपने संदेश को रिकॉर्ड कर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ़्तारी की स्थिति में जेल भरो, लेकिन शांति बनाए रखिए.

जेल शब्द ने देश की युवा पीढ़ी के भीतर एक ऊर्जा–सी भर दी. आंदोलन और जेल जैसे शब्द देश की युवा पीढ़ी को तिहाड़ की ओर खींच रहे थे. अन्ना जेल के अंदर थे. और बाहर लोगों का हुजूम. लोग एसएमएस करके और फोन करके अपने और दोस्तों को बुला रहे थे. लोगों को अपनी ही चुनी हुई सरकार अलोकतांत्रिक लग रही थी. यही हाल छत्रसाल स्टेडियम का था. अन्ना के समर्थकों को वहां गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था. सरकार का दांव उलट कर उसी पर पड़ा था. शाम तक सरकार अन्ना को रिहा करने का फ़ैसला कर चुकी थी. और अन्ना ने रामलीला मैदान में अनशन करने का फ़ैसला किया.

रामलीला मैदान वास्तव में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग और उस जंग के लिए की जा रही तमाम कोशिशों का गवाह बना. उस दौर में रामालीला मैदान में कई रंग देखने को मिले. ऐसे ही एक बैनर के सामने युवा कान पकड़कर उठ–बैठ रहे थे. उस बैनर पर लिखा था कि गलती हो गई जो कांग्रेस को वोट दिया. लोगों ने मैदान को ही अपना घर बना लिया. ऐसी ही एक सुबह रामलीला मैदान में अख़बार बिछाकर अपने पिता की गोद में सर रखकर निश्चिंतता से सोई हुई एक 14–15 वर्षीय मासूम–सी बालिका के पिता ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं. वह उन्हें इस आंदोलन में इसलिए लाया है, ताकि वह स्वयं देख सकें और महसूस कर सकें कि उनके भविष्य की बुनियाद ऐसे ही आंदोलनों से मज़बूती से रखी जा सकेगी. दिन बीत रहे थे, लेकिन न तो अन्ना का जज़्बा कम हो रहा था और न ही वहां उपस्थित होने वाली भीड़. कुछेक परिचित चेहरे उस भीड़ से ग़ायब हो जाते थे, तो कुछ नए वहां उपस्थित हो जाते थे. हर बीता हुआ दिन लोगों में एक संदेश दे जाता कि जब इस भूखे और बूढ़े हो चले व्यक्ति का उत्साह कम नहीं हो रहा है तो देश की जनता का उत्साह कम क्यों हो.

एक दिन अन्ना रसोई में खाना बनाते हुए एक बूढ़े (जिसकी तबियत थोड़ी ख़राब दिख रही थी) से किसी ने पूछा बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? उसका जबाब था कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अनशन. मैंने जेपी आंदोलन में भी भाग लिया था, पर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, यह बहुत कठिन सवाल है, जो आसानी से हल नहीं होगा. पर मैं यह चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी इसी भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा न ख़त्म कर दे. वह आगे बढ़े और बाकी देशों को पीछे छोड़ दे. एक नए भारत का निर्माण हो. चाहे मुझे कुछ और दिन भूखा क्यों न रहना पड़े. उत्तेजना में उस भूखे बाबा की आंखों से आंसू आ गए. उनका यह जवाब दिल को छू गया. आसपास खड़े लोगों को मुंह से बरबस निकल पड़ा– अन्ना अगर आप अपने उद्देश्य में सफल हुए तो आने वाली कई पीढ़ियां आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगी.

बहरहाल, यह देश पिछले लगभग ढाई वर्षों के दौरान जनलोकपाल के इस आंदोलन के उतार–चढ़ाव का साक्षी बना. जब देश में लोकपाल की बात होनी शुरू हुई, तब अन्ना हजारे 31 वर्ष के थे. जब लागू हुआ तो 75. 44 वर्ष के इस संघर्ष ने कई दौर देखे हैं. अन्ना ने गांधीवाद नहीं, गांधीगीरी को अपनाया. लोकपाल कितना कारगर होगा. इसकी परिणति क्या होगी. यह सवाल शायद उठें. लेकिन इस सफलता ने हमें जो ताक़त दी, उसे और मज़बूत करना अब हमारी ज़िम्मेदारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पीएम की कुर्सी के क़ाबिल कौन?

कृष्णकांत
feedback@chauthiduniya.com

पांच राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं. अगर किसी नये विकल्प के उभरने और नया फ्रंट गठित होने का करिश्मा नहीं होता है, तो बहुत संभावना है कि देश के दो बड़े दलों में से ही किसी एक की अगुआई में सरकार बनेगी, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों होता रहा है. जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, यह बहस भी तेज़ होती जा रही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी का क़द जिस तरह बढ़ा है, उससे साफ़ है कि अपनी पार्टी की तरफ़ से वे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. यानी अब यह तय है कि अगला आमचुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी लड़ा जाना है. आइए, देखते हैं कि इन दोनों नेताओं में वे कौन-सी ख़ूबियां हैं, जिनके कारण जनता इन्हें अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर सकती है और कौन सी ख़ामियां हैं, जिनके आधार पर इन्हें ख़ारिज़ कर सकती है.

मोदी का सकारात्मक पक्ष

गुजरात में तीन बार सत्ता-सुख भोग चुके नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को यह विश्वास है कि वे जनप्रिय नेता हैं और यही कमाल वे राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं. तमाम विसंगतियों के बावजूद मोदी ने गुजरात में विकास किया है, जिसके दम पर उन्हें उद्योगपतियों का ज़बरदस्त समर्थन हासिल है. उद्योगपतियों द्वारा बार-बार मोदी की तारीफ़ भी की जाती रही है, जो कि शायद मोदी और भाजपा के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी. अपने को प्रोजेक्ट कैसे करना है और राजनीतिक विरोधियों पर हमला कैसे करना है, नरेंद्र मोदी यह बख़ूबी जानते हैं. अपने भाषणों के दौरान मोदी सभा में मौजूद जनता से संवाद करते हैं, जिसका क्या असर होता है, यह शायद उन्हें मालूम है. वे जनता की नब्ज़ पकड़ना जानते हैं, इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, बिजली और पानी के साथ स्थानीय मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को घेरते हैं और उसके बरक्स अपने को बेहतर पेश करते हैं.

मोदी विरोधी दलों के ख़िलाफ़ बेहद आक्रामक रवैया अपनाते हैं. उन्हें शायद यह मालूम है कि एक जवान होता देश अब न सिर्फ़ वाकई जोशीला, क्षमतावान और आक्रामक दिखना चाहता है, बल्कि विश्व बिरादरी में अपनी ताक़तवर पहचान बनाना चाहता है. वह दस साल के लुंजपुंज नेतृत्व से उबरना चाहता है. मोदी वाकपटु नेता हैं. वे अपने भाषणों से लोगों को आकर्षित करते हैं. बोलने की जैसा अंदाज़ उनके पास है, वैसा आज के बहुत कम नेताओं में है. वे देश में मौजूद अलग-अलग तबके की नब्ज़ पकड़ने और उन्हें रिझाने की कला में माहिर हैं. कांग्रेस ने उन्हें चाय वाला बताकर उनकी खिल्ली उड़ाई तो मोदी ने इसे भी भुनाने का प्रयास कर डाला. अब अपनी रैलियों में चायवालों को भी बटोर रहे हैं. गुजरात दंगे मोदी पर एक बदनुमा दाग की तरह हैं लेकिन उसके बाद राज्य में कोई भी दंगा-फ़साद नहीं होना भी एक पक्ष है, जिसे मोदी अपनी प्रशासनिक कुशलता के तौर पर पेश करते हैं. बड़ी संख्या में गुजरात के मुसलमान भी अब यह कहने लगे हैं कि उनके साथ सरकार कोई भेदभाव नहीं करती. उद्योगपतियों द्वारा मोदी के विकास मॉडल की तारीफ़ उनके पक्ष में जाती है, इसकी मदद से वे अपनी छवि विकास पुरुष के रूप में बना रहे हैं.

मोदी ने गुजरात में सड़क और बिजली को लेकर काम किया है और अब सवाल उठा रहे हैं कि कब तक देश बिजली-पानी के मुद्दों में उलझा रहेगा? यह बात जनता को अपील कर सकती है, क्योंकि नेता बिजली-पानी को सनातन मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं. देश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं. मोदी ने उनकी महत्ता को देखते हुए उन्हें लुभाने के लिए वे तमाम कोशिशें कर रहे हैं. मोदी सोशल मीडिया पर मौजूद युवाओं में जमकर प्रचार कर अपनी छवि-निर्मित करने का अभियान चलाए हुए हैं.

मोदी का नकारात्मक पक्ष

मोदी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है गुजरात दंगे का दाग़, जिसके चलते उनकी छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की है. इस वजह से देश के मुसलमान और धर्मनिरपेक्ष सोच के लोग न केवल उन्हें नापसंद करते हैं, बल्कि मोदी के नाम पर असुरक्षित महसूस करते हैं. गुजरात में वीभत्स दंगों को क्रिया की प्रतिक्रिया कहने और दंगों के बाद भी उनके पद बने रहने जैसी बातों ने मुसलमानों में असुरक्षा पैदा की है. जानकार लोगों का मानना है कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर देश के सांप्रदायिकता के रास्ते पर बढ़ने का ख़तरा है.

मोदी पर तानाशाही करने जैसे आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में संजय जोशी से हुए विवाद में मोदी की ज़िद के चलते जोशी को पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया गया. पार्टी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाना भी उनकी तानाशाही का ही नमूना है. मोदी को लेकर यह सवाल उठते रहते हैं कि क्या उनका प्रधानमंत्री बनना तानशाही को निमंत्रण देने जैसा है? मोदी का बेशक गुजरात में बहुत प्रभाव है, लेकिन गुजरात भाजपा में मोदी के अलावा दूसरा नेता उनके बराबर नहीं खड़ा हो सका. इसलिए यह डर स्वाभाविक है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी वे यही करेंगे?

जिस गुजरात मॉडल की मोदी चर्चा करते हैं, उसपर कई गंभीर सवाल हैं. हाल ही में मोदी के विकास मॉडल की हवा निकालते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट जारी की कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. इसी तरह गुजरात की विकास दर भी पिछली कांग्रेस सरकारों से काफी नीचे है, जो मोदी के दावों को झुठलाती है. मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद से ही भाजपा में अंतर्कलह चल रही है. उनके नाम पर पार्टी का एकजुट नहीं हो पाना भी मोदी के केंद्रीय सत्ता में पहुंचने में एक बाधा है.

मोदी अपने भाषणों में अक्सर या तो गलत तथ्य पेश करते हैं, या हक़ीक़त से परे बहुत बढ़-चढ़ कर बोलते हैं. इसीलिए उनके लिए मीडिया, खासकर सोशल मीडिया में फेंकू जैसा विशेषण इस्तेमाल किया जाता है. मोदी देश में सर्वाधिक शासन करने वाली पार्टी और परिवार पर लगातार हमले करते हैं, लेकिन अभी तक देश के विकास खाका स्पष्ट रूप से वे भी पेश नहीं कर सके हैं, इसलिए उनके दावे विश्वसनीय नहीं हैं. मोदी की कट्टर छवि और तानाशाह रवैये के कारण भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल मोदी से किनारा करते दिखते हैं. मोदी की उदार और समावेशी छवि न होना भी उनके लिए नुकसानदेह है. 17 साल तक भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन करने वाले नीतीश कुमार ने मोदी के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनते ही भाजपा से किनारा कर लिया. हालांकि, यह नीतीश का दोहरापन ही है, लेकिन मोदी को छवि का संकट ज़रूर है. ■

राहुल का सकारात्मक पक्ष

राहुल गांधी उस राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसका भारतीय राजनीति और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर दबदबा है. इसीलिए पार्टी में कई योग्य और अनुभवी नेता होने के बावजूद वे कांग्रेस के निर्विरोध सर्वेसर्वा हैं. पार्टी में कोई विरोधी न होने से सत्ता तक पहुंचने के लिए राहुल को केवल विरोधी दलों की ही चुनौती है. राहुल गांधी अपेक्षाकृत युवा नेता हैं. भारत की कुल आबादी में 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत के क़रीब है. 21 करोड़ मतदाता 32 साल के कम उम्र के हैं, जिनमें से 12 करोड़ पहली बार मतदान करने जा रहे हैं. शांत स्वभाव और सौम्य छवि के राहुल गांधी इन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं.

कांग्रेस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता से लेकर आलाकमान तक राहुल पर सवाल न उठाकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर आंख मूंदकर भरोसा करता है और उनके साथ खड़े होने का दावा करता है. पार्टी में उनके नाम पर एक राय उनका मज़बूत पक्ष है. वे हर फैसला लेने में सक्षम है क्योंकि उन्हें उनकी मां के सिवा कोई रोकने वाला नहीं है. राजनीति को समझने के सिलसिले में राहुल ने लगभग देश भर में यात्राएं की हैं और दलितों के घर ठहरते रहे हैं. इससे निचले तबके के लोगों को राहुल गांधी अपने से जोड़ सकते हैं. देश के सबसे पुराने या कहें पहले राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उन्हें राजनीतिक संस्कृति से लेकर अनुभव तक विरासत में मिले हैं.

राहुल पार्टी में युवाओं को मौक़ा देने की बात करते हैं और उन्होंने कई युवा चेहरों को जगह भी दी है. कई युवा चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हैं. वे 2014 में युवाओं की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं. इसके चलते भी राहुल को युवाओं का साथ मिल सकता है. राहुल गांधी कोई करिश्मा कर पाने में अब तक भले कामयाब न हो सके हों, लेकिन वे काफ़ी मेहनती हैं और पार्टी या अपनी ख़ुद की कमज़ोरियों को सरेआम अक्सर स्वीकार कर लेते हैं. हाल में ही अरविंद केजरीवाल की सफलता से उन्होंने सीख लेने की बात कही. यह भी कहा कि अब तक 500 लोग सरकार चलाते हैं. सरकार में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए. राहुल गांधी पार्टी और सरकार के फ़ैसलों पर अक्सर सवाल खड़ा करते हैं. वे कई फ़ैसलों का विरोध करते हैं और सुधारों की वकालत करते हैं. इसके चलते बाकी पार्टी नेताओं की तुलना में उनकी अलग छवि बनती है. हाल में कई सरकारी निर्णयों को नाटकीय ढंग से पेश करके राहुल की छवि को भ्रष्टाचार विरोधी बनाकर पेश किया गया, चाहे वह लोकपाल बिल का मुद्दा हो, या फिर दागी जनप्रतिनिधियों को रोकने वाले बिल का मुद्दा हो. जबकि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलते तो हैं, लेकिन उनके खाते में ऐसी कोई उपलब्धि दर्ज नहीं है.

राहुल का नकारात्मक पक्ष

केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार के खाते में तमाम असफलताएं दर्ज हुई हैं. चूंकि, दस सालों से कांग्रेस राज में हर अच्छे काम का श्रेय राहुल गांधी को मिलता है, इसलिए असफलताओं का श्रेय अपने आप उनके ही खाते में ही दर्ज होगा. पिछले दस साल के कांग्रेस शासन के दौरान वे सक्रिय राजनीति में रहे. वे पार्टी उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार भी. लेकिन वे कोई सरकार की निष्क्रियता में कोई सकारात्मक हस्तक्षेप कर पाने में असफल रहे. संप्रग सरकार के दौर में अभूतपूर्व घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि समस्याएं सामने आईं, लेकिन राहुल सिर्फ़ यह कहते रहे कि हम परिवर्तन चाहते हैं. वह परिवर्तन कैसा होगा, इसकी कोई रूपरेखा वे पेश नहीं कर सके. अपने भाषणों में वे जन समस्याओं पर बात करने की जगह अपने पारिवारिक संघर्षों की कथा कहते हैं. उन्हें यह अंदाज़ा नहीं है कि जनता शासक वर्ग से कोई सहानुभूति नहीं रखती, बल्कि चिढ़ती है.

परिवारवाद भारतीय राजनीति की एक विद्रूप सच्चाई है, लेकिन गांधी-नेहरू परिवार का केंद्रीय राजनीति पर कब्ज़ा भारतीय राजनीति की एक दयनीय स्थिति पेश करता है. अब तमाम लोग, जिसमें युवा वर्ग भी है, परिवारवाद से निजात चाहते हैं. परिवार ब्रांड की आड़ में जनता दीन-हीन नेतृत्व को स्वीकारने के मूड में शायद नहीं है. यदि राहुल गांधी अपनी बेहतर नेतृत्व क्षमता को साबित करते तो शायद जनता उनके साथ खड़ी होती, लेकिन उन्होंने लगातार यह साबित किया कि वे राजनीति के शीर्ष चेहरों में इसलिए हैं, क्योंकि शीर्ष राजनीतिक परिवार से हैं.

जनतंत्र में जनता मुद्दों और नीतियों के साथ होती है, राहुल गांधी ने अब तक चंद आदर्शवादी बातों के सिवा कुछ भी जनता के सामने नहीं रखा है. बदलाव का स्पष्ट खाका दिए बिना वे शायद ही जनता को बदलाव की राजनीति के नाम पर आकर्षित कर पाएं. जनता को ख़ुद से जोड़ने का हुनर राहुल गांधी अब तक नहीं सीख पाए. वे अपने सलाहकारों के चलते राजनीतिक दांव-पेंच में ही फंसे रहे. शायद इसीलिए उन्हें अब कहना पड़ रहा है कि वे अरविंद केजरीवाल से सीखेंगे. यह उनके लिए हास्यास्पद स्थिति है.

राहुल गांधी राजनीति में व्यक्ति पूजा बंद कर लोकतंत्र लाने की बात कहते हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द भी अंधभक्तों का जमावड़ा भर है. पार्टी की चाटुकार संस्कृति कभी-कभी इतने भद्दे ढंग से सामने आती है कि आम लोगों को उससे चिढ़ होती है. राहुल गांधी में दस सालों की सक्रियता के बाद भी नेतृत्वकारी वाकपटुता नहीं आ सकी, जो जनता को प्रभावित करे. राहुल के भाषण में परिपक्वता नहीं होती. बोलते हुए वे ममाज ब्वॉय नज़र आते हैं. वे बाहें बटोरकर एंग्री यंगमैन दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लहज़ा उन पर थोपा हुआ प्रतीत होता है. उनका चेहरा घबराया हुआ सा दिखता है, हावभाव में एक हड़बड़ी दिखती है. सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा मीडिया तक में उनके लिए पप्पू विशेषण का इस्तेमाल भी उनकी अपरिपक्व छवि का द्योतक है. राहुल गांधी आज तक राज्य या केंद्र में कोई पद लेकर अपनी योग्यता साबित नहीं कर सके. इससे जनता में यह संदेश जाता है कि राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय जरूर हैं, लेकिन उनमें प्रशासनिक क्षमता और आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है. ■

उत्तर प्रदेश भाजपा में संघ की चल रही है. इसने सूबे की सभी लोकसभा सीटों का ब्यौरा तैयार किया है, जिसके आधार पर टिकटों का वितरण होना है. यूपी भाजपा को इस बार खुली छूट नहीं हैं. मोदी लहर को देखते हुए जनता के हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएंगे. प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कौन कितना सक्रिय, सशक्त और बेहतर चुनावी तंत्र रखता है. संघ ने सारा विवरण इकट्ठा करवा लिया है, ताकि जिताऊ प्रत्याशियों के चयन में असुविधा न हो.

संघ ने संभाली उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश में भाजपा की विजय पताका फहराने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ आगे आ गया है. अब बिना संघ की मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. भाजपाई समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में वह ग़लती कर चुके हैं, जिसे संघ उन्हें दोहराने नहीं देना चाहता है. संघ की कसौटी पर प्रत्याशी तराशे जा रहे हैं. काफ़ी जांच, परख और खरा उतरने के बाद ही उन्हें चुनाव मैदान में भेजा जाएगा. इसी के मद्देनज़र नये साल में संघ प्रदेश भाजपा की बिखरी गोटियों को एक एक कर सहेज रहा है. संघ को मालूम है कि चार राज्यों में जीत के चलते उत्तर प्रदेश के भाजपाई, आत्ममुग्ध और गदगद ज़रूर हैं, लेकिन उनके ज़रिये दिल्ली नज़दीक हो गई हो, यह सोचना अभी दिवास्वप्न जैसा ही होगा. हालांकि, प्रदेश भाजपा संघ के मुताबिक़ ही अमल करती दिख रही है. इसीलिए भाजपा इस बार राम पर नहीं, बल्कि रामभक्तों पर यक़ीन कर रही है. यही वजह रही है कि उसने विहिप की चौरासी कोसी परिक्रमा, मुज़फ़्फ़रनगर दंगा और सरकार की तुष्टीकरण नीति जैसे मुद्दों पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. वहीं अब भाजपा ने रणनीति के अनुसार 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' निर्माण कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अयोध्या, मथुरा चित्रकूट समेत कई ज़िलों से साधु संतों का मार्च निकाला. साथ ही झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे 14 स्थानों पर महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला. इसके अलावा प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों मेयर व अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने ज़िला मुख्यालयों पर आयोजित दौड़ में हिस्सा लिया. राजनीतिक हलकों में चर्चा है भाजपा की यह दौड़ सपा, बसपा और रालोद प्रभाव वाले क्षेत्रों में कुछ फ़ीकी रही है.

लोकसभा की तैयारी में मुस्तैदी से लगे पार्टी कार्यकर्ता कमल को खिलाने के लिए घर-घर दौड़ लगाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं. पार्टी का महिला मोर्चा कमल मेंहदी अभियान चलाकर महिला आबादी से सीधे संपर्क साधने की जुगाड़ में है. महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर महिलाओं की दोनों हथेलियों तथा अंगुलियों पर कमल का निशान बनाएंगी, साथ ही राज्य व केन्द्र सरकार के कुशासन वह भ्रष्टाचार को उजागर करेंगी. वह कथा सुंदरकांड, धार्मिक कार्य तथा गीत गायन आदि आयोजित कर योजना को साकार करेंगी. भाजपा ने सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए गांवों से लोहा संग्रहण की शुरुआत की तारीख़ एक जनवरी रखी है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के 900 स्थानों पर एक साथ करने की बात कही गई. लौह संग्रह सहयोग समिति संयोजक ओमप्रकाश सिंह के अनुसार, सभी आठ क्षेत्रों में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और संग्रह समिति संयोजक उपस्थित रहेंगे. भाजपा

जिलाध्यक्ष व समिति के जिला संयोजक संयुक्त आयोजन करेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कहना है कि सपा सरकार से जनता नाख़ुश है, इसलिए उसे आठ सीटें बसपा के कुशासन को जनता देख चुकी है, लिहाज़ा इसे नौ सीटो ंपर ही संतोष करना होगा. लोकदल का सफ़ाया हो जाएगा. यह अतिशयोक्ति नहीं. क्योंकि 1998 लोकसभा चुनाव में 85 सीटों में 60 पर भाजपा जीत चुकी है. उत्तर प्रदेश भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है. अमित शाह प्रदेश प्रभारी हैं और उन्हें सांगठनिक दक्षता हासिल है. यूपी में जातिवाद की काट राष्ट्रवाद से होगी. हम सभी को साथ लेकर चलेंगे. इस बार ख़ास बात यह है कि बूथ स्तर पर संगठन खड़ा है. भाजपा नेताओं का तर्क है कि जिस तरह प्रदेश की जनता ने सपा को बड़ा जनाधार देकर युवा मुख्यमंत्री का चयन किया था. वह मुख्यमंत्री आज जनता का विश्वास व जनाधार खंडित कर रहा हैं. नौजवानों को लैपटाप देकर बहलाया जा रहा है, जबकि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गारक की ज़रूरत हैं. भाजपाई मंचों से घोषणा कर रहे हैं कि प्रदेश व देश में उनकी सरकार बनी तो युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता व लैपटाप देने की की जगह प्रदेश के हर बेरोज़गार को दस लाख रुपये का बगैर ब्याज ऋण देकर उनके हाथों में रोज़गार देने का काम किया जाएगा.

मिशन मोदी को परवान चढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मैदान में उतर पड़ा है. सबसे पहले इसने संघ परिवार के सभी घटक दलों, विशेष तौर से भाजपा और दूसरे संगठनों को एक दूसरे के साथ बैठाकर शिकायतें दूर करने का काम हाथ में लिया है. संघ ने नतीजों के विश्लेषण के बाद रणनीति के तहत पश्चिमी, बृज और बरेली के प्रमुख पदाधिकारियों की गाजियाबाद में बैठकों के सहारे ख़ामियों को दुरुस्त करने की रणनीति बनाई है. संघ का मानना है कि कि भाजपा में जिस तरह दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, इसके चलते मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो सकती है. पहले भी ऐसा हुआ है, जब दूसरे दल के लोग आए, टिकट लिया और भाजपा के बुरे दौर के साथ ही खिसक लिए. यह भी बात सामने आई कि बाहर से आने वाले टिकट पाने के बाद अपना पूरा तंत्र खड़ा कर लेते हैं. जिले में संगठन के मूल लोगों की अनदेखी करते हैं, दागियों को टिकट से संघ परिवार के दूसरे संगठनों के काम करने में परेशानी की बात भी कही गई. इस बाबत भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह का कहना है कि इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. आने वालों को टिकट का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है. कसौटियों पर खरे उतरने वालों को ही टिकट दिए जाएंगे. भाजपा के रणनीतिकारों का विचार है कि चुनाव को देखते हुए इस बार पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा कि भूल से भी ऐसा कोई काम न होने पाए, जिससे मुसलमानों के ध्रुवीकरण की संभावना होती हो. तर्क दिया जा रहा है कि मुसलमानों में भाजपा को लेकर पहले की तुलना में भरोसा बढ़ रहा है. प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान और अन्य लोग भाजपा को भी आज़माने का मन बना रहे हैं. भाजपा चुनाव में इन लोगों का भरोसा जीत पाई तो मुसलमान विरोधी बताकर वोट बटोरने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दलों के हौंसले पस्त हो जाएंगे. बहरहाल भाजपा ख़ुश है कि कम से कम अल्पसंख्यक भी भाजपा में आने शुरू हो गए हैं. हाल ही प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं एवं पुरुषों ने सदस्यता ग्रहण की थी.

मेरठ में अखिलेश सरकार के लोकनिर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव के इस कथन पर कि मोदी का जादू प्रदेश में नहीं चलेगा, इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने करारा जवाब दिया कि सपा की मज़बूती और तीसरे मोर्चे के प्रभावशाली होने का दिवास्वप्न देखना अच्छी बात है, पर जिस उत्तर प्रदेश के भरोसे यह दिवास्वप्न देखा जा रहा है, सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही हैं. सपाई हस्तक्षेप से क़ानून व्यवस्था से लेकर जनहित से जुड़ी विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. जनसुनवाई का आलम यह है कि तहसीलों व थानों पर अधिकारी मिल ही नहीं रहे हैं. सपा और इसके समर्थक दल के नेताओं में होड़ मची है कि कौन मोदी के विरुद्ध कितनी बयानबाज़ी कर ले रहा है. तभी तो कभी नरेश अग्रवाल टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो जयराम रमेश मोदी की तुलना आसाराम से करते हैं. यही नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा ने तो हिटलर तक कह डाला है. भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार की असफलता का बोझ सपा पर ही भारी पड़ रहा है. परिणाम-स्वरूप मुख्यमंत्री की फोटो होर्डिंगों से हटा दी गई है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज मिश्र कहते हैं कि सपा ने ही अपने मुख्यमंत्री को रिजेक्ट कर दिया है तो प्रदेश की जनता क्यों बर्दाश्त करे? जब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक ने ही कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो ख़राब स्थितियां पैदा नहीं होतीं या फिर दुरुस्त कर देता.

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश भाजपा में संघ की चल रही है. उसने सूबे की सभी लोकसभा सीटों का ब्यौरा तैयार किया है, जिसके आधार पर टिकटों का वितरण होना है. यूपी भाजपा को इस बार खुली छूट नहीं हैं. मोदी लहर को देखते हुए जनता के हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएंगे. प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कौन कितना सक्रिय, सशक्त और बेहतर चुनावी तंत्र रखता है. संघ ने सारा विवरण इकट्ठा करवा लिया है, ताकि जिताऊ प्रत्याशियों के चयन में असुविधा न हो. संघ की कसौटी पर कसकर ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में भेजे जाएंगे. संघ यूपी की जीत के लिए कटिबद्ध है, वह भली-भांति इस बात को समझ रहा है कि भाजपा अभी नहीं तो कभी नहीं. फ़िलहाल मोदी के अश्वमेघ के घोड़े की रक्षा में संघ खड़ा है. इतना ज़रूर है कि मोदी की लहर और संघ की कसौटी के माध्यम से यदि भाजपाइयों ने काम किया तो प्रदेश में भाजपा एक बार फिर अपना परचम लहरा सकती है. इसे इस मुग़ालते में भी नहीं रहना चाहिए सपा, बसपा और कांग्रेस कमज़ोर हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जनांदोलन निगल जाएंगे नीतीश की सरकार

शशि सागर

बिहार की राजधानी का पटना जंक्शन पूरी राजधानी को दो हिस्सों में बांटता है. एक पटना शहर का इलाक़ा और दूसरा राजेंद्रनगर, करबिगहिया और इसके सटे इलाक़े को. इन दोनों इलाक़ों को जोड़ता है राजधानी का आर ब्लॉक चौराहा. लेकिन पिछले दिनों जितने दिन विधानसभा का सत्र चला, चौराहा का द्वार बंद रहा. पूरी राजधानी इतने दिनों कराहती रही. छह से तेरह दिसंबर तक ऐसा लगा कि मानो राजधानी के शहरी इलाक़े से शेष पटना कटा रहा. अराजक और अव्यवस्थित माहौल लगातार बना रहा. वजह यह थी कि जब तक विधानसभा का सत्र चला, बिहार के अलग-अलग हिस्सों से आए संगठन आंदोलन पर डटे रहे. ये अलग बात है कि बिहार के रहनुमाओं पर इन आंदोलनों का कोई असर नहीं हुआ. सरकार पर ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि ये आंदोलनों को लाठी-डंडे से कुचलना जानती है और इसके लिए जनआंदोलनों का कोई ख़ास महत्व नहीं है.

बहरहाल, आर ब्लॉक पर आंदोलन कर रहे दस-बारह संगठनों से राजधानी में जो अव्यवस्था का माहौल पैदा हुआ, वह अलग से बहस का विषय है. लेकिन लगातार एक हफ़्ते तक आंदोलन पर डटे रहे लोगों को देखकर इतना तो अवश्य लग रहा था कि आने वाले दिन सत्तापक्ष के लिए आसान नहीं हैं. कुछ ऐसे संगठन आंदोलन कर रहे थे जो नीतीश की सरकार के आने से पहले अपनी मांगों को लकर संघर्षरत हैं. वहीं आधिकांश संगठन ऐसे मिले जो ख़ुद नीतीश के ग़लत निर्णयों की वजह से उठ खड़े हुए हैं. नियोजित शिक्षक, बाल दीदी और आशा बहू जैसे संगठन अगर आज आंदोलन को बाध्य हैं तो इसके लिए सरकार ख़ुद ज़िम्मेदार है. बिहार के अलग-अलग ज़िलों में अन्य मसलों को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं. कई बार पटना में भी कई संगठनों ने अलग-अलग समय पर धरना-प्रदर्शन भी किया. लेकिन लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि कई संगठन एकसाथ राजधानी में जमे हुए थे और जमकर नीतीश को कोस भी रहे थे. अन्य ज़िलों से आए आंदोलनकारियों से तो राजधानी और सरकार परेशान थी ही, इसकी परेशानी को और बढ़ा दिया मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने. मामला यह था कि कन्वेन्शन सेंटर के नाम पर मगध महिला के मुख्य द्वार को बंद किया जा रहा है. कॉलेज प्रशासन और वहां की छात्राओं का कहना है कि कन्वेन्शन सेंटर के बजाय यह ज़मीन कॉलेज को दे दी जाए और कॉलेज का विस्तार किया जाए, साथ ही हमारे मुख्य द्वार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए. इसे लेकर विश्वविद्यालय की छात्राएं प्रदर्शन कर रही थीं, जिनपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. मामले को लेकर आइसा सहित कई संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया. अब बात सामने आ रही है कि कॉलेज के गेट से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन कन्वेन्शन सेंटर वहीं बनेगा. आइसा की दिव्या गौतम कहती हैं कि यह अकेला मामला नहीं है, जब सरकार ने आंदोलन को कुचला है. यह सरकार तो लाठी-गोली की

ही सरकार है. यह सरकार सामंतपरस्त है और मांगों को सुनने की बजाय दमन की नीति से काम लेती है.

ऐसे ही कई आंदोलन बिहार के अन्य ज़िलों में भी चल रहे हैं. इन आंदोनलनकारियों की भी शिकायत यही है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. प्रशासन दमन की नीति से काम लेता है. सूबे के अधिकांश ज़िले में भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं. इनमें बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुज़फ़्फ़रपुर आदि प्रमुख ज़िले हैं. खगड़िया में ऐसे ही आरोप सरकार पर लगे कि किसानों से उनकी उपजाऊ ज़मीन कौड़ियों के भाव में ख़रीद लिया गया. कहा जाता है कि बिहार सरकार की एक मंत्री प्रिस्टाइन कंपनी के माध्यम से इन ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रही हैं. इसी तरह भागलपुर के कहलगांव में भी पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री लगाने को लेकर किसानों की 1028 एकड़ उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया. जिसका किसान विरोध कर रहे हैं. वे ज़मीन की उचित क़ीमत और परियोजना में नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं. लेकिन ज़िला प्रशासन दमनात्मक रुख़ अपनाता है. ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड का है. वहां भी किसानों का आरोप है कि उनकी क़ीमती ज़मीन को कम क़ीमत पर अधिगृहीत किया गया. ऐसे ही आरोप बिहटा, बाल्मीकि नगर आदि जगहों के किसानों ने भी लगाया. इसी क्रम में महादलितों को तीन डेसीमल जमीन देने, शहरी-ग़रीब को घर देने, फारबिसगंज गोलीकांड के पीड़ितों को न्याय देने और कोसी के विस्थापितों का पुनर्वास करने को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं. धीरे-धीरे ये आंदोलन बड़ा रुख़ अख़्तियार करते दिखाई दे रहे हैं. विडंबना यह है कि सरकार इसे तवज्जो ही नहीं देती. यह नीतीश के लिए घातक साबित होगा.

बाबरी विध्वंस और 1991 के उदारीकरण के विरोध में *देश बचाओ, देश बनाओ* के नाम से देश के कुछ प्रमुख समाजसेवियों ने यात्रा शुरू की. इसके बाद 1994 में एनएपीएम का गठन हुआ. इसका उद्देश्य था कि पूरे देश के छोटे-छोटे आंदोलनों को एक मंच पर लाना. इसमें मेधा पाटेकर, डॉ. बनवारीलाल शर्मा, किशन पटनायक, बीडी शर्मा आदि प्रमुख नाम हैं. ऐसी ही पहल बिहार में भी की गई. इस सिलसिले में मेधा का कई बार पटना भी आना हुआ. बिहार में चल रहे आंदोलनों से मेधा ने मुलाकात भी की और इन मसलों पर नीतीश से मिलने की कोशिश भी की. लेकिन नीतीश ने आजतक सरोकारी मसले पर मेधा से मुलाक़ात नहीं की और न ही उनके एक भी पत्र का जवाब दिया. एनएपीएम के नेशनल कन्वेनर महेंद्र यादव कहते हैं कि जनांदोलनों को लेकर नीतीश का रवैया नकारात्मक है. लोकशक्ति अभियान के बाद मेधा उनसे मुलाक़ात करना चाहती थीं, लेकिन वे नहीं मिले. नीतीश सिर्फ़ तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, उनके पास जनता के सवालों को सुनने की फ़ुर्सत नहीं है. विधानसभा छह दिन चली और अधिकांश हंगामे की भेंट चढ़ गई. जनता के सवालों पर कोई बहस ही नहीं हुई. जो आंदोलनकारी पटना में डटे हुए थे, उनके मसलों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया. शिक्षा, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से जुड़े कई संगठन पूरे छह दिन पटना में डटे रहे. बिहार राज्य अराजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ आज भी आमरण अनशन पर है. संघ का कहना है कि जब विधानसभा चली तो हमारी बातों और समस्याओं का ज़िक्र तक नहीं किया गया. महासंघ आरोप लगाती है कि राज्य के 390 अराजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के पांच सूत्री मांगों के प्रति सरकार ने अब तक कोई ठोस क़दम नहीं उठाया है. 1980 से 390 अराजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है. जब झारखंड अलग राज्य बना था तो इसी में से 32 विद्यालय झारखंड राज्य में चले गए थे. वहां की सरकार सभी कर्मियों का वेतन आदि भुगतान कर चुकी है, लेकिन बिहार के कर्मी अब तक ठगे ही जा रहे हैं. इसी तरह वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का भी लगातार आंदोलन चला. पिछले दिनों यह संगठन भी पटना में अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था. 1996 से ही यह संगठन अपने हक के लिए लड़ता आ रहा है. लेकिन आजतक इसे सफलता नहीं मिली है. एनडीए-1 की सरकार बनने से पहले नीतीश भाषणों में कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी वित्तरहित को वित्तपोषित कर देंगे. नीतीश के इसी आश्वासन पर बिहार के लगभग साठ हजार वित्तरहित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने उन्हें अपना एकमुश्त वोट दिया था. लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. एनडीए वन में ही पहली बार इन स्कूलों को छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने की बात कही गई. इस समय भी इसका विरोध किया गया था. 2008 में अनुदान देने की घोषणा की गई और दो साल तक दिया भी गया. लेकिन पिछले कई सालों से ये अनुदान को भी तरस गए हैं. बिहार में ऐसे वित्तरहित हाई स्कूल 715, इंटर कॉलेज 507 और डिग्री कॉलेज 240 हैं. अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां के कर्मियों को कई सालों से वेतन नहीं दिया जा रहा हो, जिन्हें अनुदान के भरोसे ज़िंदा रहना पड़ रहा हो, वैसे शिक्षक कैसा अध्यापन करवा रहे होंगे. संगठन के महासचिव जयनरायण सिंह मधु कहते हैं कि हम वित्तरहितों ने भरोसा करके उन्हें जितवाया था, आज हमीं से ये वादाख़िलाफ़ी कर रहे हैं. सरकार को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना होगा. कुछ इसी तरह बिहार के अलग-अलग ज़िलों से आए लोक शिक्षक भी बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ के बैनर तले लगातार धरना पर डटे रहे. ये लोक शिक्षक 2006 से ही धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अबतक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है. पटना हाईकोर्ट के दो साल पहले दिए गए आदेश के बावजूद भी इन लोक शिक्षकों का समायोजन शिक्षा मित्र के तर्ज पर पंचायत शिक्षक के रूप में नहीं किया जा रहा है. लगातार अविवेकपूर्ण निर्णयों की वजह से ही कहीं लोक शिक्षक, कहीं वित्तरहित शिक्षक, कहीं नियोजित शिक्षक तो कहीं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आए दिन हड़ताल पर अड़े रहते हैं.

पिछले महीने ही बिहार के सैप जवान हड़ताल पर चले गए थे. सरकार के निर्णयों और अफशरशाही से इन जवानों को परेशानी हो रही थी. यह मामला भी अभी तक निपटा नहीं है, कुद मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है. पिछले साल पंद्रह सूत्री मांगों को लेकर बिहार पुलिस भी धरना कर ही चुकी है. लेकिन पिछले हफ़्ते बिहार के गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य कई दिनों तक धरने पर रहे. पुलिस अधिकारी से विधायक बने सोमप्रकाश कहते हैं कि यह पहला राज्य है, जहां समान काम के लिए अलग-अलग वेतन भत्ता दिया जाता है. पुलिस के लिए अलग व्यवस्था है और गृह रक्षकों के लिए अलग. अगर सरकार समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो सारे गृहरक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे और ठप विधि-व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेवार होगी. इन आंदोलनों के बीच में पश्चिम चंपारण में एक और आंदोलन चल रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में लौरिया विधानसभा के लोगों ने सभी प्रत्याशियों से एक फार्म भरवाया. इस फार्म में चार मुद्दे लिखे हुए थे और कहा गया था कि अगर हम विधायक बनेंगे तो दो साल के भीतर हम दो मांगों को पूरा करेंगे, नहीं कर सके तो इसे हमारा इस्तीफ़ा समझा जाएगा. अब वहां से गीतकार विनय बिहारी निर्दलीय विधायक हैं. तीन साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने दो में से एक भी मांग पूरी नहीं की है. अब उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जनता आने नहीं दे रही और इस्तीफा मांग रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपीए शासन की पहली सरकार में लोकपाल को मजबूत बनाने का वादा किया गया था. साल 2005 में वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल को स्थापित करने पर विशेष जोर दिया. साल 2011 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की जिसमें लोकपाल बिल भी शामिल था.

चौथी दुनिया की खबर का असर

समाचार एजेंसी यूएनआई के तीन कर्मचारियों को जेल

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समाचार एजेंसी यूएनआई के दो वरिष्ठ पत्रकारों समेत तीन लोगों की ज़मानत याचिका ख़ारिज़ कर उन्हें जेल भेज दिया. इन लोगों पर दलित सहकर्मी को प्रताड़ित करने के आरोप हैं. एजेंसी में विभिन्न मामलों को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रवक्ता संजय कनौजिया के मुताबिक़, इन आरोपियों के विरुद्ध करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है. अब इनके विरुद्ध मुक़दमा चल रहा है. आशा है कि सरकार यूएनआई के संकट पर विशेष ध्यान देगी और कई भाषाओं में समाचार सेवाएं प्रदान करती आ रही है इस एजेंसी को स्वार्थी तत्वों के चंगुल से आज़ाद कराकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करेगी.

ए.यू. आसिफ

बीते 12 दिसंबर 2013 को पटियाला हाउस न्यायालय द्वारा समाचार एजेंसी यूएनआई के एक दलित कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में ज्वाइंट एडीटर नीरज बाजपेयी, डिप्टी चीफ़ ऑफ ब्यूरो यूनिवार्ता अशोक उपाध्याय और क्लर्क मोहन लाल जोशी की ज़मानत याचिका ख़ारिज़ करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस मामले में निष्पक्षता से खबरें छापने और सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए 'चौथी दुनिया' (उर्दू-हिंदी) की सराहना की जा रही है. यूएनआई में कुछ वरिष्ठकर्मियों पर वित्तीय अनियमितता के भी आरोप हैं. कोर्ट द्वारा इन कर्मचारियों को जेल भेजे जाने के बाद फ़ैसले के बाद अब यह आशा की जा रही है कि न्यायालय के इस निर्णय से यूएनआई जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसी को कुछ स्वार्थी तत्वों से निजात दिलाने और आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. साथ ही इस समाचार एजेंसी को बंद करने के षडयंत्र को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकेगा और वास्तविक विवाद में आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को सज़ा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा.

उपरोक्त निर्णय पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल ज़िला व सेशन जज दिया प्रकाश द्वारा तीन बिंदुओं के मद्देनज़र लिया, जिनमें मुक़दमा एससी एंड एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़) एक्ट की धारा तीन से संबंधित है, जो एक सोशल लेजिसलेशन है और इसका उद्देश्य एससी और एसटी समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्यवाही करना है. दूसरी शिकायत जांच के दौरान शिकायतकर्ता के द्वारा दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता के साथ दो गवाहों के बयान लिए गए हैं. चालान के अनुसार आरोपों की व्याख्या की गई है. तीसरा बिंदु यह है कि आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप बेहद गंभीर हैं. यूएनआई की पीड़ित दलित महिला कर्मचारी के वकील के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएन गिरि और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद कुमार चौधरी ने आरोपियों की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि आरोपियों का जुर्म काफ़ी गंभीर है. लिहाज़ा उन्हें तत्काल ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

इस मामले में आरोपी अशोक उपाध्याय पर यूएनआई की एक वरिष्ठपत्रकार के मानसिक उत्पीड़न और शोषण का आरोप है और इस मामले की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जा रही है.

ज्ञात रहे कि इस मामले में तथाकथित कर्मचारी लीडर मुकेश कौशिक भी आरोपी हैं. यूएनआई बचाव आंदोलन के प्रवक्ता संजय कनौजिया ने 'चौथी दुनिया' को बताया कि इन आरोपियों के विरुद्ध करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं मामलों को लेकर 25 फ़रवरी 2013 को नई दिल्ली में यूएनआई मुख्यालय और एनआईएस पर पत्रकारों, कवियों, साहित्यकारों, ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक पार्टियों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्रदर्शन किया था और फिर 6 अगस्त 2013 को भी जंतर-मंतर पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया था. कनौजिया का कहना है कि यूएनआई के पूरे मामले को उजागर करने में 'चौथी दुनिया' की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. हमने 29 जुलाई से 4 अगस्त 2013 के अंक में 'यूएनआई के आर्थिक संकट का अंजाम क्या होगा?' और 16 से 22 सितंबर 2013 के अंक में ख़ुलासा करती रिपोर्टें प्रकाशित की थीं. इसके बाद यह मामला सामने आया था कि किस तरह यूएनआई पर क़ब्ज़ा करने या इसे ख़त्म करने के षडयंत्र चल रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है कि तीन आरोपी, जिनकी ज़मानत की याचिका ख़ारिज हुई है और जिनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चल रहा है, उनका संबंध यूएनआई से है जो भारी आर्थिक संकट का शिकार है.

यूएनआई के लिए दुर्भाग्य यह रहा है कि यह समय-समय पर किसी न किसी स्वार्थी व्यक्ति के शोषण का शिकार रही है. वर्तमान में विश्वास त्रिपाठी इस पर क़ाबिज़ हैं, जबकि अतीत में प्रफुल्ल महेश्वरी का इस पर प्रभुत्व था और इससे पूर्व ज़ी न्यूज़ की मीडिया वॉच के सुभाष चंद्रा को धांधली कर यूएनआई का स्वामित्व अधिकार दे दिया गया था, जिसे आनंद बाज़ार पत्रिका समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. ज्ञात रहे कि आनंद बाज़ार समूह के पास यूएनआई के सबसे अधिक शेयर हैं. इसके बाद सुभाष चंद्रा ने स्वयं को इससे अलग कर लिया था और कहा था कि अब मेरा यूएनआई से कोई लेना देना नहीं है. उस समय सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा था कि 32 करोड़ रुपये, जिनमें से जो कुछ ख़र्च हो गया है, वह पूरे का पूरा नहीं वापस किया जाए. दरअसल, आनंद बाज़ार समूह के चेयरमैन डीडी पुरकायस्थ और उदय भट्टाचार्य ने यूएनआई के सभी कर्मचारियों के वेतन व अन्य सुविधाओं आदि को नियमित कर दिया, जिससे यह संदेश मिला कि अब यूएनआई की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन यह सरासर धोखा था.

अब यूएनआई के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध मुक़दमा चल रहा है और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. आशा है कि सरकार यूएनआई के संकट पर विशेष ध्यान देगी और दशकों से कई भाषाओं में समाचार सेवाएं प्रदान करती आ रही है इस एजेंसी को स्वार्थी तत्वों के चंगुल से आज़ाद कराकर निष्पक्ष एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्रता से प्रयास करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकपाल का राजनीतिक सफर

इस बिल में कई संवैधानिक संस्थाओं को लोकपाल के दायरे में लाए जाने को लेकर हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रही. कई बार लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया गया और बाहर कर दिया गया. राजनीतिक दलों में इस बात पर आम सहमति नहीं पाई. बिल पास होते समय भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी और दोनों ही सदन में बिल का बॉयकाट कर दिया. समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का मानना है कि इस बिल के पास होने से समाज में अराजकता की अवस्था आ जाएगी.

अरुण तिवारी

संसद में लोकपाल बिल पास हो तो गया, लेकिन इसे पास होने में 44 वर्षों से अधिक का समय लग गया. इसे पास कराने का श्रेय निश्चित रूप से समाजसेवी अन्ना हजारे को जाता है, जिन्होंने इसकी लड़ाई को निर्णायक बनाया. करीब पांच दशक में यह बिल कई बार संसद के सदनों में पेश किए जाने के बाद भी मज़बूत राजनीतिक दृढ़ता की अनुपस्थिति के कारण लटका ही रहा. कभी राज्यसभा से नहीं पास हो पाया तो कभी लोकसभा से. 2011 में अन्ना हजारे द्वारा शुरू किए गए जनलोकपाल आंदोलन के बाद ही यह संभव हो पाया.

लोकपाल नामकी संस्था बनाने की शुरुआत साल 1969 में तब हुई, जब इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में पेश किया था, लेकिन उस समय यह राज्यसभा में पास नहीं हो पाया. इसके बाद साल 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011 में भी संसद में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो सका. इस बिल में कई संवैधानिक संस्थाओं को लोकपाल के दायरे में लाए जाने को लेकर हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रही. कई बार लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया गया और बाहर कर दिया गया. राजनीतिक दलों में इस बात पर आम सहमति नहीं पाई. बिल पास होते समय भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी और दोनों ही सदन में बिल का बॉयकाट कर दिया. समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का मानना है कि इस बिल के पास होने से राजनीति और प्रशासन के स्तर पर अराजकता की स्थिति आ जाएगी. जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है और कोई भी दूसरी संस्था उसकी जांच नहीं कर सकती है.

इसकी शुरुआत उस समय हुई जब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय में स्कैंडिविनियाई देशों जैसे नार्वे और स्वीडन में गठित की गई लोकपाल संस्था की तर्ज पर भारत में भी ऐसी ही संस्था बनाने की वकालत सांसद लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने की थी. सिंघवी वर्तमान में प्रभावशाली कांग्रेसी नेता अभिषेक मनुसिंघवी के पिता थे. भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने और इसकी परिधि में प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लोकपाल के गठन का प्रस्ताव 1964 और 1965 में सदन में लाया गया. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के काल में नौ मई 1968 को इसे पहली बार सदन में पेश किया गया. लोकसभा में यह बिल पास भी हो गया था, लेकिन बाद में सदन भंग होने की वजह से बिल समाप्त हो गया. उस बिल में प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया था. इसके वर्ष 1971 में फिर से इसे संसद में पेश किया गया. इस बार प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया था.

प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई के काल में 28 जुलाई 1977 को पेश लोकपाल बिल में आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के आधार पर भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया. प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने का कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया गया. बाद में यह भी बिल भी समाप्त हो गया.

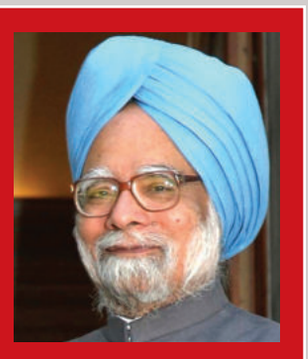

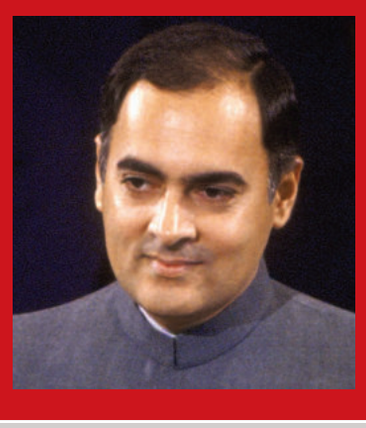

यूपीए शासन की पहली सरकार में लोकपाल को मज़बूत बनाने का वादा किया गया था. साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल को स्थापित करने पर विशेष ज़ोर दिया. साल 2011 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की जिसमें लोकपाल बिल भी शामिल था.

स्व. राजीव गांधी के शासनकाल में 26 अगस्त 1985 को इस बिल को एकबार फिर लोकसभा में पेश किया गया. इसमें भी भ्रष्टाचार की परिभाषा आईपीसी और पीओसीए के आधार पर तय की गई. इसमें दुराचरण और कुशासन को नहीं शामिल किया गया. प्रधानमंत्री को इस बार भी इसके दायरे से बाहर नहीं किया गया. बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया.

29 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों और वर्तमान प्रधानमंत्री को दायरे में रखते हुए बिल को पेश किया गया. यह बिल भी वापस ले लिया गया. बाद में प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (1996) और अटल बिहारी वाजपेई (1998 और 2001) के शासनकाल में भी यह बिल अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त हो सका. इन बिलों में प्रधानमंत्री को तो शामिल किया गया था, लेनिक नौकरशाहों को इससे बाहर रखा गया था.

साल 2002 में लोकपाल की ज़रूरत को महसूस करते हुए पूर्व न्यायाधीश वेंकटचेलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने लोकपाल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. यूपीए शासन की पहली सरकार में लोकपाल को मज़बूत बनाने का वादा किया गया था. साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल को स्थापित करने पर विशेष ज़ोर दिया. साल 2011 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की, जिसमें लोकपाल बिल भी शामिल था.

ये तो रही सरकारी प्रयासों की बात. लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन ने सबसे ज्यादा दबाव सरकार पर बनाया. अन्ना हजारे के आमरण अनशनों ने सरकार की चूलें हिलाकर रख दीं. साल 2011 में किए गए अन्ना के अनशन के बाद ही ऐसा लगने लगा कि चार दशकों से लटका हुआ लोकपाल बिल पास हो सकेगा. बात सिर्फ़ लोकपाल बिल के पास हो जाने तक ही सीमित नहीं थी. भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए देश को मज़बूत लोकपाल की ज़रूरत थी, जिसे अन्ना के नेतृत्व में देश ने प्राप्त किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

> असम, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विवरण से सामने आता है कि अगर दंगा पीड़ित अपने पैतृक स्थानों से विस्थापित होने के बाद भयमुक्त होकर वापस लौटने का साहस नहीं कर पाते हैं तो प्रशासन, सरकार और विभिन्न संगठनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाएं और उनके पुनर्वास का प्रयास करें.

दंगा पीड़ितों के पुर्नवास का संकट

आज़ादी के बाद से अब तक भारत में दंगों का लंबा इतिहास रहा है. पीड़ित अपने पैतृक निवासों से विस्थापित होते रहे हैं और कई बार वापस भी लौटते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में असम, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भय के कारण अगर दंगा पीड़ित वापस जाने का साहस नहीं कर पाते हैं, तो क्या सरकार या प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और पीड़ितों को दूसरे स्थानों पर बसाते रहें? *प्रस्तुत है एक रिपोर्ट.*

ए.यू. आसिफ़

इन दिनों एक सवाल हर किसी के दिमाग़ में घूम रहा है कि क्या हम अपने देश के नागरिकों को इतनी भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं कि वे अपने पैतृक निवासों पर स्थायी रूप से रह सकें? जो लोग हिंसक घटनाओं या दंगों के समय अपना घर-बार छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, उन्हें हम वापस लौटा सकें? पहले असम, गुजरात और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाओं के दौरान अपने पैतृक निवासों से उजाड़े गए लोगों के संदर्भ में यह सवाल चिंता का कारण बनता है. हिंसक घटनाओं के दौरान जब माहौल ख़राब हो जाता है तो अस्थायी रूप से प्रवास आम बात है, क्योंकि उस समय किसी भी जगह हिंसक समूह के डर से अल्पसंख्यक समूह ऐसा करने पर विवश हो जाता है, लेकिन यह प्रवासन अस्थायी होता है. जैसे ही सरकार, प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से स्थिति सामान्य होती है, उजड़े हुए लोग फिर से अपने पैतृक स्थानों पर वापस लौट जाते हैं, लेकिन इसके उलट, हिंसा की कुछ घटनाओं में सांप्रदायिक माहौल इतना अधिक ख़राब हो जाता है कि उस समय यह लगने लगता है कि दोनों पक्षों के लोगों के बीच की खाई शायद अब कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी. कुछ ऐसे ही हालात 1990, 2000 और 2010 के दशक में असम में बोडो और गैर-बोडो विवाद, 2002 में गुजरात और 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों के दौरान देखने को मिले. पिछले तीन दशकों में असम में बोडोलैंड के नागरिक पांच बार उजड़े और उन्हें अपने पैतृक निवासों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेना पड़ी. स्थिति इतनी दयनीय है कि 1993, 94, 98 और 2008 के गैर-बोडो पीड़ितों की संख्या आज भी बोडोलैंड ट्रिब्यूनल एरिया डिस्ट्रिक्टस (बीटीएटी) क्षेत्रों से बाहर विभिन्न राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में ज़िंदगी गुज़ार रही है, जिनमें 1993-94 में उजड़े हुए 25 हज़ार लोग बोंगाई गांव ज़िलों के राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को कोई चिंता नहीं है कि उन्हें उनके पैतृक निवासों पर वापस लौटाने का कोई प्रयास भी किया जाए. यहां तक कि 2013 में विस्थापित 4.5 लाख लोगों का मामला उपरोक्त लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनमें से अधिकतर अपने पैतृक निवासों पर पिछले एक वर्ष के अंदर वापस लौट चुके हैं और इसका श्रेय गैर सरकारी संगठन जमाते-इस्लामी हिंद और स्वयं बोडोलैंड ट्रिब्यूनल काउंसिल (बीटीसी) के अध्यक्ष हगरामा मोहीलारी के साथ-साथ उनके प्रशासन को जाता है.

जमात के सचिव मौलाना मोहम्मद शफ़ी मदनी ने चौथी दुनिया को बताया कि 2012 में उजड़े हुए लगभग 100 प्रतिशत लोग अपने अपने पैतृक स्थानों पर वापस लौट चुके हैं. वहां उनको नये मकान बनाकर और पुराने खंडहर मकानों की मरम्मत करा कर देने में जितनी भूमिका जमात की है, उतनी ही हगरामा मोहीलारी की भी है, जिन्होंने बिना मतभेद राहत कार्यों की सराहना की. उन्होंने जमात के प्रतिनिधिमंडल से 16 जनवरी, 2013 को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के मुख्य कार्यालय कोकराझार में विशेष मुलाक़ात के दौरान अपने सहयोग का आश्वासन दिया और विस्थापित लोगों को अपने पैतृक स्थानों पर वापसी के समय सुरक्षा के बंदोबस्त किए. यहां तक कि विस्थापित स्थानों पर इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनवा कर दिए. मौलाना शफ़ी मदनी के अनुसार आज इन्हीं प्रयासों से बीटीएडी के बाहर पिछले वर्ष बने सभी शिविर ख़त्म हो चुके हैं और कुछ ही शिविर मौजूद हैं. प्रयास तो ये भी किए जा रहे हैं कि इनमें रह रहे लोगों को भी जल्द उनकी पैतृक संपत्ति तक पहुंचा दिया जाए. इसके साथ-साथ बोडो और गैर-बोडो लोगों के भ्रम को दूर करने और प्रेमभावना को उभारने की कोशिश भी की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए.

उन्होंने बताया कि 2012 से पूर्व 1993, 94, 98 और 2008 के मामले पुराने हैं. लिहाज़ा उनसे अलग बातचीत और योजना बनाने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में हगरामा प्रशासन से बात की जा रही है. फोन पर कोकराझार से बोडोलैंड के काउंसिल सदस्य अफज़ल हक़ सरकार ने इसकी पुष्टि की और कहा कि पिछले वर्ष बीटीएडी के बाहर आकर 277 कैंपों में रहने को विवश चार लाख 46 हज़ार 108 प्रवासियों में से 199 शिविरों में तीन लाख 15 हज़ार 874 गैर-बोडो मुस्लिम, 76 कैंपों में एक लाख 29 हज़ार 712 बोडो हिंदू और ईसाई और दो कैंपों में 522 गैर-बोडो हिंदू व ईसाई थे. उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद देश के इस सबसे बड़े विस्थापन के पीड़ित, जमाते-इस्लामी और अन्य संगठनों की कोशिशों व बीटीसी अध्यक्ष हगरामा मोहीलारी के साथ-साथ बीटीसी के सदस्यों के सहयोग से अपने-अपने पैतृक गांवों में पहुंच चुके हैं और नये और मरम्मत किए गए मकानों में रह रहे हैं.

बीटीसी के एमसीएलए अफज़ल हक़ सरकार ने कहा कि अजीब बात है कि जमीअत-उलेमा हिंद ने बीटीएडी के बाहर जमीअत के नाम ज़मीन ख़रीद कर उन पर मकान बनाए हैं और पीड़ितों में से कुछ लोगों को नये मकान सौंपे गए हैं. जांच करने पर पता चला कि जिन गैर-बोडो मुस्लिम पीड़ितों को मौलाना महमूद मदनी की कोशिशों और जमीअत-उलेमा हिंद की ओर से जो मकान दिए गए हैं, इनमें अधिक संख्या उन लोगों की है जो बीटीएडी के पैतृक बाशिंदे नहीं थे, बल्कि वहां केवल रह रहे थे और जब पिछले वर्ष बोडो और गैर-बोडो विवाद हुआ, तो एक ओर वहां के मूल गैर-बोडो बाशिंदे उजड़े तो वहीं ये लोग भी अपने किराये के मकानों से उजड़ कर बेघर हो गए.

आवश्यकता इस बात की है कि जिन उजड़े हुए लोगों को बीटीएडी के अंदर उनके पैतृक निवास पर बसाया गया है, उनके बच्चों के लिए पिछले एक वर्ष से ठप्प पड़ी शिक्षा-व्यवस्था को पुन: आरंभ किया जाए. इसके लिए जमात की ओर से 78 बच्चों को हॉस्टल के साथ स्कूलों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिलाया गया है, यहां तक कि उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए 70 मदरसे शुरू किए गए हैं. फ़िलहाल बीटीएडी के अंदर 100 से अधिक मदरसे विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा कुछ छात्रों को गोद भी लिया गया है.

इसी प्रकार फरवरी 2002 में गुजरात दंगों के दौरान भी हज़ारों लोगों ने अपने पैतृक निवास छोड़ने पर मजबूर हुए थे और यह सिलसिला एक साल तक चलता रहा था. पीड़ितों ने राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में शरण ली. यहां भी राहत पहुंचाने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिका अलग-अलग रही. जमीअत उलेमा हिंद ने अहमदाबाद व कुछ स्थानों पर ज़मीन ख़रीदकर विभिन्न कॉलोनियों का निर्माण कराया और इन पीड़ितों में सैंकड़ों लोगों को मकान दिए. ये लोग आज भी वहां रह रहे हैं, लेकिन शरणार्थियों की तरह, क्योंकि यहां इनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है और वे इस पूरे क्षेत्र में लगभग ग्यारह वर्षों के गुज़रने के बावजूद अजनबी की तरह रहे हैं. कुछ लोगों के बारे में तो यह भी ख़बर है कि वह मजबूर होकर अपने हिस्से के मकानों को किराये पर लगाकर किसी और जगह स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि उनके समक्ष वे लोग जिन्हें जमात व अन्य समूहों ने पैतृक स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें वहां बसाने की कोशिश की, वह अब पहले की तरह अपने पैतृक स्थानों पर फिर से रहने लगे हैं और संतुष्ट भी हैं.

जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर-शामली के दंगों का मामला है, तो वहां जागर टूटती है. दंगे शुरू होते ही विभिन्न गांवों से लगभग एक लाख मुसलमानों ने आस-पास के शहरों और गांवों में प्रवास कर शिविरों और अन्य स्थानों पर शरण ली. ये लोग जिन तनावपूर्ण हालात में अपने पैतृक निवासों से निकले थे, उसे बयान नहीं किया जा सकता. पैतृक निवासों से प्रवास करने वाले लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने मां-बाप और अन्य संबंधियों को जलकर मरते हुए देखा, वे भय के कारण वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे. दूसरी ओर जिन लोगों ने उन्हें उजाड़ा था और घर छोड़ने पर विवश किया था, वे भी उन्हें वापस न आने की धमकी दे रहे थे.

दरअसल, इन हालात में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी दोनों की जमीअत उलेमा हिंद व अन्य समूहों ने विभिन्न स्थानों पर ज़मीन ख़रीद कर इन उजड़े हुए लोगों के लिए मकान बनवाने शुरू किए. बीते 18 नवंबर को 72 परिवारों के 860 लोगों को ख़ामपुर में जमीअत कॉलोनी के तहत 80 गज़ ज़मीन पर 72 मकान अन्य लोगों के हवाले करने की योजना है.

इसी प्रकार मौलाना महमूद मदनी ने भी बताया कि उजड़े हुए लोगों के लिए 250 मकान बनाए जा रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप के द्वारा पीड़ितों को मकानों के रूप उपलब्ध कराए गए इन राहत शिविरों से उनके पैतृक स्थानों से हमेशा के लिए उजड़ने का रास्ता तो नहीं निकलेगा, तो उनका कहना था कि सच तो यह है कि यह पहले ही उजड़ चुके हैं और यह ऐसे लोग हैं, जिनके दिल व दिमाग़ पर बहुत अधिक भय बैठा है. लिहाज़ा, वह वापस जाना नहीं चाहते हैं. हमारी पहली कोशिश यह होती है कि वह अपने पैतृक स्थान पर ही जाएं. इसके लिए गांवों के गैर-मुस्लिम लोगों से बातचीत करके माहौल को सामान्य बनाया जाता है. यहां कई ऐसे गांव भी हैं, जहां के गैर-मुस्लिम लोगों से बात की गई तो उन्हें अहसास हुआ और फिर वे लिखित रूप से अपनी जिम्मेदारी पर इन पीड़ितों को वापस गांव लेकर गए. अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो इसको दूर किया जाता है और अब भी यह कोशिश निरंतर जारी है कि माहौल को सामान्य बनाया जाए और लोग अपने पैतृक स्थानों को लौट जाएं. लेकिन इन पीड़ितों में कुछ ऐसे भी हैं, जो किसी भी स्थिति में वापस जाना नहीं चाहते हैं, तो इनके लिए हम निवास का बंदोबस्त करके उन्हें बसाने की व्यवस्था कर रहे हैं.

इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सांप्रदायिक तनाव का अंत और भाईचारा कायम करने के लिए जमीअत उलेमा हिंद व दारुल उलूम देवबंद दोनों को बातचीत के लिए बुलाया. लेकिन इन दोनों की ओर से चुप्पी साध ली गई. जब मौलाना मदनी से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि टिकैत पीड़ितों को उजाड़ने के आरोपी हैं, इसलिए हम इनसे कैसे बात कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि जमीअत और दारुल उलूम देवबंद की ओर चुप्पी रही, जबकि जमाते इस्लामी हिंद के सचिव मौलाना शफ़ी मदनी नरेश टिकैत से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले. मुज़फ़्फ़रनगर में उनके गांव सिसौली में और फिर बातचीत की. मौलाना मदनी ने बताया कि मैं नरेश टिकैत जी से मिला और विस्थापित मुसलमानों के पुनर्वास के मुद्दे पर बात की. उन्होंने विस्थापित मुसलमानों के पुनर्वास के लिए सहायता और हर प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन दिया है. टिकैत ने उनसे कहा कि 200 मुस्लिम परिवार उनके सिसौली गांव में वापस आ चुके हैं और अगर शांति स्थापना में मदद मिल सकती है तो वह माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं. मौलाना शफ़ी मदनी का कहना है कि विश्वास बहाल करने के इन प्रयासों से जाट नेता स्वयं ही आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के जिन पीड़ितों का अपने पैतृक स्थानों पर वापस लौटना असंभव होने लगा था, अब संभव होता जा रहा है.

अब लगता है कि मुज़फ़्फ़रनगर और शामली ज़िलों से विस्थापित लोगों के लिए उनकी पैतृक संपत्ति पर वापसी की शुरूआत हो चुकी है और अगर विश्वास बहाली का यह सिलसिला जारी रहा, तो फिर से शांति व सांप्रदायिक सौहार्द पैदा होगा और विस्थापित लोग अपने-अपने पैतृक निवासों पर वापस लौट सकेंगे. इसी बीच राहत शिविरों में स्वयं राज्य गृह सचिव कमल सक्सेना के अनुसार 49 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि मौतों की गैर-सरकारी संख्या इससे कहीं अधिक है. 12 दिसंबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और इसे पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल निर्देश दिए. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बच्चों को विशेषत: चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाए. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 13 दिसंबर को मेरठ डिवीज़न के कमिश्नर मंजीत सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समीति का गठन किया गया.

> **मुज़फ़्फ़रनगर और शामली ज़िलों से विस्थापित लोगों के लिए उनकी पैतृक संपत्ति पर वापसी की शुरुआत हो चुकी है और अगर विश्वास बहाली का यह सिलसिला जारी रहा, तो फिर से शांति व सांप्रदायिक सौहार्द पैदा होगा और विस्थापित लोग अपने-अपने पैतृक निवासों पर वापस लौट सकेंगे. इसी बीच राहत शिविरों में स्वयं राज्य गृह सचिव कमल सक्सेना के अनुसार 49 बच्चों की मौत हो चुकी है.**

जहां तक उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की बात है, तो राहत कार्यों को लेकर इसकी प्रक्रिया अजीबो-ग़रीब है. इसने बीते 26 अक्टूबर को विस्थापित हुए 200 गांवों में केवल नौ गांवों के महज़ 1800 मुस्लिम पीड़ित परिवारों को डर के कारण अपनी पैतृक संपत्ति पर वापस नहीं लौटने के शपथपत्र के बाद पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी, जिसका मतलब यह था कि पांच लाख रुपये लेने पर एक व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति पर वापस लौटने के अधिकार से वंचित हो जाएगा. इस पर पीड़ितों में चिंता पैदा हो गई. इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर को राज्य सरकार से कहा कि पुनर्वास के लिए दी जा रही रक़म पांच लाख रुपये केवल विस्थापित हुए मुस्लिम परिवारों के लिए आबंटित न होकर विस्थापित हुए परिवारों के लिए हो जाए. इसके अलावा राज्य सरकार का कहना कि अगर एक परिवार भविष्य में अपनी पैतृक संपत्ति पर लौटने का निर्णय करता है तो उसे उपरोक्त राशि वापस करनी होगी और ऐसा न करने पर सरकार 'लैंड रेवेन्यु' के तौर पर राशि को वापस लेने के लिए स्वतंत्रत होगी.

असम, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विवरण से सामने आता है कि अगर दंगा पीड़ित अपने पैतृक स्थानों से विस्थापित होने के बाद भयमुक्त होकर वापस लौटने का साहस नहीं कर पाते हैं तो प्रशासन, सरकार और विभिन्न संगठनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाएं और उनके पुनर्वास का प्रयास करें.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

देश की जनता बुद्धिमत्ता-पूर्वक वोट दे, जिसके परिणाम से ही बेहतर सरकार अस्तित्व में आएगी. आख़िरकार देश दूसरे किसी भी मसले से ऊपर है. पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से हम चुनावी प्रक्रिया देख रहे हैं. इस प्रक्रिया को सही ढंग से बनाए रखना होगा. मतदाता बड़ी संख्या में अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यह एक शुभ संकेत है. इस दिशा में चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें, यह देश के भविष्य के लिए बेहतर है.

हम अपने अतीत को याद रखें और संजोए

वर्ष 2013 बीत गया और अब हम 2014 के शुरुआती दौर में हैं. अगर पीछे देखें, तो बीता वर्ष अलग-अलग मिजाज़ की घटनाओं का समुच्चय रहा. अर्थव्यवस्था संकट से जूझती दिखी. हालांकि, यह मुश्किल केवल देश में ही नहीं, वैश्विक परिदृश्य पर भी थी. यूरोप अभी भी बड़े आर्थिक संकट में है. अमेरिका धीरे-धीरे वापसी की कोशिश कर रहा है. भारत भी अपने यहां विकास की कोशिशों में लगा है और इस पक्ष को लेकर आशान्वित भी है, उत्साहित भी. लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब भी हमें विकास का अवसर मिलता है, हम उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसके लिए प्रशासनिक निष्क्रियता या सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में होने वाली देरी ज़िम्मेदार है. चालू वित्तीय घाटा बहुत बढ़ गया है. रुपये और डॉलर की सममूल्यता अब नियंत्रण के बाहर हो गई है. निश्चित तौर पर यह स्थितियां घबराहट पैदा करने वाली थीं. फिर भी वित्तमंत्री ने हालात को संभालने की कोशिश ज़रूर की, यद्यपि कुछ देर से की. उन्होंने सोना और दूसरी ग़ैर-ज़रूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया. इस तरह के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में आई. मैं उन लोगों में से हूं, जिन्होंने 1991 में आर्थिक संकट के दौर से आज तक कभी भी आर्थिक हालात को लेकर अनावश्यक रूप से चिंता नहीं जताई. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम ऐसी मुश्किल में आतें हैं, उसके पीछे की पहली वजह उन हालात को लेकर हमारी लापरवाही और फ़ैसलों में होने वाली देरी ही रहती है.

2014 एक और महत्वपूर्ण स्थिति लेकर आएगा. वह है आम चुनाव. अगर आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में बात करें तो लोग इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव हों और नए प्रयास व नई नीतियां सामने आएं. हालांकि, इस पक्ष को लेकर बड़ी संभावनाएं नहीं जताई जा सकतीं, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है, वह ऐसी ही नीतियों के साथ आगे बढ़ती है. फिर भी अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि जो भी नई सरकार आएगी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नई नीतियां लेकर आएगी. इन नई राजनीतिक सामाजिक नीतियों को लेकर बहुत सारे आकलन हैं और बहुत सारे ख़तरे भी.

जो कारोबारी तबका है, वह इस बात को लेकर उत्साहित है कि भाजपा सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे. व्यापारी वैसे भी सामान्य तौर अपने हितों के बाहर जाकर नहीं सोचते. उन्हें लग रहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो व्यापारिक हितों से जुड़े फ़ैसले लिए जाएंगे और जिसके चलते समूचे देश में गुजरात मॉडल दोहराया जा सकता है. वास्तव में वे दूरदर्शी नहीं हैं. गुजरात एक ऐसा राज्य है, जहां नवउद्यमिता पहले से मौजूद थी. गुजरात कभी भी पिछड़ा राज्य नहीं था. गुजरात पहले से ही प्रगति कर रहा था, इसलिए अब वहां उसकी बेहतरी के लिए किसी ने कितनी कम या ज्यादा कोशिश की है इसका परीक्षण करना, इस पर पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है. जो बड़ा ख़तरा है, वह है सांप्रदायिकता. अगर समूचा देश हिंदू-मुस्लिम दंगों की गिरफ़्त में आ जाता है तो देश का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, व्यापार और अर्थव्यवस्था की तो बात ही छोड़िए. हमें इस स्थिति से बचने का सुरक्षा कवच तैयार करना होगा. सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को साथ आकर इस ख़तरे को दूर करना चाहिए. गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में सबके अपने-अपने अहम हैं. हर नेता को लगता है कि वही सही है. वह अपने राज्य में अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन जब तक यह पार्टियां वोटों का बिखराव नहीं रोक पाएंगी, इन ताक़तों को रोक पाने में अक्षम ही रहेंगी. इनके लिए यह संभव नहीं है कि वह बिना कांग्रेस को साथ लिए बीजेपी से मुक़ाबला कर पाएंगे. अगर कांग्रेस और गैर-भाजपा पार्टियां क्रमबद्ध तरीक़े से काम करें, तो वे सांप्रदायिक ताक़तों पर नियंत्रण पा सकती हैं या हिंदू संप्रदायवादियों को देश का शासन चलाने से रोक सकती हैं.

सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब भी हमें विकास का अवसर मिलता है, हम उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसके लिए प्रशासनिक निष्क्रियता या सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में होने वाली देरी ज़िम्मेदार है. चालू वित्तीय घाटा बहुत बढ़ गया है. रुपये और डॉलर की सममूल्यता अब नियंत्रण के बाहर हो गई है. निश्चित तौर पर यह स्थितियां घबराहट पैदा करने वाली थीं.

बावजूद इसके, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में उन्हें एक बड़े गठबंधन के बारे में सोचना होगा. वास्तव में ऐसी स्थिति देश के लिए बेहतर ही होगी. अगर एक बड़ा गठबंधन होता है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, तो उस भाजपा नीत एनडीए की सरकार और कांग्रेस सरकार में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा. 2002 के गुजरात दंगे के अलावा उस सरकार में कोई बड़े सांप्रदायिक टकराव नहीं हुए थे और गुजरात दंगा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों की ही छवि पर एक धब्बे की तरह है.

सबसे ज़रूरी बात है कि देश की जनता बुद्धिमत्तापूर्वक वोट दे, जिसके परिणाम से ही बेहतर सरकार अस्तित्व में आएगी. आख़िरकार देश दूसरे किसी भी मसले से ऊपर है. पिछले 60 वर्षों के अधिक समय से हम चुनावी प्रक्रिया देख रहे हैं. इस प्रक्रिया को सही ढंग से बनाए रखना होगा. मतदाता बड़ी संख्या में अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यह एक शुभ संकेत है. इस दिशा में चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें, यह देश के भविष्य के लिए बेहतर है. मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि औसत संख्या में भी मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान करें तो देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि देश की जनता के मन में सांप्रदायिकता जैसी कोई धारणा नहीं है. किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, फिर चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर किसी अन्य धर्म का, सामान्यत: लोग अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष होते हैं. ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता केवल भारतीय संविधान में ही उल्लिखित है, बल्कि यह देश में सदियों से व्याप्त है. हर धर्म और जाति के लोग इस देश में वर्षों से शांति और सदभाव के साथ रह रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कहकर मिथ्या फैला रहे हैं कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया विचार नहीं है. यह विचार हमें हमारे धर्मग्रंथों से मिला है. वेद-उपनिषद-गीता सभी हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं. यह हो सकता है कि यह ग्रंथ अपने धर्म की भाषा में संदेश देते हों, लेकिन अर्थ सबका एक ही है समानता, मानवता और ग़रीबों की सेवा. सब कुछ हमें यहीं से मिल जाएगा. कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने अतीत को याद रखें और उसी के अनुसार काम करें. यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है.■

feedback@chauthiduniya.com

ठाकुर दास बंग

संकट का स्त्रोत कहां है

कुछ भी हो, एक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है. अंग्रेजी राज में मुट्ठीभर अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे और आज 10 फीसदी लोग 90 फीसदी के सीने पर सवार हैं. अंग्रेजों की सरकार तलवार के बल पर बनी थी, हमारी सरकार हमारे वोट से बनी है और हमारे नोट से चलती है. पिछले पैंसठ वर्षों में हमारी राष्ट्रीय राज सत्ता का बेहद विस्तार हुआ है. जहां देखिए, सरकारी दफ्तर और सरकार के लोगों की भरमार है. एक औसत पंचायती क्षेत्र में, जिसमें मिडिल स्कूल हो, लगभग 39 सरकारी आदमी रहते हैं. कोने-कोने में फैला एक विशाल परिवार है सत्ता का, सत्ता के इर्द-गिर्द एक पूरा शासक वर्ग बन गया है, जिसके हाथ में सत्ता है, संपत्ति के साधन हैं और शासन के सूत्र हैं. दल कोई हो 65 वर्षों से यही वर्ग देश को चला रहा है.

बस यही हमारे संकटों का स्त्रोत है. एक शासक वर्ग द्वारा संचालित राज्य-सत्ता के हाथ में राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, आदि सभी शक्तियों का केंद्रित हो जाना ही. हमारा मुख्य संकट है. केंद्रीकरण के इस स्त्रोत से निकले प्रवाह ने, जिसकी धाराएं अनेक हैं. पूरे राष्ट्रीय जीवन को विष से भर दिया है. जिस दलीय चुनावी और काले धन पर चलने वाली राजनीति की नींव पर राज्य-सत्ता का महल खड़ा है, उसमें कोई नीति नहीं रह गई है. रह गया है केवल राज, जिसे चाहे जैसे अपने हाथ में कर लेने और एक बार कर लेने के बाद, बनाए रखने का सदाबहार संघर्ष चलता रहता है. यह संघर्ष भी सिमटते-सिमटते दल और इस गुट के बाद इस बिंदु पर पहुंच गया है कि एक परिवार विशेष की महात्वाकांक्षा राष्ट्र की आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाने लगी है.

मुक्तिः नई शक्ति और नई दिशा

प्रश्न है कि राष्ट्र के संकट की इस घड़ी में क्या करें? हमारा क्या कर्तव्य है? और मुक्ति की दिशा क्या है?

अब इस बात में संदेह नहीं रह गया है कि प्रचलित दलीय राजनीति के पास इस संकट का कोई उपाय नहीं है. यदि हो भी तो, मात्र सत्ता के परिवर्तन से राज्य-सत्ता अथवा समाज के बुनियादी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता. शराब वही रहती है, सिर्फ बोतलें बदल जाती हैं. इतना ही नहीं, क्या शासक दल और क्या विरोधी दल, दोनों की मूल निष्ठाएं समान हैं. वह मूलत: राज्य की ही सत्ता और शक्ति में विश्वास रखते हैं, यद्यपि अधिकारवादी और उदारवादी राजनीति के चरित्र में अंतर है. फिर भी राज्यवाद की मूल निष्ठा को कायम रखकर मुक्ति की युक्ति नहीं निकाली जा सकती. राज्यवाद और उस पर आधारित समाजवाद का अर्थ ही है केंद्रित सत्ता और केंद्रित संचालन. इसके अलावा देश की राजनीति में एक नई विघटनकारी प्रवृत्ति बढ़ती रही है-क्षेत्रीय दलों का बनना. इसलिए शक्ति की नई गंगोत्री की तलाश राजनीति की परिधि के बाहर ही करनी पड़ेगी. लोकतंत्र में शक्ति की गंगोत्री स्वयं जनता है. वही शक्ति का अक्षय स्त्रोत है. लोक-शक्ति ही रज्य-शक्ति के बढ़ते फौलादी पंजों को रोक सकती है और राष्ट्र के जीवन में नया मोड़ ला सकती है.

तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में हमारी पहली चिंता क्या होनी चाहिए? शांतिपूर्ण परिवर्तन की संभावना को बनाए रखना ही हमारी चिंता होनी चाहिए. इसलिए आवश्यक है कि संविधान में मिले हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें. ताकि विचार की शक्ति से हम लोक-चेतना को जगा सकें, संगठित और सक्रिय कर सकें.

राज्य सत्ता की तरह लोक-शक्ति का आधार शस्त्र की शक्ति नहीं है, जो शक्ति उसका आधार है. उसे गांधी जी ने आत्मा की शक्ति कहा है. आत्मा की यही शक्ति थी, जो सत्याग्रह के रूप में आजादी की लड़ाई में निहत्थी जनता के हाथों में अमोघ अस्त्र बनी. विनोबा जी के भूदान-ग्रामदान आंदोलन में हमने इस शक्ति का एक दूसरा आयाम देखा. हमने इसे लोकमानस को ऊंची सामाजिक प्रेरणाओं से अनुप्राणित करके देखा. अभी कुछ वर्ष हुए जे पी ने लोकात्मा को फिर ऊंचे धरातल पर पहुंचाया और उसकी शक्ति का प्रयोग लोकतंत्र पर होने वाले प्रहारों के प्रतिकार में किया. आगे वह उसे नया बिहार और नया भारत बनाने की क्रांति का साधन बनाते, लेकिन गांधी जी की तरह उनके लिए भी नियति ने कुछ दूसरा ही सोच रखा था.

हमारा राष्ट्र को आवाहन उसी लोकात्मा और लोक-शक्ति का आवाहन है, जिसके सफल प्रयोग हम देख चुके हैं और कुछ अभ्यास भी कर चुके हैं. उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है. जनता अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ले और संगठित होकर खड़ी हो जाय, तो मुक्ति को ढकने वाले काले बादलों को काटते कितनी देर लगेगी?

तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में हमारी पहली चिंता क्या होनी चाहिए? शांतिपूर्ण परिवर्तन की संभावना को बनाए रखना ही हमारी चिंता होनी चाहिए. इसलिए आवश्यक है कि संविधान में मिले हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें. ताकि विचार की शक्ति से हम लोक-चेतना को जगा सकें, संगठित और सक्रिय कर सकें. बोलने-लिखने संगठन बनाने और मत व्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकारों को खोकर जनता पंगु हो जाएगी. इसलिए इन अधिकारों पर होने वाले प्रहारों का आवश्यक प्रतिकार सहज ही हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है.

विघटन के बढ़ते वातावरण में परिस्थिति की तत्काल मांग है कि इस विविध और विशाल देश के करोड़ों-करोड़ नागरिक इस बात को समझें कि सह-अस्तित्व और सहकारी अस्तित्व में ही सबकी भलाई है और यही सदियों-सदियों से हमारी नियत रही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पहचाना था तथा अनेक भेदों के बावजूद साथ जीने और जीने देने की एक पद्धति विकसित की थी. अंग्रेजों के जमाने में तोड़ी गई और सत्ता की राजनीति अपने हित में उसे तोड़ती ही चली जा रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

राज्य सत्ता की तरह लोक-शक्ति का आधार शस्त्र की शक्ति नहीं है जो शक्ति उसका आधार है. उसे गांधी जी ने आत्मा की शक्ति कहा है. आत्मा की यही शक्ति थी, जो सत्याग्रह के रूप में आजादी की लड़ाई में निहत्थी जनता के हाथों में अमोघ अस्त्र बनी. विनोबा जी के भूदान-ग्रामदान आंदोलन में हमने इस शक्ति का एक दूसरा आयाम देखा. हमने इसे लोकमानस को ऊंची सामाजिक प्रेरणाओं से अनुप्राणित करके देखा. अभी कुछ वर्ष हुए जे पी ने लोकात्मा को फिर ऊंचे धरातल पर पहुंचाया और उसकी शक्ति का प्रयोग लोकतंत्र पर होने वाले प्रहारों के प्रतिकार में किया.

पाठकों की दुनिया

क्रिकेट की धरोहर हैं सचिन

युवाओं के प्रेरणास्त्रोत कीर्तिमानों का पर्याय, खिलाड़ियों के आदर्श, धैर्य की प्रतिमूर्ति, भारत का रत्न सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर ही नहीं, उच्च स्तर के व्यक्तित्व के धनी और राष्ट्रीय नायक है, साथ ही विश्व क्रिकेट की धरोहर भी हैं. आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान के साथ विश्व के बहुत सारे देशों ने भी उन्हें सम्मान दिया है. अपने सहज आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से करोड़ो-अरबों दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है. खेल के प्रति उनकी ईमानदारी और शालीनता हमारे भारतवर्ष के तमाम लोगों को यह एहसास कराती है कि अनुशासन ही इस देश को महान बनाता है. ईमानदारी वह वस्तु है, जिस पर हमारी प्रतिष्ठा निर्भर करती है. जीवन के 24 साल क्रिकेट को समर्पित करने वाले इस शख़्स का नाम भारत के इतिहास में हमेशा गौरवपूर्ण तरीके से शामिल रहेगा. मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन ने हर बड़ा रिकार्ड अपने नाम दर्ज कराया. 200 टेस्ट मैच खेल सचिन ने लंबे खेल जीवन में अपने खेल कौशल के साथ जिन मानवीय गुणों को प्रदर्शित किया. उसके कारण ही वह भारत रत्न के हकदार बने. वह यह सम्मान पाने वाले केवल पहले खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं. हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह यकीन करना बेहद कठिन होगा कि कोई एक खिलाड़ी अपने खेल के प्रति इतना अनुशासित और कामयाब होने के साथ ही इतना सहज और विनम्रता की प्रतिमूर्ति कैसे हो सकता है. नायाब काबलियत के इस शख़्स के नाम डाक टिकट भी जारी किया जाएगा. बहुत-बहुत बधाई सचिन.

अशोक निर्मोही, दरभंगा.

नेताओं को जनता जवाब देगी

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की शक्ति ही सर्वोपरि है. जनात ही किसी को सत्ता के शीर्ष पर बैठा सकती है या बाहर का रास्ता दिखा सकती है. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जो मुद्दे नजर आने चाहिए थे वे मुद्दे नजर नहीं आए. इसका कारण यह हो सकता है कि चुनाव आयोग के नियम अब सख्त हो गए हैं, जिसके कारण दागी नेताओं में कमी आई है. दूसरी वजह यह है कि जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बयानबाजी जारी है. कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व और मतदाता समझदार हो रहे हैं. इन दिनों खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर नेताओं और बुद्धजीवियों और पत्रकारों को बैठाकर जनता की मंशा पर चर्चा कराई जा रही है. जनता ने मतदान जरिए विधानसभा चुनावों में जवाब दे चुकी है. अभी लोकसभा चुनाव बाकी हैं, उसमें भी जनता जवाब देगी.

विकास कुमार पाटनी, झुमरी तलैया (झारखंड)

भेदभाव बंद होना चाहिए

संघलोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य करना क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के साथ अन्याय है. हिन्दुस्तान में अग्रेजी जानने वालों की संख्या एक चौथाई से भी कम है. संघलोक सेवा आयोग इतनी बड़ी संख्या की अनदेखी कैसे कर सकता है? आज तक सबसे अधिक आईएएस परीक्षा में भाषायी क्षेत्रों के छात्र ही अव्वल रहे हैं. यह संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय आम छात्रों से भेदभाव को दर्शाता है. मीडिया भी बड़ी-बड़ी बाते करता है कि वह आम लोगों के साथ है, लेकिन उसने भी इन छात्रों के साथ भेदभाव करते नजर आया. एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी जीत का जश्न के उद्घोष के साथ उसका श्रेय आम आदमी को दे रही थी और वहीं दूसरी तरफ कुछ पढ़े-लिखे युवा संघलोक सेवा आयोग के सामने अपने और आम युवाओं के अधिकारों की मांग कर रहे थे. मीडिया उस आम आदमी पार्टी के जीत को देश में उसकी राजनीति को करवट लेते हुए दिखा रहा था. मीडिया को इन आम युवाओं की कोई फिक्र नहीं है. मीडिया इसे चर्चा का विषय नहीं बना रहा है. हो सकता है कि शायद आप की जीत का इतना शोर था कि इन युवाओं की आवाज दूर तक न जा सकी. भेदभाव को मिटाना होगा नहीं, तो यह भेदभाव देश में एक तूफान ला सकता है. इसे समझना होगा.

विक्रांत, *भागलपुर*

कांग्रेस की चुनौती

अब कांग्रेस को लगने लगा है कि भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उसके लिए एक चुनौती हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्रकारों के जवाब में कहा कि हां, हम मोदी को गंभीरता से लेते हैं उनकी अन-देखी नहीं कर सकते. कांग्रेस आलाकमान अब समीक्षा करने के बाद मानने भी लगा है कि वह मोदी से पिछड़ गया है. मोदी अपने एजेंडे को लेकर मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित और गोलबंद करने में सफल रहे हैं, जबकि कांग्रेस यूपीए सरकार की उपलब्धियों और अपनी विचारधारा को जनता के पास ठीक से पहुंचा न सकी. अब कांग्रेस ने लोकपाल और धारा 377 पर खुलकर समर्थन किया है और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को दी गई. मीडिया में आई खबरों के अनुसार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी चल रही है. कांग्रेस अपने सालाना बैठक में 17 जनवरी को एलान भी कर सकती है. कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपने एजेंडे को जनता के बीच ले जाना और उसे अपने पाले में लाना.

उत्पल, मुजफ्फरपुर

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जनलोकपाल की लड़ाई आख़िर देश की जनता ने जीत ली. श्रेय अन्ना हजारे को दिया गया. देना स्वाभाविक है, क्योंकि अन्ना हजारे अगर अनशन नहीं करते तो यह बिल संसद में पास नहीं होता. न कांग्रेस की ख़्वाहिश थी और न भारतीय जनता पार्टी की ख़्वाहिश की थी कि यह बिल बने, क्योंकि बहुतों को भ्रम था कि वे अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए कहीं लोकपाल उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए. पर स्थितियां ऐसी बनीं कि सारे दलों को लोकपाल बिल पास करना पड़ा. समाजवादी पार्टी ने अपने विरोध को दर्शाया और तर्क दिया कि इस बिल के पास होने से यह भावना बढ़ेगी कि सारे राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचारी हैं या चोर हैं. समाजवादी पार्टी ग़लत नहीं सोच रही है.

लोकपाल के आगे की ज़िम्मेदारी जनता की है

दरअसल, राजनीतिज्ञों की छवि ही ऐसी बन गई है कि किसी को राजनीति में कोई ईमानदार दिखाई ही नहीं देता. कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन यहां तो तालाब को गंदा करने में मछलियों में होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा गंदा करता है. हो सकता है अब थोड़ी सावधानी बरती जाए कि लोकपाल नाम का एक संवैधानिक संगठन है, जिसमें अगर शिकायत जाएगी तो शिकायत पर गंभीरता से जांच होगी और जिनके ख़िलाफ़ शिकायत है, वे क़ानून के घेरे में आ जाएंगे.

लेकिन कैसा लोकपाल, कैसे पास हुआ, कौन इसके पीछे है, किसको श्रेय मिले आदि सवाल अब अपनी आख़िरी सीमा पर आ गए हैं. अब सवाल है कि लोकपाल के आगे क्या? क्या अन्ना लोकपाल के आगे कोई आंदोलन चलाएंगे. या जैसा कि अन्ना ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि वाच डॉग. जिसके तहत हर ज़िले में कमेटियां बनाकर ज़िम्मेदारी सौंपकर वे फिर देखेंगे कि वह कमेटियां कैसा काम कर रही हैं. संसद में भी कुछ लोगों ने कहा और देश में बहुत लोग यह कहते हैं कि लोकपाल संस्था में काम करने वाले क्या ईमानदार होंगे? इसके लिए अब वे लोग न्यायपालिका का उदाहरण देने लगे हैं और ख़ासकर ऊपर के स्तर की न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी आरोप लगने लगे हैं तो ईमानदार लोकपाल कहां से आएगा?

दरअसल, ईमानदारी तलाशना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि लोगों की नज़रें वहीं तक जा रही हैं, जहां तक भ्रष्टाचार जा रहा है. इस भ्रष्टाचार के दायरे के बाहर का इंसान लोगों को दिखाई ही नहीं देता. अच्छे लोग हैं नहीं. जो हैं वे अपमानित होते हैं. उन्हें कोई रुकने नहीं देता. उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लिहाज़ा ईमानदार सत्ता के दायरे से बाहर हो जाता है. इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अच्छे लोग मिल पाएंगे? क्या जिस तरह लोकपाल के पास लोगों के बारे में शिकायतें या उनके पास फ़ैसला आएगा तो क्या लोकपाल सही फ़ैसला देगा या लोकपाल भी मैनेज हो जाएगा? सवाल-सवाल-सवाल. लेकिन अब सवाल पूछने का समय नहीं है. जब संस्था बनेगी और संस्था काम करेगी, तब देखना पड़ेगा कि समस्याएं क्या आती हैं और जो समस्याएं आती हैं, उनका सामना लोकपाल नाम की संस्था किस तरह करती है? लोकपाल को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों को परेशान करने वाली या दुश्मनी निकालने वाली शिकायतें किस तरह पहचानी जाएं? इस तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल जलन में, झगड़े निपटाने में और दुश्मनियां निकालने में काफ़ी किया जाता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकपाल बिल पारित होने और क़ानून बनने के बाद इसकी जानकारी लोगों के पास कैसे जाएगी? मुझे याद है जब सूचना का अधिकार क़ानून बना था, बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते थे. लोगों को ये भी पता नहीं था कि सूचना के अधिकार क़ानून का फॉर्म कैसे भरा जाए और दफ़्तरों से कैसे जानकारी ली जाए. हमने तो इस पर एक सीरीज़ तक चलाई, लोगों को शिक्षित किया और आज भी लोग आरटीआई के इस्तेमाल करने के तरीक़े के बारे में चिट्ठियां लिखकर जानकारी चाहते हैं. आरटीआई क़ानून ने या सूचना के अधिकार क़ानून ने लोगों को बहुत ज़्यादा ताक़त दी है. क़ानून अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी है वो लोगों के हित में इस्तेमाल हो रहा है. ये अलग चीज़ है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. पर शायद ये हर लोकतांत्रिक सिस्टम में होता है कि कुछ लोग हर चीज़ का इस्तेमाल अपने निजी फ़ायदे के लिए करते हैं. इसी तरह लोकपाल के बारे में लोगों को शिक्षित करना एक बड़ा काम है. मुझे ये नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई मदद करेगी. मुझे यह भी नहीं लगता कि कोई बड़ी संस्था इसमें आर्थिक मदद करेगी. लेकिन कुछ लोगों को आगे आना ही होगा, जो लोकपाल के शिक्षण का काम करें. हिंदुस्तान के लोगों को समझाएं कि इस तरह का यह क़ानून है और इस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लोकपाल देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण क़ानून है. इस क़ानून का प्रचार करने, इस क़ानून के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा और ख़ासकर उनको, जिन्होंने लोकपाल और अन्ना को एक माना है. उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वे राजनीतिज्ञों पर नज़र रखने वाले इस क़ानून के प्रचारक हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना पड़ेगा. ये बहुत महत्वपूर्ण काम है. मुझे लगता है कि भारत के लोग लोकपाल क़ानून को जनता तक पहुंचाने में एक उत्साही आंदोलनकारी का रोल अवश्य निभाएंगे.■

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकपाल बिल पारित होने और क़ानून बनने के बाद इसकी जानकारी लोगों के पास कैसे जाएगी? मुझे याद है जब सूचना का अधिकार क़ानून बना था, बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते थे. लोगों को ये भी पता नहीं था कि सूचना के अधिकार क़ानून का फार्म कैसे भरा जाए और दफ़्तरों से कैसे जानकारी ली जाए. हमने तो इस पर एक सीरीज़ तक चलाई, लोगों को शिक्षित किया और आज भी लोग आरटीआई के इस्तेमाल करने के तरीक़े के बारे में चिट्ठियां लिखकर जानकारी चाहते हैं. आरटीआई क़ानून ने या सूचना के अधिकार क़ानून ने लोगों को बहुत ज़्यादा ताक़त दी है. क़ानून अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी है वो लोगों के हित में इस्तेमाल हो रहा है.

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कांग्रेस की हार का कारण कौन?

कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक दूसरी पार्टी का भी उदय हो गया है, जिससे गठजोड़ किया जा सकता है. आप पार्टी से सभी क्षेत्रीय पार्टियां सीख कर काफ़ी कुछ कर सकती हैं. कम से कम मोदी को जीतने से तो रोक ही सकती हैं. लेकिन दुखद रूप से उनका ऐसा सोचना ग़लत है, क्योंकि सपा, बसपा, राजद और यहां तक जदयू का भी आप से गठबंधन होना मुश्किल है.

बीते विधानसभा चुनावों में मोदी की कोई लहर नहीं थी. हां, बिल्कुल नहीं थी. बिना नरेंद्र मोदी की लहर के ही राजस्थान में कांग्रेस घटकर 21 सीटों पर आ गई. दरअसल, भाजपा को मोदी की आवश्यकता इसलिए नहीं थी, क्योंकि उसके पास अशोक गहलोत के साथ झगड़े में व्यस्त सीपी जोशी थे. वहीं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के राहुल गांधी की पसंद के होने के कारण असहाय अवस्था में पड़े सचिन पायलट भी थे, जो भाजपा की मदद कर रहे थे. इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी मध्य प्रदेश में दो तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं थी. लाचार अवस्था में सिर्फ़ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही शिवराज की जीत के लिए काफ़ी थे.

राहुल गांधी द्वारा चुने गए रणनीतिकार मुधुसूदन मिस्त्री छत्तीसगढ़ में हार के लिए काफ़ी थे. अगर भाजपा के विरोध में कमज़ोर टीम है, तो उसे चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत ही क्या थी?

इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को उनके जीत के क्षणों को थोड़ा हल्का करके भी देख जा सकता है. कांग्रेस ने शीला दीक्षित को बहुत पहले ही अकेला छोड़ दिया था. अगर वे चौथी बार राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो आपको यह मालूम ही है कि वे किसके लिए ख़तरा बन जातीं? राहुल गांधी दो बार शीला दीक्षित की रैलियों में तीन घंटे से ज्यादा देर से पहुंचे. किसी को इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राहुल की कितनी इच्छा थी कि शीला दीक्षित चौथी बार मुख्यमंत्री बनें. खाद्य सुरक्षा और आधार कार्ड जैसी सारी योजनाएं आम चुनावों को ध्यान में रखकर ही लागू की गईं थीं. इन बेहतर योजनाओं के लिए किसी भी तरह राहुल के अलावा किसी और को महत्व नहीं दिया जा सकता था.

आप इसके बारे में सोचिए कि अगर कांग्रेस इन चुनावों में जीत जाती, तो राहुल कितने प्रभावशाली हो सकते थे. विशेष रूप से विपक्ष के लिए.

इसके अलावा देश के लिए ख़ुशी के समाचार और भी हैं. वह है आम आदमी पार्टी की जीत. जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की घोषणा हुई थी, उस समय मैंने इसका स्वागत किया था. यह 1960 में स्वतंत्र पार्टी के गठन के बाद पहला आधुनिक राजनीतिक गठन था. आम आदमी पार्टी विचारधारा के आधार पर तो स्वतंत्र पार्टी से एकदम अलग है, लेकिन अन्य पार्टियों में उपस्थित भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर दोनों पार्टियों की विचारधारा एक तरह की ही है. आप पार्टी में स्वतंत्र सदस्यता लेने की व्यवस्था है और लोग इस

पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ टिकट चाहिए. दरअसल, देश में युवा आम आदमी पार्टी के आने से जोश में है.

हालांकि, यह पार्टी अभी नई-नई है. आंदोलनों से उपजी पार्टियों को शुरुआत में कामयाबी मिलती है, लेकिन उन्हें दोबारा भी सफलता मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता. आइए विचार करें कि अगर आम आदमी पार्टी अपना दायरा फैलाएगी तो क्या होगा. दिल्ली बहुत छोटा राज्य है. वास्तविकता में यह एक राज्य नहीं है. आप कुछ सौ वॉलंटियर के साथ दरवाज़े-दरवाज़े जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं. लेकिन मुंबई में यह तरीक़ा कारगर नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना ने यह तरीक़ा पचास साल पहले ही प्रयोग कर लिया है. शिवसेना की पहुंच वहां गली-गली में है. कोलकाता में तो तृणमूल और सीपीआई के बीच एक स्थाई जंग-सी है, तो समझ लीजिए वहां भी कोई एंट्री नहीं है.

इसके बावजूद उन्हें मेरी तरफ से बधाई. उनकी सफलता से धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को यह भ्रम हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक दूसरी पार्टी का भी उदय हो गया है, जिससे गठजोड़ किया जा सकता है. आप पार्टी से सभी क्षेत्रीय पार्टियां सीखकर काफ़ी कुछ कर सकती हैं. कम से कम मोदी को जीतने से तो रोक ही सकती हैं. लेकिन दुखद रूप से उनका ऐसा सोचना ग़लत है. क्योंकि सपा, बसपा, राजद और यहां तक जदयू का भी आप से गठबंधन होना मुश्किल है. आप जिस तरह कांग्रस विरोधी है, उसी तरह मायावती और लालू की भी विरोधी है. इसलिए कांग्रेस प्रेमी कोई सांत्वना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं और देखना होगा. लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें राहुल की तरफ नहीं देखना चाहिए. ये चुनाव कई मामलों में भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक हैं. 1969 में इंदिरा गांधी ने ऐसी राजनीति शुरू की थी, जिसमें उन्होंने सत्ता का केंद्र एक परिवार को बना दिया था. राजसत्ता की शुरुआत बेहतरीन शासकों के साथ शुरू होती है और आख़िरी में कमज़ोर शासकों के साथ. हमारे उदाहरण के रूप में मुगल वंश है, जिसमें अकबर और औरंगज़ेब जैसे शासक थे और बाद में शाह आलम जैसे भी. इस बात का विचार करना कि राहुल एक बार फिर पार्टी को जीतने की अवस्था में पहुंचा सकेंगे, यही प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस यह नहीं समझ पा रही कि इस समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता. आप की जीत के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने यह कहा कि हमें सीखने की ज़रूरत है, यह दर्शाता है वे राजनीति में अभी नौसिखिए हैं. उन्होंने हाल ही में आप का मोबाइल ऐप पाया है और अब वे इसे ऑनलाइन ख़रीदेंगे और प्रयोग में लाएंगे. उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और उन्हें भी, जो उनमें विश्वास करते हैं. तो हाल में कांग्रेस की बड़ी हार के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए? पहले राहुल को या फिर आप पार्टी को?■

दिल्ली बहुत छोटा राज्य है. वास्तविकता में यह एक राज्य नहीं है. आप कुछ सौ वॉलंटियर के साथ दरवाज़े-दरवाज़े जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं. लेकिन मुंबई में यह तरीक़ा कारगर नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना ने यह तरीक़ा पचास साल पहले ही प्रयोग कर लिया है. शिवसेना की पहुंच वहां गली-गली में है. कोलकाता में तो तृणमूल और सीपीआई के बीच एक स्थाई जंग-सी है, तो समझ लीजिए वहां भी कोई एंट्री नहीं है.

editor@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना

चौथी दुनिया ब्यूरो

पिछले अंकों में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. द्वितीय अपील तब करते हैं, जब प्रथम अपील के बाद भी आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग और केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है. हमने आपकी सुविधा के लिए द्वितीय अपील का एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. हमें उम्मीद है कि आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा. इससे निश्चय ही फ़ायदा होगा. इस अंक में हम सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 18 के बारे में बात कर रहे हैं. धारा 18 के तहत शिक़ायत दर्ज कराने की व्यवस्था है. एक आवेदक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन-किन परिस्थितियों में शिक़ायत दर्ज कराई जा सकती है. लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है तो इसकी शिक़ायत सीधे आयोग में की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने, भ्रामक या ग़लत सूचना देने के ख़िलाफ़ भी शिक़ायत दर्ज कराई जा सकती है. सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के ख़िलाफ़ भी आवेदक आयोग में सीधे शिक़ायत दर्ज करा सकता है. उपरोक्त में से कोई भी स्थिति सामने आने पर आवेदक को प्रथम अपील करने की ज़रूरत नहीं होती. आवेदक चाहे तो सीधे सूचना आयोग में अपनी शिक़ायत दर्ज करा सकता है. शिक़ायत का एक प्रारूप भी हम इसी अंक में प्रकाशित कर रहे हैं. आशा है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. आप आरटीआई से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

शिकायत का प्रारूप

सेवा में,
केंद्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पता.....

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरा जाए
1	आवेदक का नाम और पता	
2	(क) लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिसके विरुद्ध शिकायत है. (ख) आवेदन की तिथि. (ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि.	
3	(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता. (ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि. (ग) प्राप्त जवाब की तिथि.	
4	जिन आदेशों के विरुद्ध शिकायत की जानी है, उसका विवरण.	
5	शिकायत का संक्षिप्त विवरण.	
6	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नामंजूर किए जाने की दशा में आवेदन की तिथि और विषय वस्तु का विवरण.	
7	आयोग से निवेदन या राहत.	लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरंत सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दें. साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 20 (1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20 (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करें. आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं. अत: मुझे सुनवाई की अग्रिम सूचना अवश्य दें.
8	अन्य कोई सूचना, जो शिकायत निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो.	

मैं.....उपरोक्त शिकायत को दिनांक..... को सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है. इस शिकायत में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं.

संलग्नक सूची
1. आवेदन की प्रति.
2. शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति.
3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति.
4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति.
5. प्रथम अपील की प्रति.
6. प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति.
7. प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति.
8. शिकायत की एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने का प्रमाण.

नाम.....
पता.....
स्थान.....
तिथि.....

नोट : शिकायत को डबल स्पेसिंग लाइन में बनाएं, यानी लाइनों के बीच दोगुनी जगह छोड़ें. शिकायत की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजें. शिकायत की दो प्रतियां सूचना आयोग में भेजें. साथ ही एक प्रति अपने पास रखें.

ज़रा हट के

अनोखा है यह रसोई गैस बुकिंग मॉडल

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का नाम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएगा. यहां के उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो जाए. इसके लिए गोंडा के जिलाधिकारी द्वारा ई-गर्वनेंस के माध्यम से ईजी गैस सॉफ्टवेयर विकसित कराया गया है, जो अपने आप में अनोखा होगा. गोंडा के जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब का कहना है कि कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम लागू होने से योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा आसान हो जाएगी. साथ ही इसमें कम्प्यूटराइज्ड दस्तावेज से छेड़छाड़ की संभावना कम रहती है. उन्होंने पिछले साल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से ईजी गैस नामक सॉफ्टवेयर विकसित कराया है.

नई व्यवस्था के तहत सभी गैस एजेंसियों को ऑनलाइन करते हुए सभी उपभोक्ताओं का पूरा विवरण कम्प्यूटर में दर्ज करवाया गया. वहीं, दूरदराज के क्षेत्रों में बैठे उपभोक्ताओं को सुविधा दी गई कि वे न्याय पंचायत स्तर पर खोले गए 186 लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से मात्र दस रुपये में ऑनलाइन गैस की बुकिंग करवाकर रसीद प्राप्त करें. इस रसीद में बुकिंग और उपभोक्ता से संबंधित पूरा विवरण दर्ज होता है. ■

सात दिनों के अंदर मिलेगी गैस

किसी भी बुकिंग के बाद एजेंसियों को सात दिनों के अंदर गैस सिलेंडर मुहैया करने की अनिवार्यता रखी गई है. यदि किसी उपभोक्ता को तय समय के अंदर सिलेंडर नहीं मिल पाता है तो वह बुकिंग डिफॉल्टर की सूची में दर्ज हो जाती है. ईजी गैस के सॉफ्टवेयर पर एजेंसीवार कुल बुकिंग, कुल डिलेवरी और डिफॉल्टर की अलग-अलग सूचना खुद ही अपडेट होती रहती है.

इस व्यवस्था के लागू होने से गैस की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है. साथ ही कोई भी बड़ा अधिकारी कम्प्यूटर पर चंद मिनटों में ही जिले की सभी 11 गैस एजेंसियों द्वारा बुकिंग और वितरण की समीक्षा कर सकता है. ■

डिफॉल्टर पाए गए तो जवाब-तलब

ईजी गैस में यदि किसी एजेंसी के डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ती है तो जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने की व्यवस्था की गई है. खास बात यह है कि एक बार बुकिंग होने पर जब तक उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं मिलता, तब तक उसका नाम डिफॉल्टर की सूची में बना रहता है.

इस तरह सिलेंडरों की संख्या घटाने या खत्म करने के लिए प्रत्येक एजेंसी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बुकिंग के सात दिन के अंदर उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध करा दें.■

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आप क्रोध से भरे रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों से विवाद से बचें. आलस्य हावी न होनें दे. अन्यथा नुकसान होगा. इस सप्ताह खतरों से बचें. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको सफलता प्राप्त होगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे आपके अनसुलझे कार्य सिद्ध होंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए लाभप्रद साबित होगी. आपके ऊपर वित्तीय बोझ कम होगा. संपत्ति विवाद से बचें. व्यवसाय से संबंधित निर्णय जल्दबाजी में न लें. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित कर लें. आप धन की अहमियत को समझेंगे. इस सप्ताह समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. इस सप्ताह पूरे विश्वास के साथ कार्य करेंगे. जमीन-जायदाद खरीदने की योजना बना सकते हैं. पारिवारिक क्लेश रहेगा. इससे बचें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
भाग्य से ज्यादा कर्म करने पर ध्यान देने की जरूरत है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे. पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. इस सप्ताह कार्य पर ध्यान दें. उपलब्धियों के पीछे न भागें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप उत्साह से भरे रहेंगे. इस सप्ताह कुछ नई योजना बनाएंगे. कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात होगी. किसी मित्र पर विश्वास कर फैसला न लें. किसी नये व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिससे आपको फायदा होगा. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
ऐसा कोई समाचार प्राप्त होगा, जिससे आप अप्रसन्न रहेंगे, लेकिन निराश न हों. किसी पारिवारिक सदस्य से आपकी बहस हो सकती है. आलस्य के कारण आपको अपमान सहना पड़ सकता है. स्थानांतरण से प्रोन्नति का योग है. जोखिम वाले बाजार से बचें. विरोधी हावी रहेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप घरेलू कार्यों को अधिक महत्व देंगे, जिससे परिवार के लोग आप से खुश रहेंगे. आप नये जमीन-जायदाद और घर के लिए साजो-समान खरीदेंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. मित्रों से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. परिवार में बड़े आयोजन हो सकते हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
उत्साह और उमंग से आप उत्साहित रहेंगे. आप अधिक कार्य करेंगे, जिसका आपको पुरस्कार मिलेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. सेहत का ध्यान रखें. यह सप्ताह मौज-मस्ती वाला रहेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
धन को व्यर्थ खर्च न करें. अन्यथा नुकसान हो सकता है. नई योजनाएं बनाएंगे, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी. इस सप्ताह आपका ज्यादा समय कार्यों में व्यतीत होगा. भावुकता में आकर कोई संपत्ति खरीदने का निर्णय न लें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों अपने कार्य पर ध्यान दें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
क्रोध से बचें. आपको सगे-संबंधी और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. मानसिक तनाव से बचें. कोई भी पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतें. आप अपनी मेहनत से लोगों को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आपके प्रति लोगों का व्यवहार सौहार्द्र और सहयोगात्मक होगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें. आपको फायदा होगा. यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
अपनी महात्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखें और कार्य करते रहें. फल की चिंता न करें. आप अपनी मन की बातों को गोपनीय रखें. शत्रुओं को हावी न होंने दें. किसी को कर्ज देने पहले विचार जरूर करें. नौकरीपेशा को मेहनत से सफलता प्राप्त होगी. किसी अधिकारी के क्रोध का शिकार हो सकते हैं.

csastrologer@gmail.com

124 लाख डॉलर में बिकी पेंटिंग

चीन में एक पेन्टर द्वारा बनाई गई पेंटिंग ने नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया है. चीन के पिकासो के नाम से मशहूर पेंटर जोऊ वू की बनाई पेंटिंग ने नीलामी में नया रिकॉर्ड कायम किया. उनकी पेटिंग 124.7 लाख डॉलर में नीलाम हुई. अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सोथिबे कंपनी ने पेंटिंग की नीलामी कराई थी. झांग जियाजुन ने पेंटिंग को खरीदा है, जो चीन के शांक्सी प्रांत का मशहूर कोयला व्यापारी है. जोऊ को अनोखे और आकर्षक कलाकृतियों के निर्माण के लिए जाना जाता है. जोऊ ने इससे पूर्व अपनी एक पेंटिंग की कीमत 62 लाख डॉलर रखी थी, हालांकि वह इसे बेच पाने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी इस खूबसूरत पेंटिंग को कदरदान मिल गया और ये पूरे 124 लाख डॉलर में बिकी. ■

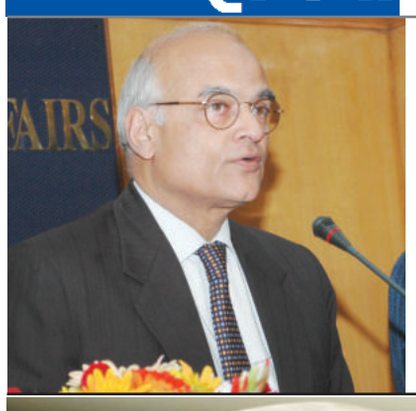

आख़िर विश्व का ऐसा कौन सा देश है, जो तलाशी के नाम पर अपने वहशी कार्रवाइयों को अंजाम देकर खुद को सभ्य समाज का हिस्सा कह सकता है? अगर भारत या किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र का कोई बड़ा अधिकारी अमेरिका में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है तो वह आतंकी या क्रिमिनल नहीं हो सकता. फिर भी उक्त देश की सरकार को किसी प्रकार की शंका होती है तो उस व्यक्ति की जांच आधुनिकतम स्कैनर या अन्य मशीनों से की जा सकती है.

देवयानी से दुर्व्यवहार

फिर सामने आया अमेरिका का असभ्य चेहरा

अमेरिका ने भारत की राजदूत देवयानी खोबरागड़े के साथ तलाशी के नाम पर जिस तरह से असभ्य हरकत की, उसके पीछे भारत सरकार की कमजोर नीतियां ही जिम्मेदार हैं. अमेरिका में भारत की राजदूत रहने के दौरान देवयानी की निर्वस्त्र तलाशी एक बर्बर कार्रवाई है. देवयानी प्रकरण से एक बार फिर बिगड़ैल अमेरिका का असभ्य चेहरा सामने आ गया है. भारत अमेरिका की इस असभ्य परंपरा पर रोक लगा पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है, क्योंकि अमेरिका ने देवयानी से पहले जिन भारतीय शख्सियतों के साथ इस तरह की नापाक हरकतें की हैं, उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है.

राजीव रंजन

अमेरिका में भारत की राजदूत देवयानी खोबरागड़े को पिछले दिनों गिरफ्तार कर सरेआम हथकड़ी पहनाई गई. उसके बाद देवयानी को निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई. उन्हें कैविटी सर्च से गुजरना पड़ा. देवयानी की जिस तरह से तलाशी ली गई, उसे कोई भी सभ्य देश जायज नहीं ठहरा सकता. तलाशी के इस तरीके को अमेरिका की असभ्य और बर्बर कार्रवाई ही कहा जाएगा.

देवयानी तलाशी के दौरान बार-बार रोईं. शायद देवयानी अपने भाग्य पर रो रही थीं कि अमेरिका में भारत की प्रतिनिधि होने के बावजूद उनको यह दिन देखना पड़ा, लेकिन देवयानी के साथ जो हुआ, वह किसी भारतीय के साथ पहली बार नहीं हुआ था. कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे भारत सरकार की कमजोर नीतियां ही जिम्मेदार हैं. सरकार की नीतियां इसलिए जिम्मेदार हैं कि इस तरह की घटना को अमेरिका ने पहली बार अंजाम नहीं दिया है. और अगर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं तो समय रहते भारत सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों भारत ने अमेरिका को बार-बार इस तरह की असभ्य घटनाओं को अंजाम देने के लिए मौका दिया.

देवयानी पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत ने भी जनता के प्रतिरोध को देखते हुए आनन-फानन में कार्रवाई की. भारत ने कार्रवाई के रूप में अमेरिकी राजदूत को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को कम कर दिया. सवाल यह उठता है कि भारत में अमेरिका के राजदूत को विएना समझौते की अनदेखी कर विशेष सुविधा क्यों मिली थी? भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अमेरिका को जिस विएना समझौता की याद आई, क्या वह समझौता भारत पर लागू नहीं होता? क्या विएना समझौता सिर्फ अमेरिका के लिए था? भारत ने अमेरिकी राजदूत को विएना समझौते को ताक पर रखकर सुविधाओं में बेवजह ढील क्यों दी? भारत सरकार की इन बचकानी हरकतों के कारण ही अमेरिकी सरकार को विएना समझौते के मुद्दे पर भारत से सवाल-जवाब करने की हिम्मत हो रही है. आखिर जमीन तो भारत ने ही तैयार की है. सच्चाई तो यह है कि अमेरिकी राजदूत को भारत ने कुछ ज्यादा ही तरजीह दे रखा था. क्या यह मेड इन अमेरिका के प्रति भारतीय सम्मोहन है? क्या भारत अभी भी अमेरिका से डरता है? भारत द्वारा अमेरिका को बढ़-चढ़ कर आंकने के कारण ही अमेरिका का मन बढ़ा हुआ है और इसी कारण वह असभ्य और बर्बर हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद भारत में समलैंगिकता अपराध है. कहा जाता है कि भारत स्थित अमेरिकी राजदूत समलैंगिक हैं. अगर यह सच है और अमेरिकी राजदूत इस तरह के कृत्यों के लिए दोषी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी क्यों? क्या हमारे यहां अमेरिकी कार्रवाइयों के बाद ही कार्रवाई करने की परंपरा रही है? आखिर हम हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में क्यों खड़े रहते हैं?

अमेरिका भारतीय शख्सियतों के कपड़े उतार कर तलाशी लेता है. कैविटी सर्च जैसी शर्मनाक जांच के लिए उन्हें बाध्य करता है. यह भारत सरकार की कमजोर नीतियों का ही दोष है कि वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा पर गए भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की तलाशी अमेरिका कपड़े उतार कर लेता है. पूर्व राष्ट्रपति कलाम को बेइज्जत करता है. कई राजनयिकों के साथ अमेरिका तलाशी के नाम पर बदसलूकी कर चुका है. देवयानी दूसरी महिला राजनयिक हैं, जिन्हें अमेरिका ने निर्वस्त्र कर तलाशी ली. देवयानी से पहले मीरा शंकर को भी अमेरिका ने निर्वस्त्र कर तलाशी ली थी.

अमेरिका यह सफाई दे रहा है कि देवयानी ने संगीन अपराध किए हैं. इसीलिए उनकी तलाशी लेनी पड़ी. पहली बात तो यह कि किसी भी राजनयिक के साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है. अमेरिका थोथी दलील दे रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका ने कई भारतीय शख्सियतों के कपड़े उतार कर तलाशी ली है. क्या अमेरिका के पास इस सवाल का जवाब है कि भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के कपड़े उतार कर उसने तलाशी क्यों ली? जॉर्ज भारत के रक्षा मंत्री थे. क्या अमेरिका बताएगा कि अगर राजनयिक मीरा शंकर की तलाशी ही लेना था तो उसका कोई और तरीका था या नहीं? अमेरिका भले ही अपने द्वारा की गई बर्बर कार्रवाइयों पर अपने देश के नियमों की दुहाई दे, लेकिन यह सत्य है कि अगर उसके यहां इस तरह के नियम हैं, तो उसके ये नियम भी उसी की तरह असभ्य हैं. अन्यथा दुनिया में इस तरह के नियमों की दलील देने वाला अमेरिका एक अकेला देश नहीं होता. और न ही इस तर्क को काटने के लिए वह यह कह सकता है कि विश्व भर में एकमात्र वही आतंक से प्रभावित देश है, इसलिए उसे तलाशी का यह रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है.

देवयानी पर आरोप

देवयानी ने अपने घरेलू सहायक के वीज़ा आवेदन में ग़लत दस्तावेज़ पेश करवाए और जानबूझ कर ग़लत जानकारी पेश करके वीज़ा हासिल किया. उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी क़ानून के तहत कामगारों को दी जानेवाली दूसरी सुविधाओं का भी उल्लंघन किया. देवयानी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो अमेरिकी कानूनों के तहत काफी संगीन अपराध माने जाते हैं.

अमेरिकी बदसलूकी का शिकार भारतीय शख्सियतें

- पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दो बार न्यूयॉर्क के जेकेएफ एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई थी.
- 2002 में वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा पर गए फर्नांडिस की अमेरिकी एयरपोर्ट पर कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी.
- सितंबर 2010 में केन्द्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- अमेरिका में भारत की पूर्व राजनयिक मीरा शंकर की तलाशी कपड़े उतरवाकर ली गई.
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी को ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- 2009 में फिल्म स्टार ममूटी को न्यूयॉर्क के जेकेएफ एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- 2000 में बॉलीवुड स्टार आमिर खान की शिकागो एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई.
- बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को दो बार हिरासत में लिया गया.
- बॉलीवुड स्टार इरफान खान को दो बार अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- 2009 में ही बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- 2009 में बॉलीवुड स्टार नील नितिन मुकेश को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
- 2008 में फिल्म निर्माता कबीर खान को अमेरिका के विभिन्न एयरपोर्ट पर तीन बार हिरासत में लिया गया.

हमारा देश भी आतंकवाद की चपेट में है. हमें भी तलाशी का हक है. इसका मतलब यह नहीं है कि तलाशी के नाम पर हम किसी देश के मुसलमान के साथ इसलिए हैवानियत पर उतर आएं कि उसके नाम के साथ खान जुड़ा है. किसी सरदार को उसकी पगड़ी उतार कर शर्मशार किया जाए, जैसा कि पूर्व भारतीय राजनयिक हरदीप पूरी के साथ किया गया. किसी संप्रभु राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति को जूते या कोट उतारने के लिए कहा जाए, जैसा कि कलाम के साथ किया गया. किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाए और कैविटी सर्च के बहाने उसके गुप्तांगों की जांच की जाए. आखिर विश्व का ऐसा कौन सा देश है, जो तलाशी के नाम पर अपने वहशी कार्रवाइयों को अंजाम देकर खुद को सभ्य समाज का हिस्सा कह सकता है? अगर भारत या किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र का कोई बड़ा अधिकारी अमेरिका में उस सरकार की मान्यता के बाद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है तो वह आतंकी नहीं हो सकता. वह क्रिमिनल नहीं हो सकता. फिर भी उक्त देश की सरकार को किसी प्रकार की शंका होती है तो उस व्यक्ति की जांच आधुनिकतम स्कैनर या अन्य मशीनों से की जा सकती है. ये नहीं कि तलाशी और जांच के नाम पर उसे कपड़े उतारने को कहा जाए. उसकी कैविटी सर्च यानी मुंह के अंदर और गुप्तांगों की तलाशी ली जाए. उसे सार्वजनिक तौर पर हथकड़ी पहनाई जाए. एक राजनयिक के साथ इस तरह का व्यवहार विएना समझौते का उल्लंघन है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है. क्या एयरपोर्ट पर दुनिया के अन्य देश लोगों की तलाशी कपड़े उतरवाकर ही लेते हैं? अगर नहीं, तो मनचले अमेरिका ने भारतीय शख्सियतों के क्यों कपड़े उतरवाए, क्यों उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया? और भारत सरकार ने अमेरिका के इस नापाक हरकतों का जवाब हमेशा लफ्फाजियों से ही क्यों दिया. जब-जब अमेरिका इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम अमेरिका के इस कदम की कड़ी निन्दा करते हैं. क्या होता है निन्दा या भर्त्सना करने से? क्या इससे पीड़ित अधिकारी को इंसाफ मिल जाता है? इसका जवाब होगा नहीं. जरूरत है कार्रवाई की. जैसा कि इस बार कुछ हद तक किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. क्योंकि जिस कार्रवाई की बात कही जा रही है, वह अमेरिकी राजदूत को मिलने वाली अधिक सुविधाओं को हटा लेने से संबंधित है. भारत को अमेरिका पर अभी भी ठोस कार्रवाई की जरूरत है.

भारत को ध्यान रखना होगा

देवयानी अमेरिका में भारत की प्रतिनिधि हैं और इसी कारण भारत को उनके साथ अमेरिकी दुर्व्यवहार पर सख्त कदम उठाना पड़ा है. अगर देवयानी ने अपने पद का फायदा उठाकर कुछ गलत किया है और अमेरिकी आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो भारत सरकार को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बड़े पदों पर बैठने वालों की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है. देवयानी का एक गलत कदम पूरे विश्व में भारत की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफी है और अगर देवयानी गलत नहीं हैं तो भारत को मनचले अमेरिका की दादागिरी पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि फिर से अमेरिका ऐसे असभ्य कदम उठाने की जुर्रत न करे. भारत का यह कदम विश्व के किसी भी देश के लिए एक ऐसा सबक होगा, जो भारत को कमजोर आंकते हैं. ■

साई

मानव प्राणी को ज्ञान ईश्वर की एक विशेष देन हैं, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर–दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में सम्भव नहीं है. देवता भी पृथ्वी पर मानव–जन्म धारण करने के हेतु सदैव लालायित रहते है. इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझ कर उसकी उपेक्षा करे तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे. यदि हम उसे मूल्यवान समझ कर उसका मोह करेंगे तो हम इन्द्रिय–सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है.

एक बार...

साई सदैव आत्मलीन रहते थे

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस विचित्र संसार में ईश्वर ने हिन्दू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है (जिनमें देव, दानव, गन्धर्व, जीवजन्तु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं), जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न–भिन्न धर्मों का पालन करते हैं. इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं. पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी, जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं. जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव–जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है. मानव प्राणी को ज्ञान ईश्वर की एक विशेष देन हैं, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर–दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में सम्भव नहीं है. देवता भी पृथ्वी पर मानव–जन्म धारण करने के हेतु सदैव लालायित रहते है. इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझ कर उसकी उपेक्षा करे तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे. यदि हम उसे मूल्यवान समझ कर उसका मोह करेंगे तो हम इन्द्रिय–सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है. इसलिए उचित मार्ग, जिसका आवलम्बन करना चाहिए, यह है कि न तो देह की उपेक्षा ही करो और न ही उसमें आशक्ति रखो. केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है, जब तक वह अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंच कर लौट न आए. इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म–साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है. ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ, कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे विशेष ज्ञान प्रदान की. जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ. इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है. उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, लेकिन साई–चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है. इस संसार में मानव–जन्म अति दुर्लभ है. हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है. ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए. जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार विलंब न कर हमें भी अपने अभीष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करना ही सर्वथा उचित है. अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का हमेशा ध्यान करना चाहिए. यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा.

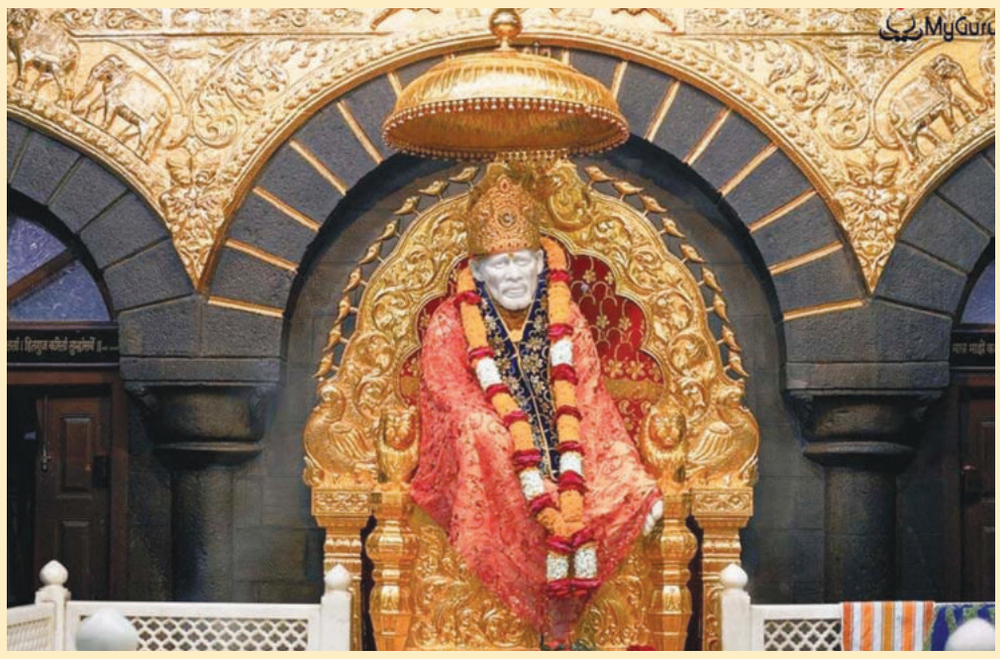

अधिक सफलतापूर्वक और सुलभ साक्षात्कार को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है-किसी योग्य संत या सदगुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो. जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही में प्राप्त हो जाता है. जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते. इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सदगुरू साई की कृपा से हो सकती है, वह ग्रन्थों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है. उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु-भाषण, गुहा उपदेश, क्षमाशीलता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार-शून्यता आदि गुण, जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल-विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्तों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते है.

अधिक सफलतापूर्वक और सुलभ साक्षात्कार को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है–किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो. जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही में प्राप्त हो जाता है. जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते. इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सदगुरू साई की कृपा से हो सकती है, वह ग्रन्थों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है. उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु–भाषण, गुहा उपदेश, क्षमाशीलता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार–शून्यता आदि गुण, जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल–विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्तों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते है. इससे मस्तिष्क की जागृति होती तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है. साईबाबा इसी प्रकार के एक संत या सदगुरु थे. यद्यपि वे बाह्यरुप से एक फकीर का अभिनय करते थे, लेकिन वे सदैव आत्मलीन रहते थे. वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत–दर्शन का अनुभव करते थे. सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे विपत्तियों से विचलित होते थे. उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे. साई बाबा कहते हैं जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है, वह सदैव मेरा दर्शन पाता है. उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है. वह केवल मेरा ही लीलागान करता है. वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा जो मेरा ही चिन्तन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख–प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है, जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है. अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति, जो तुम्हारे हृदय में आसीन है, पूर्ण रुप से समर्पित हो जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

आधुनिक समाज का यही ब्रह्मप्रश्न है

डॉ. अभय बंग

पाहोम नामक एक हुनरमंद व उत्साही रूसी किसान था. जब उसे पता चला कि एक पड़ोसी राज्य में उपजाऊ खेत बिकाऊ है, तब अपना खेत बेचकर वह उस राज्य में चला गया. वहां जमीन खरीद ली और खेती करने लगा. फिर उसे बेचकर दूसरी जगह और अधिक खेत खरीद लिए. पाहोम ने ऐसा कई बार किया. अब वह खूब अमीर हो गया था. लेकिन यात्रियों से पता चला कि दूर एक देश है जहां आदिवासी रहते हैं. वहां की जमीन अतिशय उपजाऊ है. वहां के आदिवासियों को उसका मूल्य ही मालूम नहीं. पाहोम को असीम खेती का स्वप्न दिखाई देने लगा. पत्नी बोली अपने पास सब कुछ है और भरपूर है. अब और क्या दौड़–भाग? पाहोम पत्नी पर नाराज हुआ. संसार में प्रगति करनी हो तो थोड़ी मुश्किलें तो सहन करनी ही पड़ती हैं. पत्नी और बच्चों को वहीं छोड़कर और बहुत सा पैसा और सोना लेकर पाहोम असीम वैभव की खोज में निकल पड़ा. ढूंढ़ते–ढूंढ़ते पाहोम आदिवासियों के देश में पहुंच ही गया. यात्रियों के बताए अनुसार वहां वाकई खूब खेती उपलब्ध थी. वह अधीर हो उठा उसे रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई. दूसरे दिन वह सबेरे जल्दी उठा. सारे आदिवासी व उनका बूढ़ा मुखिया एकत्र हो चुके थे. पाहोम ने मुखिया को एक हजार मोहरों की थैली अर्पण की व खेती के लिए जमीन मांगी. मुखिया ने हंसकर सम्मति दे दी और वहां का नियम सुनाया, सूर्य उगने से अस्त होने तक तुम चलकर जितनी जमीन घेर सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी.

पाहोम मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से शांत रहा. इन आदिवासियों को पता नहीं चले कि कितना बड़ा इलाका मैं घेर लेने वाला हूं. लेकिन सूर्योदय पर जहां से निकले थे वहां तक सूर्यास्त से पूर्व वापिस नहीं पहुंचे और प्रदक्षिणा अपूर्ण रह गई तो तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी और मोहरों से भी हाथ धो बैठोगे, मुखिया ने पूरा नियम बताया. पाहोम ने खतरे का इशारा मन में दर्ज कर लिया. सूर्य क्षितिज पर दिखाई देते ही पाहोम ने पूर्व दिशा में चलने की शुरूआत कर दी. उत्साह से भरा पाहोम चल रहा था. पक्षी चह–चहा रहे थे, लेकिन उधर पाहोम का ध्यान नहीं था. आज वह कितना अमीर हो जाएगा इसका हिसाब मन–ही–मन कर रहा था. सबेरे दस बजे के आस–पास वह पानी पीने के लिए तनिक रुका. थोड़ा नाश्ता किया. वह पूर्व में काफी चला आया था. अब वह बाईं ओर अर्थात उत्तर की ओर मुड़ा और तीव्र गति से चलने लगा. दोपहर दो बजे तक काफी दूरी उसने तय कर ली थी. समय बर्बाद न हो इसलिए उसने खाने का विचार भी त्याग दिया. पाहोम चलता जा रहा था. अब लौट जाएं? लेकिन अब जो जमीन आ रही थी वह अतिशय उपजाऊ थी. और कुछ दूर चलकर उसे भी अपनी प्रदक्षिणा में समेट लेने के इरादे से वह बिना मुड़े उत्तर में ही चलता रहा. उपजाऊ जमीन उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही थी. सूर्य अवश्य मध्यान्ह से काफी नीचे खिसक गया था. पाहोम को ध्यान आया कि यह सारी जमीन पाने लिए

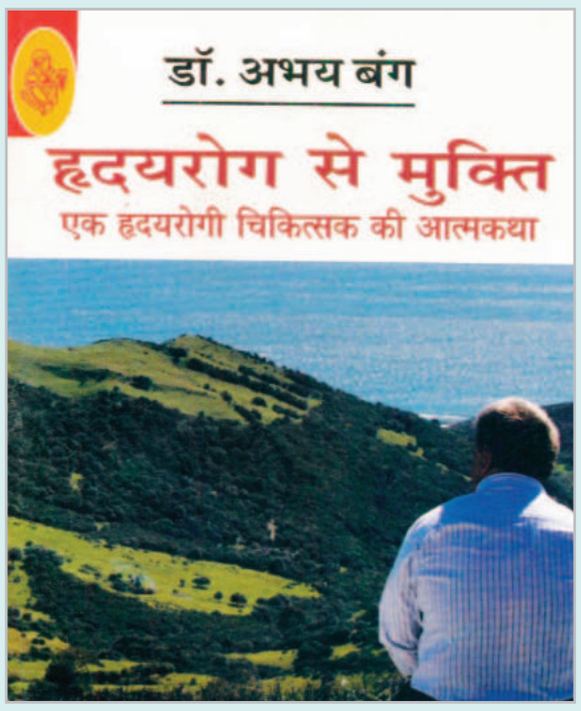

उसे चारों ओर से घेरना आवश्यक है. अतः प्रदक्षिणा की तीसरी बाजू पूरी करने के लिए अब वह पश्चिम की ओर मुड़ गया. तेज गति से चलने लगा. चल क्या रहा था मानो दौड़ ही रहा था. बोझा कम करने के लिए उसने साथ का अन्न एवं पानी फेंक दिया. कोट भी निकालकर डाल दिया. पाहोम सूर्य की ओर देखते हुए दौड़ रहा था. शरीर पसीने–पसीने हो रहा था. शाम हो आई. पाहोम दक्षिण की ओर मुड़ा. अब उसकी प्रदक्षिणा की चौथी व अंतिम भुजा वह पूर्ण कर रहा था. अपार खेती उसकी होने वाली थी, लेकिन सूर्य क्षितिज पर पहुंच चुका था. पाहोम के पैर थक चुके थे. छाती धड़क रही थी. सीने में दर्द हो रहा था. उसने मन ही मन बाल–बच्चों का स्मरण किया. मिलनेवाली जमीन का स्वप्न आंखों में ले आया. अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर जी–जान लगाकर आखिरी दौड़ के लिए दौड़ने लगा. सबकी आंखें सूर्य पर टिकी थीं. पाहोम प्रदक्षिणा पूरा कर सकेगा क्या? पाहोम सचमुच जान की बाजी लगाकर अंतिम पारी दौड़ा. सूर्य ने क्षितिज को स्पर्श किया उस क्षण पाहोम ने सीमा रेखा को छू लिया. लोग खुशी से चिल्ला पड़े. आदिवासियों की दुनिया में किसी ने आज तक इतनी जमीन नहीं जीती थी. वे आनंद से नाचने लगे. पाहोम जमीन पर निश्चल पड़ा था. आदिवासी शांत हो गए. मुखिया उठकर पाहोम के पास आया. यह सारी जमीन नियमानुसार तुम्हारी हो गई. मुखिया बोला, लेकिन पाहोम मर चुका था. अतिश्रम ने उसकी जान ले ली थी. आदिवासियों ने पाहोम की लंबाई का गड्ढा खोदा. उसमें उसका शव रख दिया. सबने मिट्टी डालकर वह गड्ढा भर दिया. उस तीन हाथ जमीन की ओर देखते हुए, विषाद से आदिवासियों का मुखिया बोला–सच पूछो तो उसे इतनी ही जमीन की आवश्यकता थी. हम सब पाहोम हैं. न हों तब भी समाज हमें पाहोम बनाता है. बस, हमारी जमीने भिन्न–भिन्न हैं. किसी को पैसा, किसी को पद, किसी को यश बुलाता है, ललचाता है. जी जान से दौड़ता है. पाहोम दौड़े नहीं तो ये जमीनें कौन पाएगा? पाहोम को दौड़ना ही होगा. उसके लिए उसे जमीन का लाभ होना चाहिए. यही तो मैनेजमेंट का तत्व है. मनुष्य को काम करने की प्रेरणा के लिए लोभ का प्रोत्साहक तो चाहिए ही. सचमुच चाहिए? पाहोम बनने के सिवाय क्या हमारे पास और कोई चारा नहीं है? क्या मनुष्य की नियति इतनी बड़ी शोकान्तिका है? मेरे लिए यह प्रश्न केवल तात्विक चिंतन का नहीं था. मेरे जीवन–मरण का प्रश्न था. आधुनिक जगत में कर्मप्रेरणा के पीछे दौड़ने से मेरी समाजसेवा भी अकांक्षा के घेरे में आ गई थी. और अधिक समाज सेवा मेरे हाथों हो इसकी खातिर मैं जी जान से दौड़ा था. जीवन के सारे महत्व के अंगो को बोझ समझकर फेंक दिया था. यश की रेखा तक दौड़ने की शर्त लगाई थी और अंत में मरने की रेखा तक जा पहुंचा था. पाहोम मर गया, मैं जीवित बच गया, बस इतना ही फर्क था, लेकिन अब मुझे पुनः पाहोम नहीं बनना था. अजीब उलझन है, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे होने की आशा से ही आधुनिक समाज के मनुष्य मर–मराकर काम करते हैं. ये गाजर हटा देने से कर्मप्रेरणा ही गायब हो जाएगी साम्यवादी व्यवस्था इसीलिए तो ढ़ह गई, लेकिन व्यक्तिगत फल की अशक्ति से खूब काम करने पर भी मनुष्य को संतोष नहीं मिलता, इसका क्या?

अहंकार (सत्ता,प्रसिद्धि,मान) स्वार्थ (पैसा, सम्पत्ति, सुविधाएं) तृष्णा व ईर्ष्या इन चार विकारों के घोड़ों को खुली छूट देकर आधुनिक अर्थव्यवस्था का रथ तीव्र गति से बढ़ा जा रहा है, लेकिन इन विकारों की प्रेरणा रथी को हमेशा के लिए दुःखी करने वाली होती है. भारतीय पुराणों के ययाति अथवा ग्रीक पुराणों की ट्रेजडी की तरह आधुनिक मानव की नियति मन के स्तर पर दुःख व शरीर के स्तर पर हृदय रोग यही है. आखिर उपाय क्या है? मनुष्य को लोभ के बिना काम करने की प्रेरणा कैसे मिल सकती है? आधुनिक समाज का यही ब्रह्मप्रश्न है. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

प्रत्येक वस्तु का महत्व

एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव–जंतुओं का उपयोग नहीं है. बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में दो जीव जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार हैं.

राजा ने सोचा– क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए. इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया. युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा.

शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे. काफी दौड़भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए. तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा जिससे राजा की नींद खुल गई. उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जा छिपे. राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया.

शत्रु के सैनिक उन्हें यहां–वहां ढूंढते हुए गुफा के नजदीक पहुंचे. द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना यह जाला क्या नष्ट न हो जाता. गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था. शत्रु के सैनिक आगे निकल गए. उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज बेकार नहीं. यदि जंगली मक्खी और मकड़ी न होती तो उसकी जान न बच पाती. ■

शिक्षा–किसी भी वस्तु को बेकार नहीं समझना चाहिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> दरअसल, हिंदी साहित्य में सालों से एक अस्पृश्यता भाव जारी है, कार्य में भी और व्यवहार में भी. हिंदी के विचारधारा वाले लेखकों को किसी अन्य विचारधारा के लेखकों के साथ मंच साझा करने में तकलीफ़ होती है. गाहे–ब–गाहे इसके उदाहरण भी हमें दिखते रहते हैं. इस साल जुलाई में ही साहित्यिक पत्रिका हंस की सालाना गोष्ठी में मंच पर अशोक वाजपेयी और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े विचारक गोविंदाचार्य की उपस्थिति मात्र से ही तेलुगू कवि और नक्सलियों के हमदर्द वरवरा राव वहां नहीं पहुंचे.

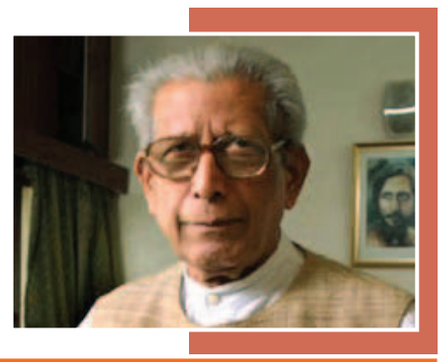

हिंदी के हिरामन पर हमले क्यों

अनंत विजय

रामचरित मानस के सुंदर कांड में एक प्रसंग है जहां रावण अहंकार में डूबकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का हुक्म देता है. तुलसीदास कहते हैं– वचन सुनत कपि मुसकाना, भइ सहाय सारद मैं जाना. अर्थात यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूं कि सरस्वती ही रावण को ऐसा बुद्धि देने में सहायक हुई हैं. कुछ इसी तरह से इन दिनों हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष नामवर सिंह भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे. वो भी यही सोच रहे होंगे कि उनपर हमला करने वाले लोगों के मन में इस तरह के विचार लाने में सरस्वती ही सहायक हुई होंगी. दरअसल, हिंदी साहित्य में इन दिनों एक विवाद उठ खड़ा हुआ है. बिहार से लालू यादव की पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता पप्पू यादव की किताब द्रोहकाल का पथिक (शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली) से प्रकाशित हुआ है. पप्पू यादव कुछ दिनों पहले तक मार्क्सवादी पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मुजरिम थे और जेल में बंद थे. इस वक्त हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं और ख़बरें हैं कि उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी. पप्पू यादव की इस किताब का नामवर सिंह ने दिल्ली में एक समारोह में विमोचन किया.

विमोचन समारोह में नामवर जी के अलावा, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान भी मौजूद थे. अब हिंदी के कुछ क्रांतिकारी लेखक इस बात के लिए नामवर सिंह को घेर रहे हैं कि उन्होंने आपराधिक छवि वाले लेखक पप्पू यादव की किताब का विमोचन क्यों किया? इस पूरे विवाद को सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने भी हवा भी दी और मंच भी मुहैया करवाया. फेसबुक की अराजक आज़ादी का फ़ायदा उठाकर वहां नामवर सिंह पर जमकर हमले शुरू हो गए.

कई टिप्पणियां बेहद स्तरहीन हैं. कुछ नए नवेले क्रांतिकारियों, जिन्हें नामवर जी की साहित्यिक हैसियत का आभास भी नहीं है, ने इस बात को लेकर उनकी लानत मलामत शुरू कर दी. इन उत्साही क्रांतिकारियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि जिस विचारधारा के नामपर वो नामवर सिंह से अपेक्षा कर रहे हैं, दशकों तक नामवर जी ने अपने लेखन का औज़ार भी वहीं से उठाया. उस विचारधारा को

विस्तार देने के लिए सतत प्रयासरत रहे. सालों तक प्रगतिशील आंदोलन के अगुवा रहे. कइयों ने तो उनपर सत्ता और ताक़त के हाथों खेलने का आरोप भी जड़ दिया. ऐसा कहने वाले यह भूल गए कि नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य को पिछले पांच दशकों से एक नई दिशा दी. पहले लिखकर और फिर देश के कोने–कोने में जाकर अपने भाषण से हिंदी के नए लेखकों और पाठकों को संस्कारित किया. गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी नामवर जी को सुनने के लिए पाठकों और छात्रों की भीड़ जमा होती रही है. नामवर जी के लिखे को पढ़कर कई लोगों ने लिखना सीखा. हिंदी का हर लेखक इस बात के लिए लालायित रहता है कि उसकी रचना पर नामवर जी दो शब्द कह दें. सार्वजनिक तौर पर नामवर जी के विरोधी लेखक भी अपनी रचना पर येन केन प्रकारेण उनकी राय जानना चाहते हैं.

यहां सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने कोई कृति लिखी है तो क्या सिर्फ़ इस आधार पर उसपर बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी आपराधिक छवि है या फिर वो जेल काटकर आया है? क्या सिर्फ़ इन आधारों पर पूरी कृति को साहित्य से ख़ारिज़ कर दिया जाना चाहिए. इस पूरे विवाद को उठाने वालों की टिप्पणियां देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पप्पू यादव की किताब को पलटने की जहमत भी नहीं उठाई है, क्योंकि किसी भी टिप्पणी में रचना पर बात नहीं है. पप्पू यादव की किताब सिर्फ़ बहाना है नामवर सिंह को घेरने का. हिंदी में यह स्थिति बेहद चिंताजनक है कि कई लेखकों की रुचि साहित्य से ज्यादा गैर–साहित्यक वजहों और विषयों में होने लगी है. इनमें से कई लेखक तो ऐसे भी हैं जो हिंदी साहित्य में अपनी पारी खेल चुके हैं. और कुछ ऐसे लेखक हैं, जिन्हें लगता है कि नामवर सिंह के ख़िलाफ़ लिखने पर उनको साहसी लेखक माना जाएगा और इसी बहाने उनको कुछ शो–हरत हासिल हो जाएगी. मेरा मानना है कि पप्पू यादव की किताब पर बात होनी चाहिए, उसकी विषयवस्तु पर बात होनी चाहिए. अगर वो कृति कमज़ोर है और नामवर जी ने उसे श्रेष्ठ कहा है तो तर्कों के आधार पर नामवर सिंह की स्थापना को निगेट करना चाहिए.

दरअसल, हिंदी साहित्य में सालों से एक अस्पृश्यता भाव जारी है, कार्य में भी और व्यवहार में भी. हिंदी के विचारधारा वाले लेखकों को किसी अन्य विचारधारा के लेखकों के साथ मंच साझा करने में तकलीफ़ होती है. गाहे–ब–गाहे इसके उदाहरण भी हमें दिखते रहते हैं. इस साल जुलाई में ही साहित्यिक पत्रिका हंस की सालाना गोष्ठी में मंच पर अशोक वाजपेयी और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े विचारक गोविंदाचार्य की उपस्थिति मात्र से ही तेलुगू कवि और नक्सलियों के हमदर्द वरवरा राव वहां नहीं पहुंचे. तर्क यह था कि फासीवादी और पूंजीपतियों के विचारों के पोषक और संवाहकों के साथ जनवादी लेखकों का मंच साझा करना उचित नहीं है. हिंदी साहित्य जगत में उस वक्त भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. जीवित रहते राजेन्द्र यादव को यह बात माननी पड़ी थी कि अलग–अलग विचारधारा के लोगों के बीच विचार विनिमय में कोई भी वाद आड़े नहीं आ सकता है. इस बार भी नामवर विरोध का दूसरा आधार राजनेताओं के साथ मंच साझा करना है. नामवर जी आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि मंच और सभा का माहौल उनसे बनता है. वो जहां मौजूद होते हैं, वहां के श्रोता और मंचासीन लोग भी नामवर जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं. अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की मानसरोवर यात्रा पर लिखी बेहतरीन किताब द्वितियोनास्ति के विमोचन समारोह में भी नामवर जी मौजूद थे. उनके साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, रामकथावाचक मोरारी बापू से लेकर योगगुरु बाबा रामदेव तक मौजूद थे. इस बात पर भी कई लेखकों ने एतराज़ ज़ाहिर किया कि नामवर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर किताब का विमोचन किया. यहां उनपर सांप्रदायिक शक्तियों से मेलजोल का आरोप लगा. मेरा इस बारे में स्पष्ट मत है कि साहित्य और साहित्यकारों को किसी भी तरह की अस्पृश्यता से बचना चाहिए. हम किसी के विचारों को नहीं सुनें या फिर किसी के विचारों का बहिष्कार करें तो यह भी तो एक प्रकार का फासीवाद ही है. इस तरह के वैचारिक फासीवाद का नमूना आपको बहुधा हिंदी जगत में देखने को मिल जाएगा. दरअसल, तथाकथित वामपंथी लेखकों ने अपने इर्द–गिर्द विचारधारा का एक ऐसा कवच तैयार किया हुआ है, जिससे वो असुविधाजनक सवालों से बच सकें. राज–नेताओं की उपस्थिति मात्र से या उनके विचारों को सुनने मात्र से भाषा भ्रष्ट नहीं होगी. कोई भी विचारधारा या उसके संवाहक असुविधाजनक सवालों से बचने का शॉर्टकट ढूंढते हैं तो तय मानिए कि वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी नामवर सिंह को हिंदी में क्या नया लिखा जा रहा है, इसकी जानकारी होती है. नामवर सिंह का विरोध करने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि वो हिंदी की धरोहर हैं, हिरामन हैं, शान हैं. यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस धरोहर कर रखें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)
anant.ibn@gmail.com

कविता

डर का चेहरा बदल गया है अब मेरी दिल्ली में

कायनात नाज़ी

क्या आप ने डर को कभी देखा है?
क्या डर का भी कोई चेहरा होता है?
हां, होता है...
मैंने डर को देखा है,
उसके चेहरे को देखा है.
बहुत क़रीब से देखा है
दिल्ली की सड़कों पर
ऑफिस के कमरों में
मॉल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमाघर में

जब भी दिल्ली की सड़कों पर निकलती हूं
लोगों के चेहरों से डर लगता है
चेहरों के पीछे छुपे नकली चेहरों से डर लगता है
आंखों में छुपे वहशीपन से डर लगता
पहले डर भूत और जानवरों से लगता था
अब ये इंसान को इंसान से है
डर का चेहरा बदल गया है अब मेरी दिल्ली में

कोई राह में मुड़-मुड़ के
इस आस में देखा करता है कि
किसी गाड़ी वाले का दिल पसीज जाए
और उसे लिफ्ट मिल जाए
पर यहां तो अब सब दहशत में हैं
कौन किसकी मदद करे?
इंसान को इंसान का डर
उसकी हैवानियत का डर
तोड़-मरोड़ कर
नोच डालने का डर
रेज़ा-रेज़ा कर देने का डर
बात सिर्फ़ सामान भर लुटने की नहीं
यहां तो असमत दांव पर है
कौन किसको लिफ्ट दे?
किसकी मदद करे?
राह में मदद करने वाला कहीं राहज़न न निकले
सामान के साथ इज़्ज़त भी न गंवानी पड़े
सोच कर वह सिहर उठती है
इंसान ही नहीं, अखबार से भी डर लगता है
हज़ारों निर्भया की ख़बरों से
टीवी पर गूंजती सैकड़ों दामिनी की चीत्कार से
बलात्कार के आंकड़ों से
डर का चेहरा बदल गया है अब मेरी दिल्ली में ■

समीक्षा

स्त्री प्रेम स्वप्न में विचरण करती कविताएं

मनीषा बड़गूजर

ज़मीन से जुड़ाव समकालीन हिंदी कविता का महत्वपूर्ण बिंदु है. कवियत्री सविता सिंह 'अपने जैसा जीवन' और 'नींद थी और रात थी' के बाद अपने नये काव्य संग्रह 'स्वप्न समय' में अपनी उन कविताओं के साथ उपस्थिति दर्ज कराती हैं, जो आज के समय और समाज से लड़ रही हैं. वह सदियों से अंधेरी कोठरियों में बंद स्त्री के मसोसे हुए मन के कई पक्षों को सामने लाई हैं. स्त्री मन की कुलबुलाहट, उसकी बेचैनी, स्वप्न में विचरण करती उसकी आकांक्षाएं, कल्पना में जीती और अपने को महसूस करती उसकी देह आदि अवस्थाओं का वर्णन सविता सिंह की कविताओं का महत्वपूर्ण बिंदु है.

संवेदन शून्य समाज में अब मनुष्य इतना व्यक्तिगत हो गया है कि वह किसी अन्य के दुःख को समझना नहीं चाहता. धीरे–धीरे समाज में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है. इसलिए 'तड़पना पत्थर की आत्मीयता के लिए ज्यूं सदा' सविता सिंह को कविता के माध्यम से कहना पड़ा है और एक जड़ और पत्थरनुमा व्यक्ति से आत्मीयता की उम्मीद के बारे में सोचना भी व्यर्थ है.

सविता सिंह के काव्य का सर्वाधिक प्रबल पक्ष है, उनके काव्य में स्त्री और उसकी मुक्ति के विभिन्न उद्गार और उसके प्रति चिंतन. कवियत्री ने प्रेम संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भली–भांति काव्य पंक्तियों में पिरोया है, अनायास ही ये भाव फूट पड़ते हैं– 'लाना मेरे लिए खुद को/जैसे चिड़िया लाती है तिनका संभलकर.'

कवियत्री की स्त्री सच्चे प्रेम की तलाश में है, वह निरंतर खोज रही है कोई अपना, हालांकि, वह सचेत है कि आज के इस भूमंडलीकरण समाज में जहां प्रेम जैसा शाश्वत और पवित्र संबंध भी बाज़ारवाद की चपेट में आ चुका है. यह सब जानते हुए भी एक स्त्री कहती है– 'चली जाती हूं/उन घाटियों में भटकने/जहां कतई उम्मीद नहीं है उससे मिलने की.'

भारतीय समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहां मनुष्य या मनुष्यता से ऊपर रीति–रिवाज हैं, वे रूढ़ियां गहनतम में व्याप्त हैं जिनके कारण स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण हुआ, परंपरा के नाम पर बाल–विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि का भरपूर निर्वाह भारतीय समाज में होता रहा. 'रक्त प्रेम का ' कविता में सविता सिंह एक ऐसी विधवा स्त्री का वर्णन कर रही हैं– 'चली गई थी/उन विधवाओं के पास/जिन्हें सम्भोग वर्जित है/जिनके रेशमी स्तनों पर/नहीं पड़ता बाहर का कोई प्रकाश.'

एक स्त्री प्रेम की तत्परता, उसके समर्पण को सविता सिंह ने गहनतम रूप में समझा है. वर्तमान समय की पीढ़ी जिस तीव्रतम वेग से बढ़ती जा रही है, ऐसे में उनका संभलना बेहद आवश्यक है. स्त्री अपनी विडंबना, अपनी विवशता को प्रेम में जब बयां करती है, तो लगता है सब ख़त्म हो गया. सविता सिंह के यहां भाषा का चमत्कार यत्र–तत्र दिखाई पड़ता है. इस भाषिक कौशल के द्वारा वे अपने उक्त भावों को इस प्रकार प्रकट करती हैं– 'अब मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी/अब मैं लौट गई हूं उन्हीं पत्तों में/जिनकी मैं हरियाली थी/उन्हीं हवाओं में जिनकी मैं गति थी.'

संबंधों का विघटन सबसे ज्यादा हमारे मन मष्तिष्क को प्रभावित करता है, मानसिक रूप से मनुष्य इसी अवस्था में अस्वस्थ होता है. 'भटकाव' कविता इसी अवस्था का भान कराती हुई प्रतीत होती है– 'मैं ही नहीं भटकती रही थी सच

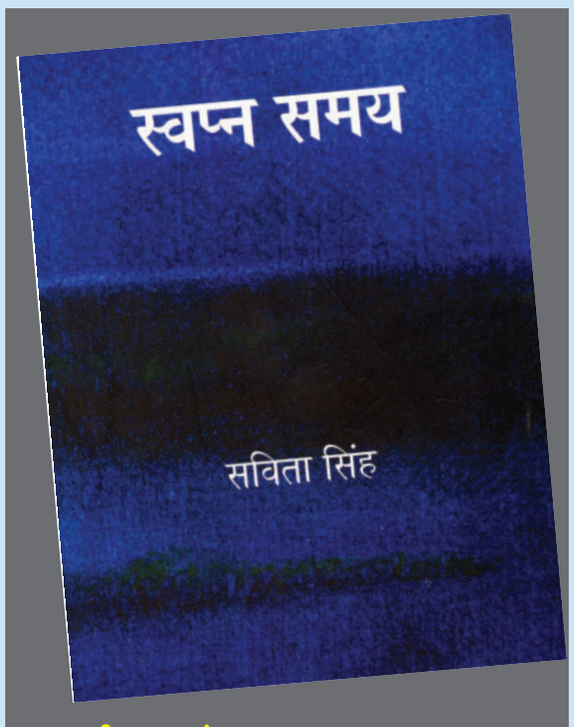

समीक्ष्य काव्य संग्रह : स्वप्न–समय
प्रकाशन : राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 250 रुपये

की खोज में/वह भी आया था मुझे खोजता/मैं ही विचलित हो देखने लगी थी दूसरी तरफ/मुस्कुराता हुआ वह निकल गया था उधर/जिधर भटकना था फिर मुझे वर्षों.'

स्त्री इस सृष्टि की अद्भुत रचना है, अगर ये न हो तो इस सृष्टि की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हैं, परंतु स्त्री और पुरुष में प्राकृतिक रूप से जो भिन्नता है, उसमें पुरुष वर्ग शारीरिक रूप से अधिक सशक्त होता है.' ईश्वर और स्त्री कविता में यही फर्क नज़र आता है– 'देखता होगा ईश्वर भी स्त्री के हाहाकार को/बदलने के लिए होगा उत्सुक अपनी ही कल्पना को/की बनाए नहीं वे पुरुष अब तक/ले सकें जो उसे बाहों में.'

स्त्री जबसे पैदा होती है, उसका संघर्ष शुरू हो जाता है, घर से लेकर बाहर तक उसका भिन्न–भिन्न रूपों में शोषण होता है, जिसे वह ताउम्र सहती है, उसकी आज़ादी पर पहरा पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है. परंपरा के नाम पर कितनी रूढ़ियों का पालन उन्हें अनचाहे करना पड़ता है, वह बाल–विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो या विधवा विवाह निषेध जैसी कोई प्रथा हो. इन कुप्रथाओं को रीति–रिवाज़ से जोड़कर विशेष तौर पर स्त्रियों पर थोपा गया, इन कुप्रथाओं में पुरुष यदि कहीं था भी तो उसका इस प्रकार से शोषण नहीं हुआ, जैसा कि स्त्रियों का. सविता सिंह की 'स्त्री मृत्यु के बाद' कविता में कुछ इस प्रकार से चित्रित होती हैं– 'तकलीफ उठाने की सचमुच/कैसी तमीज़ होती है औरतों में.' फिर आगे चलकर कहती हैं– 'हमारे पास जो अनुभव पराजय के/उनका किसी को ठीक–ठीक अंदाज़ा नहीं/रो लेते हैं रात के किस पहर हम/दिन के उजाले में कब उसको भी नकार देते हैं.' इसी कड़ी में संग्रह की वह कविता आती है, जिसके शीर्षक पर संग्रह को नाम दिया गया है . इस कविता 'स्वप्न–समय' में संगृहीत अधिकांश कविताओं का सार दिखाई पड़ता है. साथ ही स्त्री की तड़प, उसका रुदन, उसका स्वर, जिसमें वह चैन की नींद लेना भूल चुकी है. अब वह रात्रि में आने वाले स्वप्न में विचरण नहीं करना चाहती. अब उसे न रात चाहिए, न आंखें जो सपना देख सकें– 'चीत्कार और करुण पुकार से फिर शुरू होता है वह सब कुछ/जिसे हम जानते हैं/वह स्वप्न/जिसे न आंख चाहिए न रात.'■

feedback@chauthiduniya.com

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

> गूगल के हाल ही में जारी किए गए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट से गूगल ग्लास में नया फीचर जुड़ गया है. इंटरनेट से जुड़ा यह आई वेयर यूजर्स को ऐसी सुविधा देगा, जिससे यूजर एक पलक झपकाकर सामने की तस्वीरें खींच सकेंगे.

स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए भी पेन ड्राइव

यह पेन ड्राइव्स मोबाइल मल्टी-टास्किंग के लिए सबसे बेहतर हैं. सोनी की ये नई पेन ड्राइव्स एंड्रायड(ऑपरेटिंग सिस्टम आईसक्रीम सैंडविच से लेकर जेली बीन तक) ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं.

अभी तक स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कोई पेन ड्राइव नहीं आई थी, लेकिन सोनी ने दुनिया का पहली पेन ड्राइव लांच किया है, जिसे इनमें भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे. अब तक केवल कम्प्यूटर और लैपटॉप के डेटास्टोर के लिए ही पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता था. 2–इन–वन डिवाइस वाली यह पेन ड्राइव यूएसबी 2.0 और माइक्रोयूएसबी कनेक्टर दोनों के लिए है. यही नहीं स्मार्टफोन और टैबलेट के अलावा यूजर्स इसका इस्तेमाल कम्प्यूटर और लैपटॉप के लिए भी कर सकते हैं.

सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के उपभोक्ता मीडिया मार्केटिंग के डायरेक्टर विवियानो कांटू का कहना है कि ये पेन ड्राइव्स मोबाइल मल्टी–टास्किंग के लिए सबसे बेहतर हैं. सोनी की नई पेन ड्राइव एंड्रॉयड(ऑपरेटिंग सिस्टम आईसक्रीम सैंडविच से लेकर जेलीबीन तक) ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं. सोनी का कहना है कि वह गूगल के सबसे नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है. कंपनी का कहना है कि वह गूगल के सबसे नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 4.4(किटकैट) के लिए भी इस पेन ड्राइव को अनुकूल बना रही है. डेटा कॉपी करने के अलावा ये पेन ड्राइव स्मार्ट फोन और टैबलेट के लिए अतिरिक्त या टेंपरेरी स्टोरेज का काम भी करती है. तीन रंगों में उपलब्ध इस पेन ड्राइव के लॉकिंग कैप्स इन्हें धूल मिट्टी और टूटने से बचाएंगे. कंपनी ने बताया कि उसकी ये नई पेन ड्राइव्स 8जीबी, 16जीबी और 32जीबी में उपलब्ध है. जिनकी कीमत क्रमश: 1240.88, 1861.54 और 3909.92 रुपये हैं. हालांकि जापान की कंपनी सोनी ने भारत में इन पेन ड्राइव की लॉचिंग के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी. ■

इसुजु मोटर्स की कार अब भारत में

एमयू–7 भारत में लॉन्च होने वाली इसुजु मोटर्स की पहली कार है. इसका निर्माण हिंदुस्तान मोटर्स के संयंत्र में किया गया है. कंपनी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शिगेरू वाकाबायाशी ने बताया कि कंपनी 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में निर्माण संयंत्र बना रही है.

इसुजु मोटर्स ने भारत में अपनी पहली कार लॉन्च की है जो कि हिन्दुस्तान मोटर्स की एंबेस्डर कार के लिए डीजल इंजन की सप्लाई करती है. एमयू–7 भारत में लॉन्च होने वाली इसुजु मोटर्स की पहली कार है. इसका निर्माण हिंदुस्तान मोटर्स के संयंत्र में किया गया है. कंपनी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शिगेरू वाकाबायाशी ने बताया कि कंपनी 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में निर्माण संयंत्र बना रही है.

कंपनी ने कहा कि यहां खास तौर पर लाइट कॉर्मियल वाहनों और स्पोर्ट्स वाहनों का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम 2016 तक पूरा हो जाएगा. एमयू–7 कार का निर्माण पहले की तरह हिंदुस्तान मोटर्स के संयंत्र में ही होगा. कंपनी यहां से प्रत्येक साल 5,000 कारों का निर्माण कराएगी. अपने डी–मैक्स पिक–अप ट्रक के बारे में वाकाबायाशी ने कहा कि इसकी भार वहन क्षमता टाटा जेनॉन और महिंद्रा जेनियो के बराबर होगी. कंपनी ने अभी दक्षिण भारत के बाजारों पर ही ध्यान केंद्रित किया है. इसके कारण ही हैदराबाद, चेन्नई और कोयंबटूर में शोरूम खोले गए हैं. कंपनी अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक मुंबई दिल्ली में भी शोरूम खोलना चाहती है. अनुमान है कि एमयू–7 की शोरूम कीमत लगभग 22.3 लाख रुपये होगी. ■

इंतजार खत्म आया ड्यूल सिम नोकिया आशा 502

नोकिया ने ड्यूल सिम वाला नोकिया आशा 502 को लॉन्च कर दिया है. इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो नोकिया स्टोर पर आसानी उपलब्ध हो जाएगा. इस फोन की कीमत 5739 रुपये है. इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 5 एमपी का कैमरा है. इसमें कैमरे का फोकस फिक्स्ड रहता है, जिससे यूजर्स को आसानी होगी. इसकी टच स्क्रीन तीन इंच की है. ये फोन नोकिया के डेवेलप किए गए आशा 1.1 प्लेटफॉर्म पर चलता है. इस फोन में 64 एमबी की रैम है. माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है. नोकिया आशा 502 में फेसबुक,ट्विटर, लिंकडिन, वीचैट जैसे कई पॉपुलर एप्स हैं, लेकिन इसमें व्हाट्स एप इन बिल्ट नहीं है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है. आशा 502 एक फीच फोन है इसमें थ्री जी नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता. फोन 2 जी नेटवर्क पर ही चल सकता है.

2जी और वाई फाई दोनों पर चलता है इसके अलावा वाई फाई पर भी फोन चलाया जा सकता है. आशा 502 में 1010 एमएएच की बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह फोन लगातार बात करने पर 13.7 घंटे तक चल सकता है. स्टैंडबाई मोड में फोन 24 दिन तक चल सकता है. आशा 502 कुल छह कलर्स में उपलब्ध है. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और व्हाइट. ■

आ गई सुजुकी इनाजुमा जीडब्ल्यू 250

कंपनी अपनी दो नई पॉवरफुल बाइक्स भारत में लॉन्च करने जा रही है. इसमें सुजुकी इनाजुमा जीडब्ल्यू 250 भी शामिल होगी. कंपनी ने इनाजुमा जीडब्ल्यू 250 का भारत में परीक्षण का काम पूरा कर लिया है.

टू व्हीलर्स के लिए प्रचलित कंपनी सुजुकी अपने नए मॉडल इनाजुमा जीडब्ल्यू 250 को बहुत जल्द भारत में लॉन्च करेगी. कंपनी इस बाइक की कुछ महीनों से भारत में परीक्षण कर रही थी. कंपनी अपनी दो नई पॉवरफुल बाइक्स भारत में लॉन्च करने जा रही है. इसमें सुजुकी इनाजुमा जीडब्ल्यू 250 भी शामिल होगी. कंपनी ने इनाजुमा जीडब्ल्यू 250 का भारत में परीक्षण का काम पूरा कर लिया है. यह 247 सीसी की बाइक है. इसका फ्यूल-इंजेक्टेड पैरलल्ड ट्विन मोटर इंजन 26 बीएचपी का पावर व 24.4 एनएम का टॉर्क देता है. साथ ही इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी है. कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है, जिसका अभी लॉन्च होने तक इंतजार करना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

सभी बाइकों की कर देगी छुट्टी

बजाज ऑटो ही एक ऐसी कंपनी है जो भारत में एक लाख रुपये से कम कीमत की क्रूजर बाइक की बिक्री करती है.

बाइक की जानी मानी कंपनी बजाज आटो की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है. कंपनी पहले नंबर दो की पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन अब नंबर दो की पोजीशन पर होंडा पहुंच गई है. अब बजाज इसे देखते हुए और अपनी बादशाहत कायम करने के लिए बजाज ऐसी दमदार बाईक को लॉन्च कर सकती है, जो कंपनी को उसकी जगह दोबारा दिला सके. राजीव बजाज ने पहले साफ कर दिया है कि कंपनी बाइक पर अब अधिक ध्यान देगी. कंपनी अपनी दोबारा जगह वापस पाने के लिए नई क्रूजर लॉन्च करेगी. बजाज ऑटो ही एक ऐसी कंपनी है जो भारत में एक लाख रुपये से कम कीमत की क्रूजर बाइक की बिक्री करती है. कंपनी की एवेंजर 220(एवेंजर 220डीटीएस–आई) बाइक कीमत 79.47 रुपये है, बाजार में उपलब्ध रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 और 500 की कीमत एवेंजर की तुलना में काफी अधिक है. बजाज इस कीमत को पूरा करने के लिए अपनी नई क्रूज बाइक लॉन्च कर सकती है जो आने वाले ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित भी की जा सकती है. कंपनी इस बाइक को अलग–अलग इंजन पॉवर के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके बेस मॉडल की कीमत लगभग एक लाख रुपये होगी.■

पलक झपकते ही फोटो खीचेंगा गूगल ग्लास

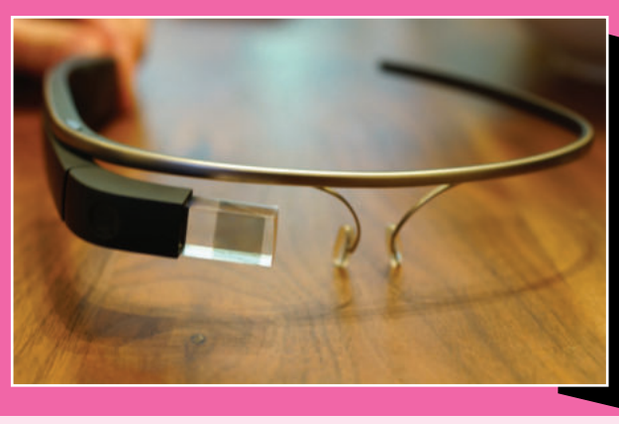

गूगल ने अपने फ्यूचरिस्टिक आई वेयर ग्लास के लिए नया सॉफ्टवेयर ईजाद किया है. गूगल ग्लास को प्रयोग करने वाले अब एक पलक झपकाकर ही तस्वीरें खींच सकते हैं.

गूगल के हाल ही में जारी किए गए सॉफ्टवेयर अपडेट से गूगल ग्लास में नया फीचर जुड़ गया है. इंटरनेट से जुड़ा यह आई वेयर यूजर्स को ऐसी सुविधा देगा, जिससे यूजर एक पलक झपकाकर सामने की तस्वीरें खींच सकेंगे. गूगल प्लस पर गूगल ग्लास की तरफ से डाली गई पोस्ट में कहा गया है कि हमने नई सेटिंग्स की है. अब आप गूगल ग्लास के माध्यम से पलक झपकाकर (विंक करके) आसानी से लम्हों को कैद कर सकते हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि अभी तो हम तस्वीरें खींचने से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे इससे बहुत कुछ किया जा सकेगा. नए अपडेट में यूजर्स को यह सुविधा भी दी गई है कि वे अपने ग्लास को लॉक कर सकें.

गूगल ने ग्लास से यू–ट्यूब पर डायरेक्ट विडियो अपलोड करने समेत कई सारे अपडेट्स किए हैं. अभी और भी कई सारे अपडेट्स पर काम किया जा रहा है.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> 2016 में रियो डी जिनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए जेम्स ग्लॉफर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं. गौरतलब है कि उसैन बोल्ट ने 2009 की बर्लिन विश्व चैंपियशिप में 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकेंड में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था.

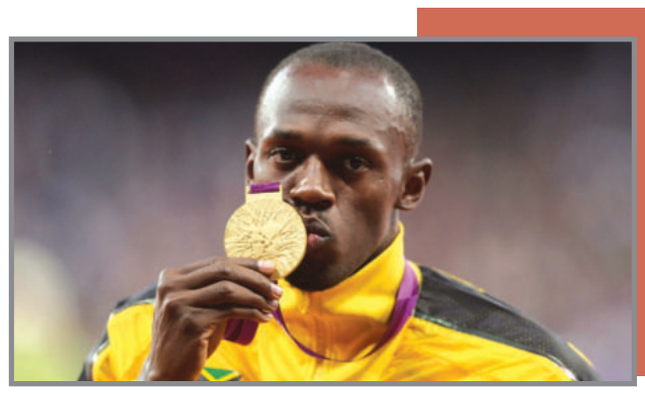

विराट के प्रशंसक बने डोनाल्ड

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज विराट कोहली के लगातार अच्छे प्रदर्शन से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने पहले टेस्ट में विराट की शतकीय पारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि विराट ने मुझे सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी. डोनाल्ड कहते हैं कि जब टीम इंडिया 1996 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर आई थी, तब मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारतीय टीम में दम नहीं है, उस दौरे में सचिन ही थे, जिन्होंने उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया. विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 181 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 119 रनों की पारी खेली. डोनाल्ड का कहना है कि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना हमेशा जिम्मेदारी भरा होता है. विराट ने हमेशा की तरह अपनी पारी के दोरान अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ खेला. उसकी पारी देखकर मुझे सचिन की पारी याद आ गई.

सचिन ने भी 1996 में केपटाउन में खलते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी. एलन डोनाल्ड इस समय दक्षिण अफ्रीका टीम के गेंदबाज कोच हैं. एक समय था जब सचिन और डोनाल्ड का रोचक मुकाबला देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में बहुत उत्सुकता रहती थी. डोनाल्ड ने अफ्रीका की तरफ से 72 टेस्ट में 330 विकेट लिए, वहीं 164 वनडे मैंचों में 272 विकेट चटकाए.■

धोनी का नया रिकॉर्ड

धोनी का कप्तान के तौर पर यह 50वां मैच था. 50 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले धोनी भारत के पहले कप्तान हैं. इस मामले में उनका एशिया में दूसरा और दुनियाभर में 14वां स्थान है. एशिया में सबसे अधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा के नाम है. रणतुंगा ने 56 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है.

सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी

50 एमएस धोनी
49 सौरव गांगुली
47 मुहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर
40 मंसूर अली खान पटौदी
34 कपिल देव

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कप्तानी करने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के टेस्ट मैचों में सबसे अधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए. टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड बनाने वाले

अमला ने रिचर्डस को पछाड़ा

हाशिम अमला ने सर विवियन रिचर्ड्स के वनडे मैचों में 4000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अमला ने कहा कि उन्हें रिचर्ड्स के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद अजीब लग रहा है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने महानतम खिलाड़ी रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. डरबन में अमला ने शतकीय पारी के दौरान 59 वां रन बनाते ही महान कैरिबियाई बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अमला ने 81 मैचों में 4000 रन पूरे किए हैं. वहीं रिचर्डस ने 88 मैचों में यह रिकॉर्ड कायम किया था. अमला ने सात मैचों से पहले ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अमला ने कहा इस रिकॉर्ड को लेकर मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने सर विवि का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि असली मास्टर ब्लास्टर हैं और महानतम ब्लेबाज हैं. वे हर लिहाज से मुझसे ही नहीं किसी से भी अधिक इसके हकदार हैं. मैं भाग्यशाली हूं कि उनसे कई बार मिलने का मौका भी मिला है. यदि वे आगे रहते तो यह फिट बैठता. अब वनडे क्रिकेट अधिक होने लगा है, इसलिए आराम से कोई न कोई इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा.■

> अमला ने 81 मैचों में 4000 रन पूरे किए हैं. वहीं रिचर्डस ने 88 मैचों में यह रिकॉर्ड कायम किया था. अमला ने सात मैचों से पहले ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अमला ने कहा इस रिकॉर्ड को लेकर मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने सर विवि का रिकॉर्ड तोड़ा है.

धोनी टेस्ट टीम में रहने योग्य नहीं: अमरनाथ

> अमरनाथ ने कहा कि धोनी को बाहर बैठना चाहिए. उन्होंने तमाम युवा विकेटकीपरों की जगह रोक रखी है. अमरनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि धोनी कौन होते हैं, यह कहने वाले कि वह टीम में रहेंगे और कप्तानी करते रहेंगे? उन्होंने आखिर किया क्या है?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चयनकर्ता एवं क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को निशाने पर लेते हुए धोनी को कप्तान तो दूर टेस्ट में भी रहने लायक नहीं बताया है. अमरनाथ ने कहा कि धोनी को बाहर बैठना चाहिए. उन्होंने तमाम युवा विकेटकीपरों की जगह रोक रखी है. अमरनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि धोनी कौन होते हैं, यह कहने वाले कि वह टीम में रहेंगे और कप्तानी करते रहेंगे? उन्होंने आखिर किया क्या है? वह टेस्ट टीम में रहने लायक नहीं हैं. देश में उनसे बेहतर विकेटकीपर और बल्लेबाज मौजूद हैं. उन युवा खिलाड़ियों को इसलिए मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि धोनी कप्तान हैं. अमरनाथ के अलावा पूर्व खिलाड़ी व मुख्य चयनकर्ता के श्रीकांत और दिलीप वेंगसरकर भी धोनी की टीम में जगह को लेकर सवाल उठा चुके हैं. अमरनाथ ने धोनी की टेस्ट टीम में जगह को लेकर बात करते हुए कहा कि पिछले एक साल से वह भारतीय टीम की कप्तानी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत उनकी अगुवाई में वनडे विश्व कप जीता था, लेकिन यहां मुद्दा टेस्ट क्रिकेट का है. ■

बोल्ट से भी तेज दौड़ता है ग्लाफर

> बोल्ट को पछाड़ने वाले 14 वर्षीय जेम्स ग्लॉफर न्यू साउथ वेल्स के साउथ कोस्ट क्षेत्र का रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने यह रिकॉर्ड टाउंसविले में इस वीकेंड में हुई दौड़ में बनाया.

अगर आप यह मानते हैं कि उसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज धावक हैं तो आप गलत है. जी हां, एक 14 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के ने बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलियाई न्यू साउथ वेल्स के साउथ कोस्ट के एक छात्र ने 200 मीटर की दौड़ को मात्र 21.73 सेकेंड में पूरी कर अपने आयु वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. उसका प्रदर्शन वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बोल्ट से बेहतर था. उसने उसैन बोल्ट द्वारा 14 साल की उम्र में बनाए रिकॉर्ड से 0.08 सेकेंड का बेहतर समय निकाला. बोल्ट को पछाड़ने वाले 14 वर्षीय जेम्स ग्लॉफर न्यू साउथ वेल्स के साउथ कोस्ट क्षेत्र का रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने यह रिकॉर्ड टाउंसविले में इस वीकेंड में हुई दौड़ में बनाया. 2016 में रियो डी जिनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए जेम्स ग्लॉफर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं. गौरतलब है कि उसैन बोल्ट ने 2009 की बर्लिन विश्व चैंपियशिप में 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकेंड में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई धावक नहीं तोड़ पाया. इसके अलावा, इसी चैंपियनशिप में 200 मीटर की रेस में बोल्ट ने 19.19 सेकेंड का समय निकालाते हुए रिकॉर्ड बनाया था, जो आजतक कायम है. ■

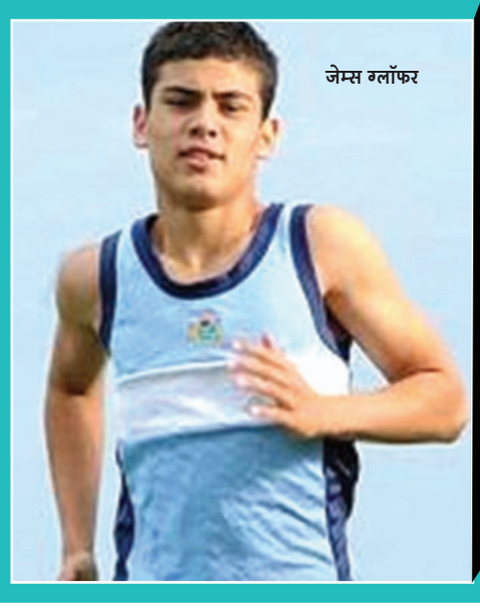
जेम्स ग्लॉफर

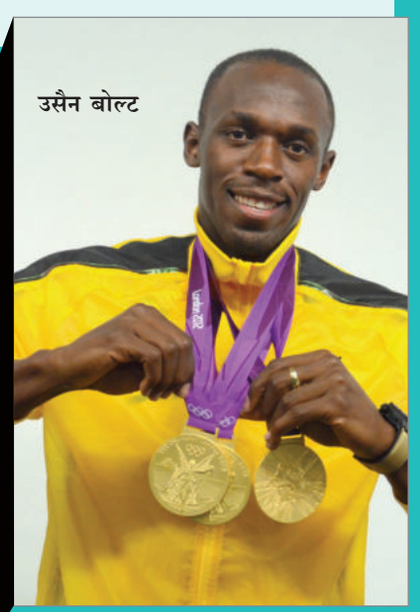
उसैन बोल्ट

खेल के मैदान में मौत

पाकिस्तान के एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी की बैटिंग करते वक्त सीने पर गेंद लग जाने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद सिंध प्रांत के तीसरे सबसे बड़े शहर सुक्कुर में सभी खेल गतिविधियों को तीन दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. सुक्कुर में क्लब क्रिकेट के दौरान यह हादसा 22 साल के खिलाड़ी जुल्फिकार भट्टी के साथ हुआ. यहां के जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सुपर स्टार क्लब और सिंध यंग्स क्लब के बीच खेले जा रहे मैच के दरमियान एक शॉर्ट पिच गेंद भट्टी के सीने पर लग गई. गेंद लगते ही वह पिच पर गिर पड़े. इसके बाद साथी खिलाड़ियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. भट्टी का सपना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का था, लेकिन उनका यह सपना पूरा न हो सका. इसके पहले भी कई क्रिकेट खिलाड़ियों की मैदान में मौत हो चुकी है. 1998 में पूर्व भारतीय खिलाड़ी रमन लांबा की फील्डिंग के दौरान सिर पर गेंद लगने की वजह से मौत हो गई थी. लांबा को फार्वर्ड शॉट लेग में फील्डिंग करते समय सिर पर गेंद लगी थी. 2013 में ही इस तरह के एक और हादसे में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जॉन रेंडल की मौत हो गई थी. रैंडल के सिर पर बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

प्रभुदेवा-रामलथ-नयनतारा

प्रभुदेवा ने एक मुस्लिम युवती रामलथ से शादी की थी. उन दोनों से तीन बच्चे हुए. 2008 में प्रभु के बड़े बेटे की कैंसर से मौत हो गई. प्रभु को अभिनेत्री नयनतारा से प्यार हो गया. उनकी पत्नी ने अभिनेत्री नयनतारा से उनके लिव-इन-रिलेशन को लेकर फैमिली कोर्ट में एक याचिका भी डाली थी और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले कुछ संगठन के साथ मिलकर भूख हड़ताल भी किया. बाद में उनकी पत्नी ने आखिर तलाक दे दिया. नयनतारा इसाई हैं और उनका असली नाम डायना मरियम कुरियन है. उन्होंने हिंदू धर्म अपना कर प्रभु से शादी कर ली.

कितने अजीब रिश्ते हैं यहां पर...

बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं, जिनके रियल लाइफ अफेयर भी किसी फिल्म की कहानी से कम मजेदार नहीं है. ये कपल्स मजहब-जाति और उम्र की दीवारों को लांघ कर एक-दूसरे से प्यार किए और उस प्यार को पाने के लिए वर्षों इंतजार किए, पर अफसोस प्यार के कुछ खूबसूरत अफसाने लिखने के बाद अलगाव की राह पर वे चल पड़े. लाखों दिलों की धड़कन रितिक रोशन की शादी टूटने से पूरा बॉलीवुड सन्न रहा गया, क्योंकि उन्हें एक आदर्श कपल के रूप में देखा जा रहा था. उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्म की कहानी से कम दिलचस्प नहीं है. ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों ने एक-दूसरे को देखा और दोनों में प्यार हो गया. उनकी प्रेम कहानी कई सालों तक चली, फिर दोनों ने शादी कर ली. पूरे 13 साल के रिलेशन और दो प्यारे बच्चों के माता-पिता रितिक और सुजैन अलग हो गए. हालांकि बॉलीवुड में ऐसे और भी कई कपल्स हैं, जिन्होंने प्यार किया और फिर शादी की. जिंदगी का एक खूबसूरत सफर मिलकर तय किया और फिर अलग हो गए. हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही कपल्स के बारे में.

रणवीर शौरी-कोंकणा सेन शर्मा

कोंकणा सेन शर्मा को रणवीर शौरी से 2007 में प्यार हुआ और 2010 में दोनों ने शादी कर ली. 2011 में दोनों को एक बेटा हुआ. बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद दोनों में विवाद होने लगा और दोनों अलग रहने लगे.

धर्मेंद्र-प्रकाश कौर-हेमा मालिनी

धर्मेंद्र शादी करने के बाद फिल्मों में आए थे. उनकी पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें दो बच्चे भी हैं. सन्नी देओल और बॉबी देओल. इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें मीना कुमारी से प्यार हुआ, लेकिन मीना की शादी पहले ही कमाल अमरोही से हो चुकी थी. फिर उन्हें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से प्यार हुआ. हेमा और धर्मेंद्र फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान करीब आए. हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र प्रकाश को तलाक देना चाहते थे, लेकिन प्रकाश ने मना कर दिया. तब धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर हेमा से शादी की. इसके लिए उन्होंने समाज ही नहीं, परिवार का भी विरोध सहा.

मेड फॉर इच अदर कहे जाने वाले रितिक और सुजैन अलग हो गए हैं. इसी दौरान उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया. वह मीडिया से भी रूबरू हुईं और कहा कि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है. इस मौके पर कई सितारे पहुंचे. अर्जुन रामपाल भी अपनी पत्नी मेहर के साथ वहां पहुंचे. सुजैन अपनी दोस्ती अब बॉलीवुड के खान्स से बढ़ा रही हैं तो वहीं रितिक और अपने कॉमन फ्रेंड्स से दूरियां भी बना रही हैं.

जीनत अमान-संजय खान-मजहर खान

जीनत अमान बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकत संजय खान (सुजैन के पिता) से हुई. दोनों में प्यार हुआ और कहा जाता है कि दोनों ने शादी भी की, जबकि संजय की शादी पहले ही ज़रीन से हो चुकी थी. बाद में संजय और जीनत का रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि संजय उनके साथ मारपीट तक करने लगे. दोनों अलग हो गए, फिर जीनत ने मजहर खान से शादी की. उनके दो बच्चे भी हुए. मजहर और जीनत के संबंध भी अच्छे नहीं थे. मजहर भी उनके साथ काफी मारपीट करते थे. परेशान जीनत ने मजहर से भी तलाक ले लिया.

कमल हसन-सारिका ठाकुर

चौबीस साल की उम्र में कमल हसन ने अपने से बड़ी उम्र की डांसर वाणी गणपति से शादी की. करीब दस साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. वजह सारिका थीं. कमल और सारिका ने 1988 में शादी कर ली. उन्हें दो बेटियां हुईं. शादी के बाद सारिका ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया. 2004 में सारिका ने भी कमल हसन से तलाक ले लिया. अलगाव की वजह कमल से बाईस साल छोटी अभिनेत्री सिमरन बग्गा थीं. बाद में सिमरन ने अपने बचपन के दोस्त से शादी रचा कर ली. अब कमल पूर्व अभिनेत्री गौतमी तडिमल्ला के साथ 2005 से रह रहे हैं.

संजय दत्त-रिया पिल्लई

पहली पत्नी रिचा की कैंसर से मौत और कई अफेयर्स के बाद संजय को सहारा दिया सामाजिक कार्यकर्ता और मॉडल रिया पिल्लई ने. जब संजय 13 महीनों के लिए जेल गए, तब रिया उनसे मिलने बार-बार जेल जाती थीं. जेल से छूटने के बाद संजय ने 1998 में रिया से शादी कर ली, लेकिन दोनों 2005 में अलग हो गए. बाद में रिया ने टेनिस स्टार लिएंडर पेस से शादी कर ली. संजू की जिंदगी में ऐंट्री हुई जूनियर आर्टिस्ट नादिया दुर्रानी की. तलाकशुदा और 9 साल की बेटी की मां नादिया के इश्क में संजय डूब गए थे. कहा जाता है कि नादिया की वजह से ही रिया ने संजय को छोड़ा था. हालांकि जल्द संजू नादिया से अलग हो गए और मान्यता से शादी कर ली.

पंकज कपूर-नीलिमा अजीम-सुप्रिया पाठक

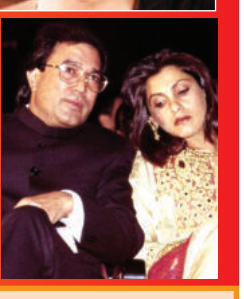

नीलिमा अजीम ने एक्टर पंकज कपूर से शादी की. इनके बेटे शाहिद कपूर हैं. दोनों दस साल तक साथ रहे, पर बाद में पंकज ने नीलिमा को तलाक दे दिया और सुप्रिया पाठक के साथ दूसरी शादी कर ली, जबकि नीलिमा ने राजेश खत्तर से शादी की. 2001 में दोनों का तलाक हो गया. उन्होंने तीसरी शादी बड़े गुलाम अली खान के ग्रैंड सन उस्ताद रजा अली खान से की.

राजेश खन्ना-डिंपल कपाड़िया

उम्र में काफी छोटी डिंपल से राजेश खन्ना ने शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनमें अहम को लेकर टकराव शुरू हो गया. इस बीच दो बेटियों का जन्म भी हुआ, लेकिन दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों ने स्वेच्छा से अलग हो जाना ही बेहतर समझा.

मनीषा कोईराला-सम्राट दहल

बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नेपाली बाला मनीषा कोइराला ने सात साल छोटे सम्राट दहल से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता खराब होने लगा. मनीषा ने यहां तक कहा कि उनका पति, पति नहीं जल्लाद है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन है. मनीषा ने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट से 19 जून, 2010 में शादी की. बाद में दोनों ने तलाक ले लिया.

राज बब्बर-नादिरा बब्बर

नादिरा और राज बब्बर की मुलाकात तब हुई, जब राज बब्बर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई कर रहे थे. वर्षों की मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी कर ली. दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे. राज और नादिरा के दो बच्चे भी थे और तभी उन्हें स्मिता पाटिल से प्यार हो गया. राज ने स्मिता से शादी करने के लिए नादिरा को छोड़ दिया, पर स्मिता की मौत के बाद वह नादिरा के पास वापस लौट आए.

अनुराग कश्यप-आरती बजाज-कल्की कोचलीन

बॉलीवुड के चर्चित डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुलाकत दिल्ली में कॉलेज के दिनों में आरती से हुई थी. उनका प्रेम वर्षों चला, फिर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए. दोनों की एक बेटी है आलिया. बाद में दोनों अलग हो गए और अनुराग ने कल्की कोचलिन से शादी कर ली. उनकी शादी 30 अप्रैल, 2011 को ऊटी में हुई थी. कल्की उम्र में उनसे लगभग 12 साल छोटी थीं, पर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों सहमति से अलग हो गए.

सैफ अली खान-अमृता सिंह

सैफ अली खान ने अपने से लगभग 12 साल बड़ी अमृता से शादी की. शादी के कुछ साल काफी अच्छे से गुजरे. फिर सैफ के अफेयर्स की खबरें भी आईं. आखिर दोनों का अलगाव हो गया. अमृता और सैफ ने अलग होने के कारणों को कभी सार्वजनिक नहीं किया और गरिमामय खामोशी बनाए रखी. उनके दो बच्चे भी हैं. सैफ बाद में करीना के साथ लिव-इन में रहने लगे. अब दोनों शादी कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

आमिर खान-रीना दत्त

रीना दत्त और आमिर खान पड़ोसी थे. उन्होंने लव मैरिज किया और घरवालों को भी नहीं बताया. खुशी-खुशी उनका रिश्ता 16 साल तक चला. फिल्म लगान के सेट पर आमिर खान को किरण राव से प्यार हो गया. किरण को पाने के लिए आमिर ने अपनी पत्नी रीना को तलाक दे दिया.

रणधीर कपूर-बबिता

कपूर खानदान के बड़े बेटे रणधीर कपूर से बबिता ने शादी की. रणधीर एक गैर जिम्मेदार पति थे और शराब की लत भी थी उन्हें. तंग आकर बबिता उनसे अलग रहने लगीं. हालांकि दोनों में तलाक नहीं हुआ. और आज भी पारिवारिक आयोजनों पर रणवीर भी साथ दिखते हैं.

प्रीव्यू

मिस्टर जॉय बी कारवाल्हो

डायरेक्टर	:	समीर तिवारी
प्रोड्यूसर	:	शीतल मालवीय एवं भोला राम मालवीय
कहानी	:	महेश रामाचंदानी
कलाकार	:	अरशद वारसी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी, विजय राज, शक्ति कपूर, रंजीत, हिमानी शिवपुरी, कुणाल खेमू.
गेस्ट अपियरेंस	:	गीता बसरा, करिश्मा कोटक एवं कुणाल खेमू.
डिस्ट्रीब्यूटेड बाई	:	बीआर एंटरटेनमेंट
भाषा	:	हिंदी
रिलीज डेट	:	3 जनवरी, 2014
बजट	:	150 मिलियन

समीर तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल मालवीय और भोला राम मालवीय ने. फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अरशद वारसी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी और विजय राज. फिल्म में गीता बसरा और करिश्मा कोटक का गेस्ट अपियरेंस भी है. इसमें आपको बाबुल सुप्रियो के गाने भी सुनने को मिलेंगे. इस फिल्म में अरशद वारसी एक जासूस की भूमिका में हैं, जबकि सोहा अली खान एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. लेकिन इसमें वह कई रूपों में दिखेंगी. इस फिल्म में वह पुलिस ऑफिसर, कैबरे डांस में और अप्सरा के रूप में दिखेंगी. सोहा ने इस फिल्म में पहली बार बिकनी भी पहना है. अरशद वारसी ने फिल्म में एक गाना भी कोरियोग्राफ किया है. अरशद के किरदार का नाम इस फिल्म में कार्लोस का है. इस फिल्म की शूटिंग गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में किया गया है. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

30 दिसंबर 2013–05 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

सीएम अखिलेश और उद्योगपतियों के बीच बनी बात

स्पीड ब्रेकर हटे, मिलेगी विकास को गति

चार राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश की लगभग हर पार्टी भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन से घबरा गई है. सपा नेतृत्व भी भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की बेदाग छवि को देखते हुए अपने युवा मुख्यमंत्री की साफ–सुथरी विकासवादी छवि को उकेरने में लग गया है. यही कारण है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना में उत्तर प्रदेश में पिछले 18 महीनों में ज्यादा जनोपयोगी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया.

अजय कुमार

चार बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की आंखे खोल दी हैं. उन्हें लगने लगा है कि वोट बैंक के तिलिस्म को बनाए रखने के लिए राजनीति और विकास नीति के शास्त्र को समझना जरूरी है. भले ही वोट बैंक की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल कर ली जाए, लेकिन जातिवाद के झमेले में ज्यादा समय तक जनता को उलझाया नहीं जा सकता है. जनता तभी खुश रहेगी, जब मंहगाई, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा. जनहित और विकास की बात होगी. सपा ने जिस प्रकार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की बेदाग छवि को उभारकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाबी हासिल की थी. इसे वह भले ही सत्ता हासिल करने के बाद कुछ समय के लिए भूल गई थी, लेकिन ऐसा लम्बे समय तक नहीं हो पाया. चार राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सपा नेतृत्व एक बार फिर अपने युवा मुख्यमंत्री की साफ–सुथरी विकासवादी छवि को उकेरने में लग गया है. लोकसभा चुनाव में भी सीएम अखिलेश की यही छवि जनता के सामने रखने की कार्ययोजना तैयार करने में सपा जुटी है. समाजवादी रणनीतिकार सपा की नई सोच को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत और विकासशील छवि से जोड़कर देख रहे हैं. दोनों की लोकप्रियता ने उनको दोबारा सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी. बीते दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों क्रमश: शिवराज सिंह चौहान और डॉ. रमन सिंह को मिली सफलता के पीछे उनकी बेदाग छवि ही रही है. भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सत्ता जनित कई और समस्याओं से दोनों सरकारें पूरे कार्यकाल के दौरान जूझती रही हैं.

भाजपा शासित उक्त राज्यों में जनता से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो दोनों प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में पिछले 18 महीनों में ज्यादा जनोपयोगी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया, लेकिन पार्टी इस बात का ढिंढोरा वैसे नहीं पीट पाई, जैसे की पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और इसके बाद रमन–शिवराज ने पीटा. मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने जनता से किए गए एक–एक वादे को ईमानदारी पूर्वक पूरा करने में अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाया. बात चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की हो या फिर कन्या विद्याधन, छात्रों को लैपटॉप की योजना हो. सभी समय से आगे बढ़ीं. ऐसी ज्यादातर योजनाओं को अखिलेश सरकार तेजी से पूरा करते दिख रही है. विधान सभा चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने के क्रम में सपा सरकार के पिछले 18 महीनों के कामकाज को मुख्य रूप से फोकस किया जा सकता है. सपा सरकार की ऐसी भी तमाम योजनाएं हैं, जिन्हें दूसरे राज्यों ने अपनाया.

अखिलेश सरकार ने इन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया, जो यह कहते घूमते रहते हैं कि सपा राज में औद्योगिक घराने यहां अपना पैसा निवेश करने से डरते हैं. हाल में ही 15,765 करोड़ की आठ औद्योगिक परियोजनाओं पर सरकार और उद्योगपतियों के बीच समझौता होना और तुरंत ही इन परियोजना के लिए भूमि आबंटित करके अखिलेश सरकार ने मिसाल कायम कर दी. किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जमीन की होती है. खासकर तब यह मसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब किसानों का रुख ऐसी परियोजनाओं के लिए सकारात्मक नहीं रहता है. राज्य सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए जमीन आबंटित करके अच्छा काम किया है. इससे प्रदेश में निवेश को इच्छुक अन्य उद्योगपतियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री अखिलेश कहते हैं कि समाजवादी सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रही है. सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप माहौल में बदलाव आया है. राज्य सरकार ने अलग–अलग क्षेत्रों के लिए नवीन नीतियां बनाकर इन्हें लागू किया, जिनसे प्रभावित होकर उद्यमी प्रदेश

में उद्योग स्थापना के लिए आ रहे हैं. प्रदेश में विकास की गंगा बहाने को ललायित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत दिनों यू.पी.एस.आई.डी.सी. तथा टी.एच.डी.सी. इंडिया लि. एवं जगदीशपुर पेपर मिल के अधिकारियों के बीच क्रमश: तापीय विद्युत संयंत्र तथा पेपर मिल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करके ओर औद्योगिक इकाइयों एवं 1 तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि के आबंटन पत्र उद्यमियों को प्रदान करके बता दिया कि वह बातों के बताशे नहीं बना रहे हैं. वह कहते हैं कि समाजवादी सरकार प्रदेश के विकास व जनता की खुशहाली के पक्ष में है. क्षेत्र का भेदभाव किए बगैर राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश का संतुलित विकास चाहती है. इसको देखते हुए रायबरेली में एम्स तथा होटल प्रबन्धन संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई. केन्द्र सरकार के मंत्रियों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए भी राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराई है. अमूल जैसे उद्यम को लेकर कोई राजनीति नहीं किए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अमूल की स्थापना न तो एक दिन में हुई और न ही इसे किसी एक सरकार ने बनाया.

श्री यादव का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि उद्योगों की स्थापना और किसानों की खुशहाली से प्रदेश का विकास सम्भव है. उद्योगों के जरिये लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होता है. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि मेट्रो रेल पर काम शुरू किया गया है. धनराशि का इंतजाम किया जा रहा है. आगरा इनर रिंग रोड परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से करने का फैसला लिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में अन्य उद्यमी भी प्रदेश में निवेश करेंगे. पराग द्वारा दुग्ध उत्पादकों को वितरित की जाने वाली धनराशि का व्यय वेतन मद में किए जाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने प्रकरण की जांच के निर्देश दिए.

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र वाजपेई सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि प्रदेश सरकार की नई नीतियों के माध्यम से राज्य की खुशहाली और औद्योगीकरण का रास्ता प्रशस्त हुआ है. पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 5 प्रतिशत थी. कृषि के क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 प्रतिशत था. सेवा सेक्टर प्रदेश में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 6.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई. प्रदेश में औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 0.5 प्रतिशत कम रही. ऐसा इसलिए था, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में बिगड़ी हुई स्थिति को पटरी पर लाने में वक्त लगा और इसका वर्तमान सरकार से कोई लेना–देना नहीं है. यह पिछली नीतियों का प्रभाव था.

इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यू.पी.एस.आई.डी.सी. प्रदेश के औद्योगीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है. प्रदेश के विकास के लिए पूंजी निवेश को बढ़ा कर औद्योगीकरण किया जाना आवश्यक है. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की औद्योगिक विकास दर 11.2 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसे हासिल करने के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाई गई हैं, जिनके जरिये उद्यमी निवेश के लिए आकर्षित होंगे और प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा. प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास व अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु डॉ. सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि नई औद्योगिक नीति से उद्योगपतियों को विश्वास हो गया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां औद्योगीकरण की व्यापक सम्भावना मौजूद है.

ज्ञातव्य है कि एम.ओ.यू. एवं प्रदान किए गए आबंटन पत्रों के क्रम में स्थापित होने वाली इकाइयों से 15765.70 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इनमें से 10,270 करोड़ रुपये का निवेश तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, 1540.70 करोड़ रुपये सीमेंट उत्पादन तथा 3700 करोड़ रुपये कागज उत्पादन में निवेश होगा. इसी प्रकार 140 करोड़ रुपये दुग्ध उत्पादन, 105 करोड़ रुपये मक्का प्रसंस्करण तथा 10 करोड़ रुपये का निवेश प्लास्टिक तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में होगा. विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इन परियोजनाओं से लगभग 29,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

टी.एच.डी.सी. इंडिया लि. द्वारा खुर्जा में 10,270 करोड़ रुपये की लागत से तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा 1200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का समझौता सम्पन्न हुआ. इस परियोजना से 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा में हिन्दुस्तान पेपर मिल की सहायक इकाई, जगदीशपुर पेपर मिल्स लि. के पक्ष में भूमि आबंटन के लिए समझौता किया गया. इस इकाई में लगभग 3700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. औद्योगिक क्षेत्र उमरदा, कन्नौज में 30 एकड़ भूमि पर 105 करोड़ रुपये की लागत से मक्का आधारित परियोजना के लिए भूमि का आबंटन पत्र प्रदान किया गया. ए.सी.सी. सीमेंट कम्पनी को क्षमता विस्तार के लिए टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र, अमेठी में 3 एकड़ भूमि का आबंटन पत्र सौंपा गया. इससे 650 करोड़ रुपाये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है. श्री सीमेंट लि. को सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में 30 एकड़ भूमि का आबंटन पत्र दिया गया. इस इकाई की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र बांदा में आम्रपाली पावर एंड सीमेंट द्वारा 490 करोड़ रुपये की लागत से 29.33 एकड़ भूमि पर सीमेंट एवं सीमेंट क्लींकर ग्राइंडिंग इकाई स्थापित की जाएगी.

इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र करखियांव, वाराणसी में 30 एकड़ भूमि पर 140 करोड़ रुपये की लागत से अमूल द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की परियोजना के लिए भूमि का आबंटन पत्र प्रदान किया गया. इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीपेट) द्वारा 10 करोड़ रुपये के निवेश से प्लास्टिक आधारित तकनीकी शैक्षिक संस्थान की स्थापना के लिए प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर औरैया में 5 एकड़ भूमि का आबंटन पत्र प्रदान किया गया है.

समाजवादी सरकार के जैसे पंख निकल आए हों, इसीलिए यूपी में 15 हजार करोड़ का निवेश की घोषणा करने के चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री एक बार फिर विकास के एजेंडे के साथ मीडिया से रूबरू हुए और दोहराया कि राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए गम्भीरता से काम किया जा रहा है. यह पहली राज्य सरकार है, जो वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विभागवार एजेंडा निर्धारित कर लागू कर रही है. मुख्यमंत्री द्वारा इस दौरान लोक निर्माण, ऊर्जा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है. प्रदेश सरकार के प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं. चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा जनसामान्य को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप एम.बी.बी.एस. की 500 सीटों की बढ़ोत्तरी हुई. नये मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू किया गया है.

श्री यादव ने बताया कि विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं. लाइन हानि को कम करने के साथ–साथ तहसील स्तर पर फीडर परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है. पूर्वांचल में 2 माह में 11,640 खराब ट्रांसफॉर्मर बदले गए. इसी के साथ–साथ राज्य में अच्छी सड़कों एवं पुलों का संजाल बिछाया जा रहा है. अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख–रखाव की व्यवस्था नहीं थी. राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण के लिए ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति बनाकर लागू करने का फैसला लिया है. इसी प्रकार प्रदेश की विभिन्न नदियों पर आवागमन के लिए बड़ी संख्या में पुलों के निर्माण तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुगम यातायात के लिए आर.ओ.बी. बनाए जा रहे हैं. इन्होंने कहा कि अकेले लखनऊ शहर में जितने फ्लाईओवर बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, इतने कभी नहीं बने. उन्होंने कहा कि पिछली बी.एस.पी. सरकार ने सपा सरकार के समय में बनाए जा रहे कई पुलों का कार्य रोक दिया या इनके लिए बजट की व्यवस्था ही नहीं की. फलस्वरूप इन पुलों की निर्माण लागत बढ़ गई. इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने इन्हें पूरा कराने का काम किया. मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है. संगठन द्वारा साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने तथा धर्म निरपेक्ष शक्तियों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है.

बहरहाल, मुख्यमंत्री ने उद्योपपतियों की राह के स्पीड ब्रेकरों को हटा कर अपना काम कर दिया है. वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को कोई परेशानी न हो. उन्होंने उद्योगपतियों के पक्ष में कई कदम उठाने के अलावा उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल भी दे दिया है. अब अखिलेश के मंत्रियों पर जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरे उतरें. अफसरों को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा. ऐसा माहौल और विश्वास बार–बार नहीं बनता है. सब मिलकर चाहें तो प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

भाजपा पर भारी पड़ सकती हैं तिकड़ी

दर्शन शर्मा

तीसरे मोर्चे की परिकल्पना करने वाले सपा प्रमुख मुलायम सिंह के साथ चुनाव बाद कितने दल साथ आएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि वह कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूत के पांव पालने से नजर आते हैं. कुछ ऐसा ही मंसूबा मायावती का भी हो सकता है. कांग्रेस का बाहर से साथ देने वाली बसपा सुप्रीमो भी इसी ख्याल में डूबी हैं कि वह कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि चुनावी महाभारत में उनके साथ अन्य कोई दिख नहीं रहा है, जो उन्हें सहारा दे सके. सपा और बसपा द्वारा दिए गए समर्थन से कांग्रेस अब इन दोनों दलों के मुखियाओं को अपने कुनबे में जोड़े रखना चाहती है. भले ही सपा और बसपा के बीच 36 का आंकड़ा बना हो, लेकिन सपा और बसपा की दूरी से कांग्रेस को काफी फायदा पहुंच रहा है. राजनीतिक हकीकत समझी जाए तो इन तीनों पार्टियों की उत्तर प्रदेश में दिशा-दशा रेखागणित के एक समकोण त्रिभुज के समान दिखती है, जिसका जोड़ हर ओर से 180 अंश ही निकलता है. ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में राजनीति की पौध को खाद-पानी दे रही भाजपा अकेली ऐसी पार्टी रहेगी, जिसे न तो सपा चाहती है, न बसपा और न ही कांग्रेस. सपा और बसपा को यकीन हो चला है कि अगर वह कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े तो गट्ठर की अलग-अलग लकड़ियों की तरह भाजपा उन्हें तोड़ डालेगी.

हाल के चुनावों में आ रहे नतीजों से सपा और बसपा का ग्राफ नीचे आया है. वहीं कांग्रेस का जनाधार औंधे मुंह गिरा है. घबराई कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है कि ऐसे बिगड़ते हालात में इसका असली हमदर्द कौन होगा? सबसे पहले इसकी नजर इन्हीं दो दिग्गजों पर जाएगी, जिन्होंने इसकी डूबती नैया को सहारा दिया था. हालांकि कांग्रेस के डूबते जहाज पर सवार होने की भला कौन जुर्रत करेगा. ऐसे बुरे समय में कांग्रेस के हमसफर रहे ये दोनों दल इसे बहुत अच्छे लग रहे हैं. कांग्रेस बसपा और सपा के एहसानों से दबी है, क्योंकि बुरे समय में साथ देने वाले ही असली दोस्त कहे जा सकते हैं. कांग्रेस उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे जितना ही सपा और बसपा इसे बुरा और भला कहे या कह चुकी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राजनीतिक फार्मूलों के बदौलत सपा कांग्रेस के जनाधार को तोड़कर बड़े सूबे में अपना परचम लहराती आई हो, अगर वे चुनाव में एक-दूसरे का खिलाफत नहीं करेंगे तो उनका जनाधार कांग्रेस में शामिल हो सकता है. यही हाल बसपा के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दलित बसपा का वोट बैंक है, जिसे बहन जी ने कांग्रेस से ही झटका था. वह इसे संजोए रखना चाहेंगी. उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर

दलित उनके हाथ से निकल गया तो वह राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में कंगाल हो जाएंगी. यही कारण रहा है कि दलित वोट को बचाने के चक्कर में बसपा सुप्रीमो कांग्रेस से नजदीक रहकर भी दूरी बनाए हुए हैं. इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस से सपा और बसपा का साथ और दूरी बनाए रखने की नीति को नूरा-कुश्ती बताता रहा है. राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा रही है. हां इतना जरूर है कि उनकी तिकड़ी में इतनी ताकत है कि अगर वह एक साथ आक्रमण कर दें, तो बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर को जमीन दिखा सकते हैं. यदि मुलायम का मुसलमान और माया का दलित वोट के साथ-साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का आंशिक जनाधार मिल जाए तो लोकसभा की 80 सीटों में से आधी से अधिक सीटें इसी तिकड़ी को हासिल हो सकती हैं, क्योंकि विधानसभा के पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2007 में बसपा प्रचंड बहुमत में सत्ता में आई तो दूसरी बार 2012 में सपा ने प्रचण्ड बहुमत उत्तर प्रदेश में पहली बार हासिल किया है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि कहीं सपा बसपा मिल गए होते और उनका साथ जारी रहता तो उन्हें हराना किसी दूसरे दल के बूते की बात नहीं थी. इनमें से एक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता था. लगातार केन्द्र में दो बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस के पास इस बार अच्छा मौका है, जब इन दोनों को अपने साथ करते हुए उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़े, तो इसे काफी सफलता मिल सकती है. इसकी खोई पुरानी साख लौटा ले. जहां कांग्रेस चौथे नंबर पर रहकर पिछले ढाई दशक से संघर्ष कर रही है.

हालांकि बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार मुलायम सिंह का रूझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है. सपा के कांग्रेस प्रेम की झलक हाल ही में देखने को मिली है. जब सपा ने अचानक राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देकर सभी दलों को अचंभित कर दिया है. इसे सपा की एक नई रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे. इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है. राजनीतिज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस को सपा अछूत नहीं मानती है. सपा की यह राजनीतिक शैली है कि वह किसी हद तक सांप्रदायिक शक्तियों को प्रदेश में बढ़ने नहीं देगी. इसी लिहाज से शायद सपा प्रमुख ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को राज्य सभा के लिए समर्थन दिया है. कांग्रेस के पीछे चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस की ओर भी रुख कर सकता है. शायद इसे रोकने के लिए ही मुलायम सिंह ने ऐसा पत्ता चला है. यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा है.

कांग्रेस का बसपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं पिछले दिनों सुर्खियों में रही हैं. कभी हां, कभी ना का खेल कांग्रेस और बसपा के बीच चल रहा है, लेकिन सीटों का समीकरण न बन पाने के कारण बसपा और कांग्रेस आगे-पीछे होती दिख रही हैं, लेकिन यह तय है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और बसपा के बीच में खिचड़ी पक रही है. भले ही अभी इसका खुलासा नहीं हो रहा है. लब्बोलुआब यह है कि जिस कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और बसपा सुप्रीमो को बचा लिया हो, तो सपा, बसपा नेतृत्व इस एहसान को चुनाव में साथ देकर क्यों नहीं अदा करेंगे. लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस यदि एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो यह भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप की आहट भी गुल खिला सकती है. कयास यह लगाये जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे दल भाजपा के खिलाफ ही ताल ठोंकेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

छिटपुट घटनाओं की भी होगी वीडियोग्राफी

संदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था समाजवादी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है. जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद भी हालात में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है. लोकसभा चुनाव सिर पर हैं. ऐसे में अक्सर साम्प्रदायिक और आपराधिक ताकतें मजबूत हो जाती हैं. कुछ नेताओं का भी ऐसी ताकतों का संरक्षण मिला होता है, जिसके चलते कानून व्यवस्था का मामला और भी पेचीदा हो जाता है. पुलिस के पास संसाधन और फोर्स सीमित होती है. ऐसे में अक्सर बिगड़े हालातों को काबू करना आसान नहीं होता. पुलिस महकमे की तमाम खामियों से मिली नाकामयाबी का ठीकरा सरकार के माथे फोड़ दिया जाता है. यही दर्द समाजवादी सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है.

इस बात का एहसास युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी है. इसीलिए एक तरफ पुलिस भर्ती अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी व चुस्त-दुरुस्त बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जनपदों को वीडियो कैमरे उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी शासन स्तर पर

लिया गया है. प्रदेश के सभी जनपद के पुलिस प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा 2-2 लाख रुपये की दर से डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है. प्रमुख सचिव (गृह) अनिल कुमार गुप्ता यह बात स्वीकारते हुए कहते हैं कि इस पैसे से सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे खरीदे जा रहे हैं. इससे कानून-व्यवस्था संबंधी घटनाओं तथा आने वाले त्योहारों व चुनाव आदि के मौके पर होने वाली छिटपुट घटनाओं तक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि गड़बड़ी कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध पुख्ता सबूत के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके. बहरहाल, अगर यह योजना सलीके से परवान चढ़ जाती है तो इन छोटे-छोटे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है, जो कभी-कभी बड़ी वारदात का कारण बन जाते हैं.

पूर्व डीजीपी राम अरुण इस फैसले की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह की पुलिस की कार्यशैली है, उसे देखते हुए इस महकमे को आधुनिकतम सुविधाओं से लैस रखना जरूरी है. हम जब तक अपराधियों से दो कदम आगे जाकर नहीं सोचेंगे, तब तक अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बड़े फैसले, बढ़ते क़दम

श्री अखिलेश यादव
मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

हर क़दम पर ग़रीबों व जरूरतमंदों के स्वास्थ्य की चिंता

- समस्त मरीजों का भर्ती शुल्क माफ। बीपीएल कार्ड धारकों का समस्त उपचार एवं परीक्षण निःशुल्क।
- विभिन्न रोगों के इलाज के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 360 करोड़ रूपये का प्राविधान।
- गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट कार्ड जारी। कार्ड धारक परिवार के पांच सदस्य चिन्हित सरकारी अथवा मिनी अस्पताल में एक वर्ष तक 30 हजार रूपये का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
- चिकित्सालयों में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की औषधियां तथा विशेष मरीजों जिनका उपचार लम्बे समय तक चलना है, को 15 दिन की औषधियां प्रदान की जा रही है।
- रोगियों को शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क (टोल फ्री) नम्बर 108 के माध्यम से आपातकालीन 988 मोबाइल वैनों (एम्बुलेन्सों) का संचालन शुरू। अब तक 12,01,422 रोगियों को मुफ्त एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी गयी।
- जिला बदायूं एवं जौनपुर में एक-एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना।

ग्रामों के समग्र विकास के साथ ही अन्नदाता किसानों के दुःख दर्द बांटने की पहल

- किसानों की जमीन बन्धक रखकर लिये गये कर्ज की माफी हेतु उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक को 1650 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था। 4.19 लाख कृषकों का लगभग 900 करोड़ रूपये का ऋण माफ।
- कृषक दुर्घटना बीमा राशि एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दी गयी है।
- किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त पानी की व्यवस्था। 55,45,804 किसान लाभान्वित।
- 'डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना' के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से 05 वर्षों में 10,000 ग्रामों का चयन कर उनमें अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- 'लोहिया ग्रामीण आवास योजना' के लिये 1402.98 करोड़ रूपये की व्यवस्था। लोहिया आवासों में सोलर लाइट की व्यवस्था। 1,19,752 आवास निर्मित कराने का लक्ष्य।
- समस्त अनजुड़े ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है।

कन्या विद्याधन व लैपटॉप से खुले उच्च शिक्षा के द्वार, बेरोजगारों को भत्ता

- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित 'कन्या विद्याधन योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 2,85,417 छात्रायें लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 900 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- इण्टरमीडिएट पास छात्र/छात्राओं को 15 लाख 'निःशुल्क लैपटॉप' वितरित कराये जा रहे हैं। अब तक लगभग 10 लाख लैपटॉप वितरित।
- 'बेरोजगारी भत्ता' योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 11,59,398 लाभार्थियों को 1100 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित कर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2013-14 में 1200 करोड़ रूपये की व्यवस्था। 12,57,129 लाभार्थी इस वर्ष लाभान्वित।
- मेडिकल कालेजों में छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा में अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 500 सीटों में बढ़ोत्तरी।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने एवं उनकी जमीन की सुरक्षा व संरक्षा के लिये इन स्थलों की चहारदीवारी बनाये जाने हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- अल्पसंख्यक समुदायों की हाईस्कूल पास पुत्रियों को आगे की शिक्षा हासिल करने अथवा उनके विवाह के लिये 30,000 रूपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु संचालित 'हमारी बेटी, उसका कल' योजना में वर्ष 2012-13 में 82,916 छात्राओं को 250 करोड़ रूपये की धनराशि का वितरण। वर्ष 2013-14 में 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था। 1.15 लाख बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- शहरी गरीबों तथा अल्पसंख्यक परिवारों को 'आसरा' योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

श्रमिकों, बुनकरों का सम्मान एवं कल्याण

- पावरलूम बुनकरों को राहत प्रदान करने के लिये बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु 120 करोड़ रूपये स्वीकृत। हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित।
- श्रमिकों के कल्याण हेतु शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, दुर्घटना सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना, औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना एवं सौर ऊर्जा सहायता योजना का कार्यान्वयन।

जन-समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक प्रयास तथा जनसुविधाओं का विस्तार

- महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिये 'वूमेन पावर लाइन 1090' टोल फ्री नम्बर चालू। 98,278 से अधिक शिकायतों का समाधान।
- लोकवाणी केन्द्रों तथा जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 8 विभागों की 26 शासकीय सेवाओं/प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की सुविधा।
- लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण।
- तीन हजार नयी बैंक शाखा खोले जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण।

अन्य क्षेत्रों में की गयी अनूठी पहल

- टूरिज्म विकास हेतु ब्रज-मथुरा परिपथ एवं बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों का पर्यटन विकास।
- इटावा जनपद के फिशर फारेस्ट के चयनित क्षेत्र में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र एवं बब्बर शेर सफारी की स्थापना।
- रिक्शा चालकों को शारीरिक श्रम से राहत दिलाये जाने हेतु मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 400 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था।
- बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को 01-01 कम्बल प्रदान किये जाने हेतु 800 करोड़ रूपये का प्राविधान।

उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा इनर रिंग रोड, गाजियाबाद-नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड का निर्माण। इसके साथ ही बरेली-अल्मोड़ा मार्ग किमी. 56 तक, वाराणसी-शक्तिनगर (हाथीनाला तक) किमी. 115 तक, दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग किमी. 217 तक, मेरठ-करनाल मार्ग किमी. 90.4 तक, इटावा-मैनपुरी-कुरावली मार्ग, जोया-अमरोहा मार्ग, मुरादाबाद-सम्भल मार्ग, मूरतगंज से मन्झनपुर मार्ग तथा बहराइच से भिनगा मार्ग आदि का भी निर्माण।
- सभी जिला मुख्यालयों को फोर-लेन सड़क से जोड़ना।
- आगरा एवं कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण।
- लखनऊ में मेट्रो रेल संचालन हेतु प्रभावी कार्यवाही।
- अधूरे सेतुओं व अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।
- सौर ऊर्जा नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश में सोलर पावर प्लान्टों की स्थापना।

आधुनिक तकनीकी शिक्षा का विस्तार

- कन्नौज, सोनभद्र एवं मैनपुरी में नये राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना।
- फैजाबाद विश्वविद्यालय के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना।
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुरखीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना।
- मदनमोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाना।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
http://information.up.nic.in

दिल्ली के आप की यूपी में दस्तक

संजय सक्सेना

दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार इंट्री करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) इत्तर प्रदेश की राजनीति में छा जाने को बेकरार है. आप ने संजय सिंह को इत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर पहला कदम बढ़ा भी दिया है. संजय सिंह यूपी के लिए कोई नया चेहरा नहीं हैं. दो वर्ष पूर्व समाजसेवी अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अपना आंदोलन शुरू किया था, तब संजय सिंह ने यूपी की कमान संभाली थी. यूपी के सुल्तानपुर जिला के गबड़िया मोहल्ले से निकल कर पूरे देश में नाम रोशन करने वाले संजय सिंह आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं. वह धर्म-जाति में बंटी राज्य की जनता को बिजली-पानी, कानून व्यवस्था, पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाये हुए हैं. एक तरफ यूपी में सभी 70 सीटों के लिए दावेदारी ठोंकने की बात कर रहे संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ उनकी टीम के अन्य सदस्य चेतना यात्रा निकाल कर जनता के बीच राजनीतिक अलख जला रहे हैं. इसकी शुरुआत लखनऊ से करते हुए गत दिनों आप के कार्यकर्ताओं ने कृष्णा नगर (थाना आलमबाग) से बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी तक आम आदमी चेतना यात्रा का आयोजन किया. आप की इस यात्रा को अगर संकेत माना जाए तो यह अच्छी शुरुआत रही.

आप के कार्यकर्ताओं द्वारा करीब 25 किलोमीटर का सफर चेतना यात्रा के दौरान पूरा किया गया. इस दौरान जगह-जगह लोग इनसे जुड़ते रहे और इस तरह से उनका कारवां बढ़ता गया. आप वाले कहते हैं कि इसकी वजह साफ है कि 8 दिसंबर को जैसे-जैसे चुनाव परिणाम आते गए, पूरे देश में एक नई चेतना का संचार हुआ. 8 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को मिले जनसमर्थन से स्पष्ट हो गया कि आने वाला समय आप का ही है. चुनाव तो दिल्ली में था, लेकिन इसका असर पूरे देश में दिखाई दिया. पूरे देश से मिल रहे अपार जन समर्थन से उत्साहित आप के कार्यकर्ता कहते हैं कि अब स्पष्ट हो चुका

है कि आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प देने की स्थिति में है. अब, जबकि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने निश्चय किया है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पार्टी पूरे देश में अपना प्रत्याशी उतारेगी, ऐसी स्थिति में आप लखनऊ की 15 सदस्यीय जिला इकाई ने नये सिरे से तैयारी करने का निर्णय लिया है. इसकी शुरुआत आम आदमी चेतना रैली से हो चुकी है.

रैली की करीब 25 किलोमीटर मार्ग की बात की जाए तो कृष्णानगर (पुलिस स्टेशन) से शुरू होकर यात्रा ने मवइया, एवरेडी क्रॉसिंग, चौक, घंटाघर, रूमी गेट, डॉलीगंज ब्रिज, आईटी कॉलेज, कपूरथला, गोल मार्केट, निशातगंज, लखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, एबीसी मुंशी पुलिया, पॉलीटेक्निक से होते हुए बीबीडी यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया. लखनऊ में पहली बार आप ने एक बड़ी चेतना यात्रा निकाल कर लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज किया. चेतना यात्रा में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से अवध जोन की संयोजक अरुणा सिंह, जिला संयोजक अनमोल, सचिव विशाल सिंह, पावन, व डॉ. पवन चतुर्वेदी, गोल्डी, डॉ. प्रमोद राय, कौशल, महावीर, रूबील, अंजली लाल, राजेश, गौतम भारती, राकेश, मनोज तिवारी, आरके नायक, पुरुषोत्तम शुक्ला, इफ्तिकार अहमद, मोहित टंडन, मुनीष शुक्ला, अनुज पाठक आदि थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

वाणिज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

भ्रष्टाचार का दीमक बड़ी तेज़ी से अपना शिकंजा सरकारी विभागों पर कसता जा रहा है. पगार मिलने के बावजूद ऊपरी आमदनी की लालच में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी जमकर 'वन टू का फ़ोर' और 'फ़ोर टू का वन' की बिसातें चल रहे हैं, जिनके मकड़जाल में उलझकर विभागों को लाखों रुपये प्रतिदिन की चपत लग रही है. भ्रष्टतंत्र की ये भयानक बीमारी कभी पूर्वांचल के कमाऊ पूतों में गिने जाने वाले डिपार्टमेंट वाणिज्य कर विभाग को भी लग गई है. परिणामत: अधिकारियों, कर्मचारियों और अवैध कारोबारियों की सांठ-गांठ से यह धंधा ऐसा चमका की विभागीय आमदनी का बंटाधार हो गया. वाणिज्य कर विभाग के ज़िम्मेदार अफ़सरों की लापरवाही से पूर्वांचल में धान व गल्ले पर करों को अपवंचन डंके की चोट पर जारी है. अवैध कारोबारी अधिकारियों की शह पाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का अनाज मध्य प्रदेश, बिहार एवं दिल्ली समेत अन्य बाहरी प्रदेशों में भेज रहे हैं, जिससे वाणिज्य कर विभाग को एक महीने में करोड़ों रुपये की चपत लग रही है. पिछले दिनों वाराणसी स्थित विभागीय मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई गई थी. उन्हें चेताया भी गया था कि सुधर जाएं, वरना उनके खिलाफ़ भी जांच सेटअप की जा सकती है. करों के अपवंचन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के साथ ही टैक्स वसूली सौ फ़ीसद होने की भी बात कही गई थी. अधिकारियों को निर्देश है कि दिसम्बर में धान के करों के अपवंचन पर नज़र रखें. इस वर्ष धान की सरकारी खरीद पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी नहीं है. ऐसे में मंडी में धान की आमद, राइस मिलों द्वारा दिखाई जा रही धान की खरीद और अन्य प्रांत में की जा रही खरीद-फ़रोख्त के दस्तावेज़ों की गहनता से जांच कराए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि अभी भी पुराने ढर्रे पर ही अंगद की तरह पांव जमाए खड़े हैं.

वैसे बताते चलें कि नवम्बर माह में धान में 3.66 लाख व गल्ले में 5.96 लाख रुपये की वसूली वाणिज्य कर विभाग द्वारा की गई है, जो लक्ष्य से कोसों पीछे है. कभी टैक्स

वसूली में अव्वल रहने वाला यह विभाग अबकी बार वसूली में फिसड्डी साबित हुआ है, लेकिन अधिकारी हैं कि ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं. उन्हें अपनी ही पीठ थप-थपाने से फुर्सत नहीं मिल रही है. वाणिज्य कर विभाग ग्रेड-1 के एडीशनल कमिश्नर डीपी सिंह का मानना है कि विभागीय अधिकारी पैनी नज़र से धान की खरीद-फ़रोख्त का ध्यान रख रहे हैं. तभी तो जोन प्रथम में धान के पांच मामलों की धर-पकड़ कर जहां क़रीब 3 लाख 66 हज़ार की वसूली की गई. वहीं जोन दो में धान के 19 मामले पकड़े गए, जिनसे 10 लाख 49 हज़ार रुपये की भारी-भरकम रकम वसूली गई. अगर अधिकारिक आंकड़ों पर ही नज़र दौड़ाएं तो तस्वीर बिल्कुल साफ़ नज़र आती है. दोनों ज़ोन मिलाकर 24 मामले पकड़े गए और उनसे 14 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई, जो यह समझने के लिए काफ़ी है कि विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण करों के अपवंचन का शिकंजा कसता जा रहा है और अधिकारी सिर्फ बयानबाज़ी और कागज़ी कोरम पूरा करने के लिए ही कलम चला रहे हैं. अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाणिज्य कर विभाग का जल्दी ही दिवालिया हो जाना तय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संसद के टिकट के लिए सिर फुटव्वल

अजय कुमार

सपा करीब दर्जन भर प्रत्याशी बदल चुकी है. प्रत्याशी चयन या उन्हें बदलने को लेकर सपा में पनपा आक्रोश सड़कों पर आ चुका है. कहीं खुलकर तो कहीं भीतरघात करके प्रत्याशियों को कमजोर किया जा रहा है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा में प्रत्याशियों के बदलने और बगावत का खेल चरम पर है.

समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से काफी पहले प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति आत्मघाती साबित हो रही है. नेतृत्व ने विभिन्न सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की तो टिकट मिलते ही उम्मीदवार मैदान में कूद पड़े. मेल-मुलाकातों, राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने, रूठों को मनाने, विरोधी खेमें में सेंध लगाने का दौर शुरू हो गया. लोकसभा की चौखट लांघने को आतुर सपा के उम्मीदवारों को अपनी जीत सुनिश्चित करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जो सपा की राजनीति के लिए अच्छा भी था, लेकिन इस दौरान देश-प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा था. इस बात की चिंता सपा के लड़ाकों को भले नहीं थी, लेकिन आलाकमान चिंतित था. समय और राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था. अखिलेश सरकार की नाकामियां मुलायम के मिशन 2014 पर भारी पड़ रही थीं. इधर मुजफरनगर दंगों की आग में प्रदेश झुलस गया, जिसकी तपिश सपा के गलियारों में साफ दिखाई दी.

दंगों से पूर्व तक मुलायम मुस्लिम के एक मात्र ठेकेदार बने घूम रहे थे, लेकिन दंगों के बाद हालात बदल गए. मुसलमानों में यह बात घर कर गई थी कि इनको दंगों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और इनके रहनुमाई का दावा करने वाले सपा नेता तमाशबीन बने रहे. कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेता मुसलमानों को भरमाने की कोशिश में पहले से ही थे. दंगों के बाद इन्होंने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया. दोनों ही दलों ने ऐसा ताना-बाना बुना कि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी सरकार और इसके नेताओं को अपना दुश्मन समझने लगे. इन सब बदलावों से सपा आलाकमान चिंतित था तो रही-सही कसर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी. भाजपा सबल होकर उभरी तो आम जनता पार्टी जैसे नवोदित दल ने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करके सबको चौंका दिया. सपा नेता भले ही सार्वजनिक रूप से दावा कर रहे थे कि नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश में कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन भीतर से वह हिले हुए थे. आप भी दिल्ली फतह करने के बाद यूपी में दस्तक देने की तैयारी करने लगी थी. सपा जिस कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर चल रही थी और आगे भी

चलना चाहती थी, उसकी हार ने मुलायम के राजनीतिक कुनबे को हिला कर रख दिया. हवा का रुख भांप कर कई समाजवादी भगवा रंग मे रंग गए तो हालत पतली देख कर सपा आलाकमान ने जीत की भूख मिटाने के लिए कई दागी-दंबगों को अपने गले लगा लिया. इसमें से कई टिकट के दावेदार भी थे. इसी के बाद शुरू हुआ सपा में प्रत्याशियों के बदलने और बगावत का खेल.

सपा करीब दर्जन भर प्रत्याशी बदल चुकी है. प्रत्याशी चयन या उन्हें बदलने को लेकर सपा में पनपा आक्रोश सड़कों पर आ चुका है. कई नेताओं को लाल बत्तियां बांटकर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की गईं, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. कहीं खुलकर तो कहीं भीतरघात करके प्रत्याशियों को कमजोर किया जा रहा है.

बात सुल्तानपुर से की जाए, जहां हाल में प्रत्याशी बदला गया है. यहां का बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सपा ने यहां शकील अहमद का टिकट काट कर बाहुबली अतीक अहमद को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है. अतीक अहमद बसपा राज में भागे-भागे फिर रहे थे. यहां तक कि उन्हें यूपी छोड़ना पड़ा था. खैर, सुल्तानपुर की पहचान कांग्रेस से अधिक गांधी परिवार से होती है. कांग्रेस नेता संजय सिंह यहां से सांसद हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा यहां से वरुण गांधी को मैदान में उतारना चाहती है. वहीं बसपा ने बाहुबली पवन पांडेय को उम्मीदवार बना रखा है. किसी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने का सपा फायदा लेना चाहती है. इस बदलाव से शकील खेमा, जिसका टिकट कटा है, नाराज चल रहा है. वहीं ऐसे सपाइयों की भी संख्या कम नहीं है, जिन्हें अतीक रास नहीं आ रहे हैं, लेकिन मौके की नजाकत को भांप कर इन लोगों ने मुंह सिल रखा है. सपा के महासचिव

बात सुल्तानपुर से की जाए, जहां हाल में प्रत्याशी बदला गया है. यहां का बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सपा ने यहां शकील अहमद का टिकट काट कर बाहुबली अतीक अहमद को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है. अतीक अहमद बसपा राज में भागे-भागे फिर रहे थे. यहां तक कि उन्हें यूपी छोड़ना पड़ा था. खैर, सुल्तानपुर की पहचान कांग्रेस से अधिक गांधी परिवार से होती है. कांग्रेस नेता संजय सिंह यहां से सांसद हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा यहां से वरुण गांधी को मैदान में उतारना चाहती है. वहीं बसपा ने बाहुबली पवन पांडेय को उम्मीदवार बना रखा है.

रामगोपाल यादव अतीक को बेदाग साबित करने में जुटे हैं. फिरोजाबाद में रामगोपाल ने एक कार्यक्रम के दौरान यहां तक कह दिया कि अतीक के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है. बगावत के सुर पूर्वांचल की लालगंज सीट पर भी उभरे. आजमगढ़ जिले में पड़ने वाली इस संसदीय सीट से पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में विधायक बेचई सरोज को प्रत्याशी बना दिया गया. दरोगा का टिकट कटा तो उनके समर्थक विरोध पर उतर आए. दो माह तक विरोध का सिलसिला चलता रहा. फिर भी बात नहीं बनी तो सरोज भगवा रंग में रंग गए.

जौनपुर में भी सपा की अंदरूनी राजनीति का पारा डॉ. केपी यादव का टिकट काटने से चढ़ा हुआ है. उन्हें नवंबर 2012 को प्रत्याशी घोषित किया गया था. वह एक साल तक सड़कों पर संघर्ष करते रहे. फिर अचानक उनकी जगह कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को उम्मीदवार दिया गया. विरोध में डॉ. केपी यादव के समर्थकों ने हंगामा किया. डॉक्टर साहब कहते हैं कि टिकट कटने के बाद हफ्ते भर तक मैं लखनऊ में मुलायम सिंह जी से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी. तब हमारे हजार समर्थकों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ जनता के बीच जाने की सलाह दी. इसी कारण जनभावना यात्रा शुरू की गई. देखना है सपा नेतृत्व अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं. केपी कहते हैं कि 27 साल से नेताजी से जुड़ा हूं. 36 बार गिरफ्तार हुआ. 12 बार जेल गया. 2002 में विधानसभा टिकट काटा गया तो नेताजी ने मजबूरी बताई. 2007 में भी षड़यंत्र की राजनीति का शिकार हो गया. एक साल से तैयारियों में जुटा रहा, लेकिन बिना पूछे टिकट काट दिया गया. मेरा दर्द भी नहीं सुना गया. अब जनता ही फैसला करेगी. अगले महीने के शुरू में जन अदालत महारैली करके सियासी फैसला किया जाएगा. ऐसे ही हालात फर्रूखाबाद के हैं. यहां भी प्रत्याशी बदलना सपा नेतृत्व को भारी पड़ रहा है. यहां राज्य मंत्री नरेन्द्र यादव के तेवर तीखे हैं. इनके समर्थक मंत्री पुत्र का टिकट कटने से आहत हैं. सचिन का टिकट काटकर अलीगंज (एटा) के विधायक रामेश्वर यादव को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन सचिन का चुनाव अभियान बदस्तूर चल रहा है, जबकि पिछले दिनों वह पार्टी के प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों तक में शामिल नहीं हुए थे. सचिन भी बगावत कर सकते हैं. बस, पेंच सचिन के पिता का पड़ रहा है, जो अखिलेश सरकार में मंत्री हैं और अपनी लाल बत्ती नहीं खोना चाहते हैं.

श्रावस्ती सीट पर यासर शाह का विरोध है. सहारनपुर में उमराना मसूद के हाथ पार्टी का बड़ा खेमा है, लेकिन फिरोज आफताब का टिकट कटने के बाद विरोध के खूब स्वर उठे. मुजफ्फरनगर सीट पर एक खेमा गौरव स्वरूप की उम्मीदवारी बदलने के पक्ष में है. तर्क है कि दंगे के बाद गौरव के पक्ष में समीकरण नहीं है. ऐसी स्थितियां कई और संसदीय क्षेत्रों में भी हैं.

सपा प्रमुख पूरे हालात पर नजर रखे हैं. बगावत वाली सीटों पर मुलायम स्वयं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं. इसके लिए प्रभारियों से रिपोर्ट ली जा रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बगावत स्थानीय स्तर पर चल रही है, शीर्ष नेतृत्व से कोई खफा नहीं है. हां, इसका नुकसान जरूर पार्टी को उठाना पड़ सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

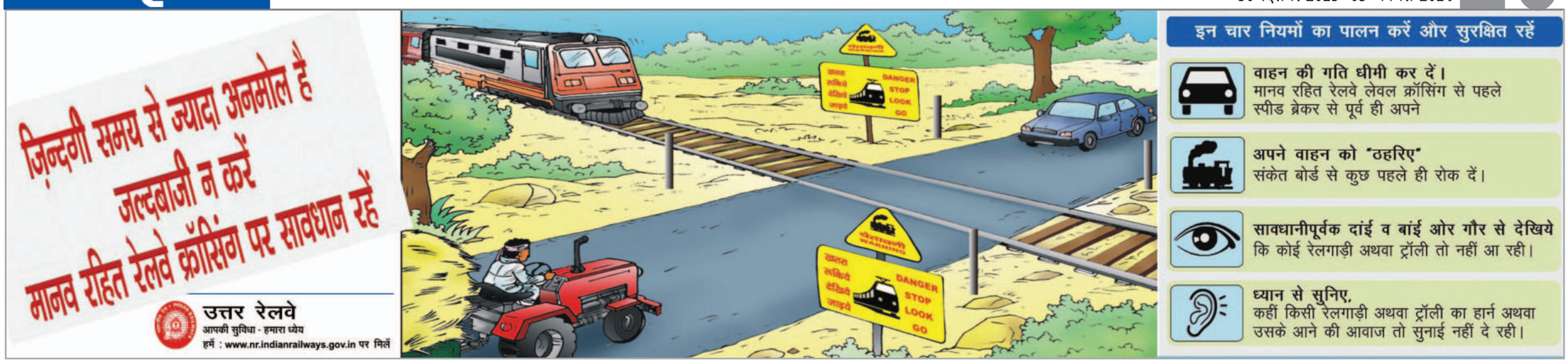

सरयू नदी का अस्तित्व संकट में

राकेश चंद्र श्रीवास्तव

भारत–नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले में पौराणिक सरयू नदी का अस्तित्व संकट में है. इस नदी को झिगहा व गोलवा नाम से भी जाना जाता है. इस नदी की धारा अब जगह–जगह खंडित हो चुकी है, जिससे नदी का स्वरूप नाला सरीखा दिखने लगा है. कभी धार्मिक दृष्टि से पूज्य एवं बहराइचवासियों के जन आस्था का प्रतीक इस दमतोड़ रही नदी में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में औद्योगिक और घरेलू कचरों को डाले जाने से बचा जल भी जहरीला हो गया है. जलकुम्भी और कूड़े के संजाल के चलते जलचर प्राणियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. चीनी मिल द्वारा सीरा छोड़े जाने से अब जानवर भी नदी का पानी पीने से कतराते हैं. पुरानी सरयू नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय की निचली पहाड़ियों में शीशापानी नामक स्थान से हुआ है. नेपाल के भाभर और तराई क्षेत्रों में लगभग 30 किलोमीटर का पथरीला रास्ता तय कर यह नदी बहराइच की सीमा में प्रवेश करती है. इसका प्रवेश सीमा के निकटवर्ती गांव सलारपुर के निकट होता है. कई छोटे–मोटे पहाड़ी व बरसाती नालों को मिलाती हुई पुरानी सरयू नदी बहराइच शहर के दोनों ओर बहती है. कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले यूरोप के लकड़ी व्यापारियों ने लकड़ी के सुगम परिवहन के लिए नहर खोदाई करवाकर इसे कौड़ियला में मिला दिया था. पुरानी सरयू बहराइच की ओर से कैसरगंज तहसील की सीमा में बहती हुई गोंडा जनपद के पसका नामक स्थल पर घाघरा में मिलती है. यही स्थल गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली शूकर क्षेत्र भी माना जाता है. इसके महात्मय को देखते हुए ही प्राचीन संत–महात्माओं ने तटीय क्षेत्र में मौनी बाबा आश्रम संत हरदब दास आश्रम आदि की स्थापना की थी. बाद में इसी के तट पर मरी माता मंदिर की स्थापना कर इन मंदिरों को जन आस्था का केन्द्र बिन्दु बना डाला. लगभग 70 किलोमीटर तक बहने वाली इस नदी में कोई दो दशक पूर्व लबालब पानी भरा रहता था, जिसका उपयोग मवेशियों के अलावा नागरिक भी बहुतायत से करते थे, लेकिन नानपारा स्थित श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल एवं नजदीक ही लगे आसवानी इकाई का गंदा जल के इस नदी में मिल जाने से समूचा जल क्षेत्र जहरीला हो गया है. नदी के किनारे स्थित मंदिरों में लगने वाली भीड़ तथा मेले भी अब नहीं लगते.

नदी में पहले देशी प्रजाति की मछलियां बहुतायात से पाई जाती थीं, लेकिन जलकुम्भी के आच्छादन के चलते मछलियां तो क्या, मेढक भी विलुप्त हो गए हैं. राटीफर्श, काइरोनामस, ट्यूवीफैक्स नामक जलीय प्राणियों का बहुतायत मात्रा में पाया जाना भी इसके जल के जहरीला होने की पुष्टि करती है. जहां एक ओर सरयू नदी का अस्तित्व संकट में है, वहीं इसकी सफाई के लिए न तो प्रशासन जागा है और न सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक संगठनो की नींद ही खुली है. हालांकि बहराइच में जिलाधिकारी रहे डॉ. ओमप्रकाश का कहना है कि शीघ्र ही प्रमुख सचिव (पर्यावरण) से मिलकर सरयू नदी को बचाने के लिए बात करेंगे. साथ ही इसके लिए व्यापक रणनीति बनाकर नदी को गंदा होने से बचाने की मुहिम चलाएंगे. समाजसेवी श्यामकरन टेकड़ीवाल का कहना कि वे सरयू नदी को बचाने के लिए शीघ्र ही समाजसेवियों की एक बैठक करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो आन्दोलन भी चलाएंगे. ■

लोकपाल-लाल बत्ती पर गरमाई यूपी की राजनीति

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी सरकार के न चाहते हुए भी जाते–जाते दिसंबर 2013 दोहरी खुशी दे ही गया. पहली खुशी समाजसेवी अन्ना हजारे की मुहिम के बाद लोकपाल के रूप में सामने आई तो दूसरी खुशी का कारण उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का वह आदेश बना, जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने अखिलेश सरकार द्वारा खैरात में बांटी गई लाल बत्ती और मंत्री पद पर रोक लगा दी. इन फैसलों से सपाई हताश दिखे तो कांग्रेस–बसपा और भाजपा को सपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया मौका मिल गया. दोनों ही फैसले ऐसे थे, जिसमें सपा को छोड़कर प्रदेश के सभी छोटे–बड़े दल एक सुर में बोल रहे थे. लोकपाल पास होने पर अन्ना समर्थकों ने जगह–जगह पूरे प्रदेश में विजय जुलूस निकाला और इसे जनता की बड़ी जीत बताते हुए विश्वास जताया कि लोकपाल से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और जनतंत्र की स्थापना होगी. चाहे लोकपाल हो या फिर लाल बत्ती बांटने का मामला, यह दोनों ऐसे मसले हैं, जो लोकसभा चुनाव तक शायद ही ठंडे हों. अखिलेश सरकार के लिए लाल बत्ती पर रोक का मामला कोई पहला झटका नहीं था, इससे पहले भी विभिन्न अदालतें अखिलेश सरकार के कई आदेशों पर रोक लगा चुकी हैं. खासकर आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने की राज्य सरकार की कोशिश के मामले में तो सीएम अखिलेश को काफी शर्मसार होना पड़ा था. कांग्रेस लोकपाल का श्रेय अपनी सरकार को देकर यूपी में 2009 को दोहराना चाहेगी, जब इसे 22 सीटें मिली थीं. 2009 में राहुल गांधी का जादू चला था. इसके बाद विधानसभा चुनाव मे भले ही वह पुराना इतिहास नहीं दोहरा पाए थे, लेकिन पिछले एक–डेढ़ वर्ष में हालात काफी बदल गए हैं. समाजवादी पार्टी अपना इकबाल खो चुकी है. मुसलमानों का भरोसा इससे करीब–करीब उठ गया है. बात केन्द्र में सरकार बनाने की है, इसलिए मुसलमान न चाहते हुए भी बसपा के मुकाबले कांग्रेस को 2013 में अपना कीमती वोट दे सकता है. कांग्रेस इसके लिए गोटे काफी समय से बैठा रही थी. इधर, समाजवादी नेता भी अनेक बार थाली में परोस कर कांग्रेस को मौका देने से पीछे नहीं हटे. लोकपाल का ही उदाहरण ले लिया जाए, जब पूरे देश की जनता और राजनीतिक ताकतें एकजुट होकर लोकपाल के समर्थन में खड़ी थीं, तब न जाने कौन सी मजबूरीवश सिर्फ और सिर्फ मुलायम टीम इसका विरोध करती रही. सपा के साथ सिर्फ शिवसेना वाले खड़े थे. दोनों ही दलों ने लोकपाल के जो तर्क दिए, उनका कोई मूल्य–महत्व नहीं था.

सपा के ना–नुकर के बाद लोकपाल पास हो गया और इसके साथ ही मुलायम को लोकपाल के बहाने घेरने वालों ने बांहें चढ़ा लीं. बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकपाल पारित होने से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटेगा. इसीलिए बहन मायावती ने इसे संसद में पास कराने के लिए बिल का समर्थन किया, जबकि सपा ने भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए बिल का विरोध किया. सपा सरकार हमेशा ही गुंडे, माफियाओं व भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और दुर्गाशक्ति जैसी ईमानदार अफसरों को उत्पीड़न करती रही है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री ने लोकपाल का श्रेय अन्ना हजारे के साथ राहुल गांधी को भी दिया और कहा कि पूरे देश के साथ–साथ उत्तर प्रदेश भी लोकपाल के कारण भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शास्त्री का कहना था कि प्रदेश में पहले से ही लोकायुक्त मौजूद था. लोकपाल पास होने से लोकायुक्त की ताकत और बढ़ जाएगी. प्रदेश में जिस समय चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तब यह बिल जनता के बीच विश्वास पैदा करने का काम करेगा. उधर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एन के महरोत्रा ने एक बार फिर दोहराया कि बिना जांच एजेंसियों के दायरे में आए भ्रष्टाचार नहीं हटेगा. लोकपाल के प्रभाव के संबंध में पूछे जाने पर श्री लोकायुक्त महरोत्रा का कहना था कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, तब तक वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. वहीं सपा के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने लोकपाल को भ्रमित करने वाला बताया. विभिन्न दलों के नेताओं के बयानों से आसानी से कयास लगाया जा सकता है कि कोई भी दल इस मसले को अपने हाथ से नहीं जाने देगा.

ऐसा ही मुद्दा लाल बत्ती का है. वर्तमान में करीब सौ लोगों को सरकार ने लाल बत्ती बांट रखी है. मंत्री का दर्जा प्राप्त यह लोग करते क्या हैं, कोई नहीं जानता. कई के पास तो अपना कार्यालय तक नहीं है. काम की बात तो दूर की है. बस, सरकारी सुविधाओं का दोहन हो रहा है. जनता की मेहनत की कमाई से वोट बैंक मजबूत करने की सरकारी मजबूरी समझ से परे है. दर्जा प्राप्त यह मंत्री जिन आयोगों, निगमों, बोर्डो अथवा विशेष समितियों के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में तमाम सुविधाओं से लैस हैं, इसमें से कुछ की ही उपयोगिता दिखाई देती है. इन पदों पर ऐसे लोगों तक को बैठा दिया गया है, जो चुनाव तक नहीं जीत सके. वैसे यह परम्परा कोई नई नहीं है, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, यह खेल शुरू हो जाता है. देखना यह है हाई कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश सरकार क्या कदम उठाती है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी राज्य सरकार के ऊपर अनेक बार अदालत के आदेशों से खिलवाड़ का आरोप लग चुका है. चाहे आतंक के आरोपियों को क्लीन चिट देने का प्रयास हो या फिर जातिवाद को बढ़ाने वाली अखिलेश सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं, जिनकी समीक्षा अदालतें समय–समय पर करती रहती हैं. ■

बच्चों को अमानुषिक अत्याचारों से बचाना जरूरी

शिवनाथ चतुर्वेदी

आज के अर्थप्रधान युग में जहां सवेदनाएं मर रही हैं और स्वार्थ ही सर्वोपरी हो गया है, वहां बचपन बचाओ का नारा अर्थहीन लगता है. आवश्यकता है उन कारणों को दूर करने की जो खेलने, खाने एवं पढ़ने की उम्र में ही बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर कर देते हैं. बाल श्रम उन्मूलन के नाम पर जिन बच्चों को कार्यक्षेत्र से मुक्ति दिलाई जाती है, उन बच्चों के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना भी नहीं है. बात बाल संरक्षण गृहों की करें तो वहां भी इन बच्चों को नारकीय जीवन ही जीना पड़ता है. बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं तो आम हो गई हैं. बच्चों को इस अमानुषिक अत्याचार से बचाना सर्वाधिक जरूरी है. इस बात की भी जरूरत है कि कार्यक्षेत्र में इन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के प्रयास संजीदगी से किए जाएं.

सभी जानते हैं कि बाल संरक्षण गृह इसी उद्देश्य से बनाए गए थे कि बच्चों को भोजन, वस्त्र, निवास एवं शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें रोजगार की दिशा में भी प्रवीण बनाया जाए, लेकिन वहां उनके तन–मन दोनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है. हम देशवासियों का दुर्भाग्य यह है कि हम योजनाओं का हश्र देखने के बाद भी इसके विरोध का साहस नहीं जुटा पाते. कन्या धन, विद्या धन, लैपटॉप वितरण अथवा अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर धन लुटाने से अच्छा है कि बच्चों के लिए ऐसी ठोस योजनाएं बनाई जाए, जिससे वह बाल श्रम करने पर मजबूर न हो और युवा होने पर इन्हें रोजगार की पूरी गारंटी मिल सके. कालीन उद्योग में बच्चों एवं महिलाओं की अंगुलियों का जादू सीर चढ़ कर बोलता है तथा आने वाले दिनों में वह कुशल कारीगर बन कर निकलते हैं. फलस्वरूप कम से कम उनके बच्चे तो बाल श्रमिक बनने पर मजबूर नहीं होते.

ऐसा अनुमान है कि 14 से 17 वर्ष तक के लाखों की संख्या में बच्चे देश भर में स्थित होटल रेस्तरां, दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों एवं घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका कोई हिसाब–किताब लेबर डिपार्टमेन्ट के पास नहीं है. कार्यस्थल पर बाल मजदूरों का मानसिक, शारीरिक एवं यौन शोषण जब हदें पार करने लगती हैं तो वे हत्या, बलात्कार जैसे संगीन आपराधों की ओर उन्मुख हो जाते हैं. वहां से उनकी अपराधिक जिन्दगी की शुरुआत होती है.

किशोर अपराधियों की जघन्य अपराधों में बढ़ती संलिप्तता चिन्ता का विषय है. हत्या, दुराचार, अपहरण, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम देने वालों में कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं. वे दोषी साबित होने पर भी सजा से बच जाते हैं. यही कारण है कि किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकना जरूरी है. पिछले वर्ष दिसम्बर में दिल्ली की लोमहर्षक घटना में शामिल अव्यस्क अपराधी पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और मात्र तीन वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि उसके व्यस्क साथियों को फांसी की सजा दी गई. उस समय नाबालिग पर अदालत में अन्य साथियों के साथ मुकदमा चलाने की जोरदार मांग उठी थी, पर सरकार ने कानून बदलने से इन्कार कर दिया था. न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने भी कहा था कि केवल एक प्रकरण के कारण कानून नहीं बदला जा सकता है. मुम्बई में शक्ति मिल दुराचार कांड में भी नाबालिग अपराधियों की संलिप्तता का मामला सामने आने के बाद भी एक बार कम उम्र के अपराधियों को व्यस्क अपराधियों के समान दंडित करने का प्रश्न उठा. दिल्ली कांड की पीड़िता के परिजनों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर किशोर न्याय अधिनियम रद्द करने की मांग की है, जो संगीन अपराधों में शामिल किशोरों पर समान न्यायालयों में मुकदमा चलाने से रोकता है. यह याचिका निर्भया के केस से जुड़ा है. जिस तरह हमारे समाज में कम उम्र के अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में निश्चित रूप से अब मासूमियत के मापदंड नये सिरे से तय किए जाने की जरूरत है. पिछले एक दशक के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि यौन अपराधों में किशोरों की संलिप्तता तेजी से बढ़ रही है. इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में किशोरों द्वारा हत्या के मामलों में भी इजाफा हुआ है.

इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो किशोरों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर निर्भया के माता–पिता द्वारा उठाया गया यह सवाल न केवल हमारी न्याय व्यवस्था, बल्कि पूरे समाज के लिए विचारणीय है. किशोरो में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति को लेकर अब जो बहस छिड़ी है, उसका यह हिस्सा बेहद गम्भीर है कि अपराध के प्रति आरोपों की समझ और अपराध करने में उनकी भागीदारी को आधार मान कर दंड देने का प्रावधान हो. नई पीढ़ी को यह पुख्ता संदेश देना भी जरूरी है कि सजा उम्र नहीं, अपराध की गम्भीरता तय करेगी. ■

चौथी दुनिया
आवश्यकता है
संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि
चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.
E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

30 दिसंबर 2013-05 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

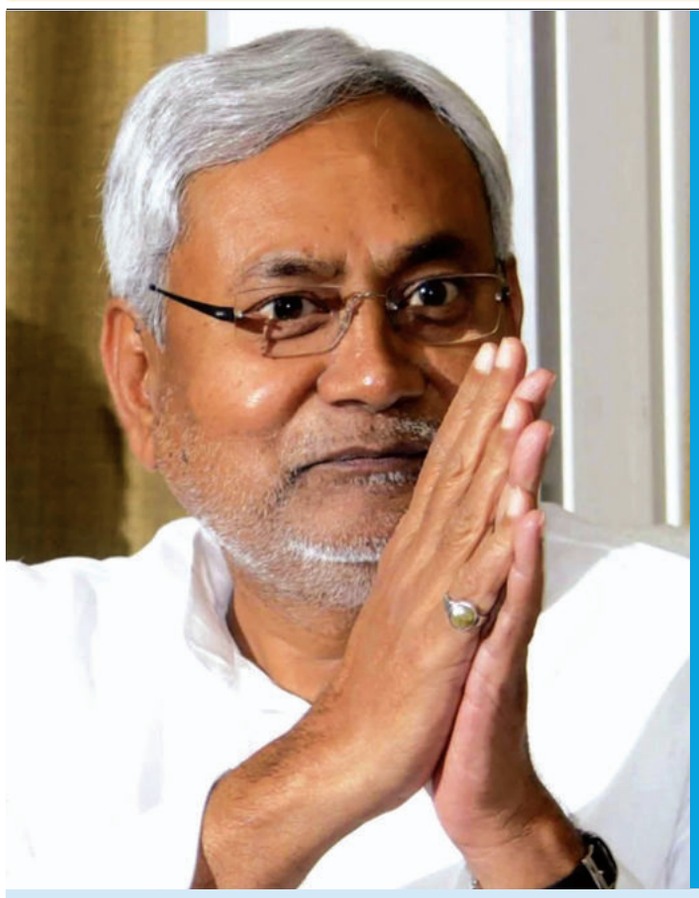

मुस्लिम वोटों पर लालू और नीतीश की नजर

यह महज संयोग नहीं है कि लालू प्रसाद ने जेल से निकलते ही यह ऐलान कर दिया कि वह धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए देश भर का दौरा करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का नेता कोई भी हो हम उसके साथ हैं. इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया. लालू धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने की बातें तो करते हैं, पर नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना चाहते हैं.

सरोज सिंह

रांची में जेल से निकलते ही लालू प्रसाद ने दहाड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को केवल और केवल मैं ही रोक सकता हूं. लालकृष्ण आडवाणी का रथ मैंने ही रोका था और अब देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को भी रोकूंगा. जब लालू जब रांची में अपनी भावी रणनीति का खुलासा कर रहे थे तो ठीक उसी समय नीतीश कुमार पटना में छाती ठोंक कर दावा कर रहे थे कि हम अपनी नीतियों से समझौता करने वाले लोग नहीं है. सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा युद्ध जारी रहेगा चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े. देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए हम अपने जीवन की कुर्बानी दे सकते हैं तो सत्ता कौन बड़ी चीज है. दरअसल जिस कहानी की पटकथा दोनों नेता बयान कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में मुसलमानों का वह थोक वोट बैंक है जो जिस नेता की झोली में जाएगा उसकी किस्मत देखते ही देखते चमक सकती है. नरेंद्र मोदी के उभार के पहले इस वोट बैंक पर लालू प्रसाद का कब्जा था और यह उपलब्धि उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोककर हासिल की थी. आडवाणी का रथ रोकने के बाद लालू प्रसाद देश भर में मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनकर उभरे और मुसलमानों ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया. चुनावी बिसात पर यह वोटबैंक लालू प्रसाद की तरफ इस तरह चिपका की बिहार और देश की सत्ता पर लगभग 15 सालों तक उनका दबदबा बना रहा. लेकिन जैसे-जैसे मुसलमानों का रुख बदला लालू प्रसाद का ग्राफ गिरने लगा और आज की तस्वीर क्या है इसे सब जान रहे हैं. यह महज संयोग नहीं है कि लालू प्रसाद ने जेल से निकलते ही यह ऐलान कर दिया कि वह धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए देश भर का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता कोई भी हो हम उसके साथ हैं. इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को वह उखाड़ फेंकेंगे.

लालू धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने की बातें तो करते हैं पर नीतीश कुमार को साथ लेना नहीं चाहते हैं. इसके पीछे लालू प्रसाद के अपने ही तर्क हैं. लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार 17 सालों तक भाजपा की गोद में खेलते रहे हम उन्हें कैसे धर्मनिरपेक्ष मान लें. देख लीजिएगा चुनाव के बाद भाजपा व जदयू फिर एक हो जाएंगे. मतलब साफ है कि लालू प्रसाद जिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने वाले हैं उनमें जदयू शामिल नहीं है. लालू प्रसाद जब जेल से छूटकर पटना पहुंचे तो उनके तेवर और सख्त हो गए और उन्होंने कहा कि जदयू को एक या दो सीट भी लोकसभा चुनाव में मिल जाए तो गनीमत है. लालू प्रसाद का मानना है कि सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में नीतीश कुमार ने मजबूत किया है इसलिए आगामी चुनाव में मुकाबला भाजपा के साथ ही होना है. लालू प्रसाद इस कठिन लड़ाई की चुनौतियों को समझ रहे हैं इसलिए वह इस मुहिम में जेल के अंदर लगे हुए थे कि उनका माय समीकरण

यानि मुसलमान व यादवों का गठबंधन पहले की तरह अपने रौ में आ जाए. लालू के जेल जाने के बाद यादवों की सहानुभूति निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के प्रति बढ़ी और जो विरोध में थे वे अब लालू की शरण में आने लगे हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि आठ सालों से सत्ता से दूर रहने का दर्द उन्हें परेशान कर रहा है. उन्हें लगता है कि उनके सामने लालू प्रसाद को आगे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. अगर लालू मजबूत हुए तो तय है कि यादवों का दबदबा सत्ता के गलियारों में बढ़ेगा. लालू प्रसाद भी इन बातों को समझते हैं इसलिए यादवों को लेकर वे ज्यादा परेशान नहीं हैं. असली चुनौती मुस्लिम वोटों को लेकर हैं क्योंकि इसके एक नए दावेदार नीतीश कुमार भी हो गए हैं. नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा के साथ संबंध तोड़ चुके नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक लाइन खींचने का काम किया है. नीतीश कुमार को लगता है कि मुस्लिम समाज उन्हीं की खींची हुई लाइन पर चलना पसंद करेगा क्योंकि उन्होंने बड़ा त्याग किया है. लालू प्रसाद अपनी नई रणनीति से नीतीश कुमार की खींची हुई इसी लाइन को मिटा देना चाहते हैं. लालू प्रसाद धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं बल्कि वह इसका देशव्यापी चेहरा बनना चाहते हैं. बहुत जल्द लालू मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों से मिलने जाने वाले हैं. इसके बाद लालू प्रसाद लोकसभा की उन सीटों का दौरा भी कर सकते हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक संख्या में मौजूद हैं. लालू यह बात घूम-घूम कर कहने वाले हैं कि आप अपना वोट बर्बाद न करें. देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हो रही हैं और अगर उन्हें कुचलना है तो मेरी खींची हुई लाइन पर चलिए न कि किसी ओर की लाइन पर. कांग्रेस को फ्रीहैंड देकर भी लालू प्रसाद मुस्लिम समाज को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि देश भर में वह ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक ताकतें फंस कर रह जाए. वह यह जताना चाहते हैं कि उनका अहं इस काम में कोई बाधा नहीं डालेगा चाहे मामला बिहार का ही क्यों न हो. बिहार में लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ हर हाल में समझौता करना चाहते हैं, चाहे लोजपा को कम सीटें ही क्यों न देनी पड़ें या उसका साथ ही क्यों न छोड़ना पड़े. लालू ऐसा करके मुस्लिमों को यह समझाना चाहते हैं कि कम से कम बिहार में तो राजद और कांग्रेस का गठबंधन ही सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की स्थिति में है. उनके हिसाब से नीतीश को वोट देना मतलब वोट की बर्बादी करना है और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करना है. इसलिए लालू प्रसाद अपनी दोहरी रणनीति पर बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं. जेल में बंद रहने का जो नुकसान हुआ उसका अहसास उन्हें है, इसलिए बिना समय गंवाए वह अपने मिशन में निकल चुके हैं. दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए अपने सातों घोड़े दौड़ा दिए हैं. दिल्ली में वामदलों द्वारा आयोजित रैली में जोरदार भाषण देकर नीतीश कुमार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे. लोकसभा में वह मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा सीटों पर उतारेंगे. इसकी भी कवायद चल रही है. दूसरे दलों के वैसे मुस्लिम नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी है जिन्हें वहां उचित सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर टिकट को लेकर उनके आसार धूमिल हो रहे हैं. चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए कई लोकलुभावन फैसले भी हो सकते हैं. नीतीश कुमार की रणनीति साफ है अगड़ी जातियों के वोट कटने की भरपाई वे मुस्लिमों वोटरों से करना चाहते हैं. भाजपा के हटने के बाद यह साफ हो गया है कि अगड़ी जातियों का स्वाभाविक झुकाव भाजपा की ओर है ऐसे में इसकी भरपाई मस्लिम वोटों से ही संभव है. जदयू के रणनीतिकार इस मामले में साफ हैं और इसी आधार पर काम कर रहे हैं. नीतीश कुमार को एक बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर पेश की जा रही है ताकि मुस्लिमों का झुकाव इनकी ओर हो सके. देखा जाए तो लालू और नीतीश दोनों के निशाने पर मुस्लिम वोट है क्योंकि दोनों के ही सपनों को यही वोट बैंक पूरा कर सकता है. कांग्रेस जिसके साथ जुड़ेगी उसे यह सपना पूरा करने में उतनी ही आसानी होगी क्योंकि तब मुसलमानों को भी यह भरोसा हो जाएगा कि यही गठबंधन भाजपा को मात दे सकता है. इधर भाजपा ने भी पसमांदा मुसलमानों में सेंध लगाने का अभियान शुरू कर दिया है. इसे लेकर भी जदयू व राजद के कान खड़े हो गए हैं. भाजपा की सोच है कि अगर 30 फीसदी मुसलमानों को भी वह अपने पक्ष में कर पाई तो उसे चुनावों में चमत्कारिक सफलता मिल सकती है. देखना है कि भाजपा की इस बढ़त को लालू और नीतीश कैसे रोक पाते हैं क्योंकि अगर भाजपा ने सेंध लगा दी तो फिर लालू और नीतीश के सपने चूर-चूर हो जाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

पुस्तक का लोकार्पण

श्री राम को कोई देवता या अवतार न स्वीकार कर एक महामानव, एक महानायक स्वीकार करने वाले लेखक ऋतेश कुमार गुप्त की पुस्तक अखिल विश्व के नायक – श्री राम का लोकार्पण कानूनविद् न्यायधीश श्री संजय कुमार सिंह द्वारा आईडीएच कॉलोनी में स्थित एनआईएचईआर में किया गया. इस मौके पर पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि श्री राम ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए उन सभी के गूढ़ निहितार्थ निकलते हैं और वे आज भी हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय हैं. उन्होंने समाज के सभी शोषित और उपेक्षित लोगों के लिए भी बड़े–बड़े कार्य कर उन्हें मुख्यधारा में लाया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री अवधेश मंडल ने कहा कि यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों में अवय ही पहुंचनी चाहिए क्योंकि इस पुस्तक को जन–जन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही लिखा गया है. जहां यह पुस्तक सामाजिक एवं धार्मिक समरसता, वैश्विक एकता आदि को प्रोत्साहित करती है, वहीं वीरता, नीति, प्रबंधन, राजनीति, इतिहास, स्त्री एवं शूद्र विमर्श आदि विषयों पर भी अपने प्रखर विचार रखती है. वहीं इस पुस्तक के लेखक ऋतेश कुमार गुप्त ने कहा यह पुस्तक कि भारतीय इतिहास का सच नामक किताब के बाद गौरवशाली भारत प्रकाशन–पाटलीपुत्र के लिए दूसरी उपलब्धि के समान है. यह पुस्तक हर व्यक्ति की रुचि और हितों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है. पटना में यह पुस्तक पूरे अशोक राजपथ के सभी पुस्तक स्टॉलों पर उपलब्ध है.

–अमृता कुमारी

रामकथा की होगी अमृतवर्षा

मां जानकी जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में वृहद श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है. सीतामढ़ी शहर के कमला राइस मिल प्रांगण में आगामी 9 जनवरी से 18 जनवरी तक उक्त आयोजन होगा. कथा वाचक वृंदावन धाम के ख्याति प्राप्त संत प्रवर विजय कौशल जी महाराज होंगे. कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार, 6 जनवरी को महारुद्राभिषेक, 8 को श्री रामायण जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी. वृंदावन मंडली के आचार्य योगेंद्र मिश्र 51 पाठकों के साथ रामायण पारायण करेंगे. कार्यक्रम की सफलता को लेकर तैयारी जोरों पर है.

–ब्रजेश कुमार

जमुई लोकसभा सीट पर कड़ी चुनौती देगा राजद

राजेश कुमार/मनोज भारद्वाज

जमुई की जमीन पर संभावनाओं को तलाशता राजद आगामी लोक सभा चुनाव में कामयाबी का किला फतह कर पाने में सक्षम साबित हो सकेगा अथवा नहीं? इसका जवाब समय के गर्भ में है पर जमुई में बनते–बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों से जो तल्ख माहौल तैयार होता दिख रहा है उससे यह संभावना बन रही है कि इस दफे राष्ट्रीय जनता दल कड़ी चुनौती पेश करेगा. जिले के ताजा सियासी हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो जदयू यहां पूरी तरह दो खेमों में विभाजित है. मंत्री नरेन्द्र सिंह व दामोदर रावत के नेतृव में यहां दल की दो धाराएं हैं. हालांकि जदयू संगठन इसे मानने को तैयार नहीं. जमुई सांसद भूदेव चौधरी ने क्षेत्र की जनता से दूर रहकर यहां के मतदाताओं को हम बाहरी हैं होने का भलीभांति अहसास करा दिया. जदयू सांसद की बची खुची प्रतिष्ठा भी हालिया स्टिंग ऑपरेशन ने धो डाली, लिहाजा जमुई सांसद की प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई ही पार्टी को यहां जबरदस्त झटका भी लगा. हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू द्वारा भूदेव चौधरी की उम्मीदवारी को नकारने की खबरें आ रही है. मोदी लहर के दौर में जमुई भाजपा ने लोक सभा के लिए प्रत्याशियों की संभावित सूची तैयार की है. सूची में डा. आरआर कन्नौजिया व महावीर पासवान के नाम पर यहां आम सहमति बनने की स्थिति नहीं दिखती. लिहाजा अंतिम समय में किसी तीसरे प्रत्याशी को सर्व सम्मति के आधारपर यहां मैदान–ए–जंग मे उतारा जा सकता है. जमुई में जदयू व भाजपा के अंदरूनी खाने की हलचल से राष्ट्रीय जनता दल खुश नजर आता है. राजद जिलाउपाध्यक्ष मो. निहाल फखरुद्दीन का कहना है कि राजद कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं. नीतीश के शासन में साम्प्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रचा गया है जिसे यहां के मुसलमान बखूबी समझते हैं. मुस्लिम समाज के लिए नीतीश ने केवल थ्योरी दी है जबकि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकल वर्क किया है. आडवाणी का रथ रोकने वाले लालू यादव मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं . निहाल फखरुद्दीन ने बताया कि राजद शासन काल में तोगड़िया को बिहार नहीं आने दिया गया, जबक नीतीश के राज में तोगड़िया की दर्जनों जनसभाएं मुस्लिम विरोध को केन्द्र में रखकर की गईं.

राजद के प्रदेश महासचिव गोपाल प्रसाद गुप्ता का दावा है कि युवाओं का पार्टी में जुड़ने तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जमानत मिल जाने से संगठन में अब एकता दिखेगी. संगठन की मजबूती के मद्देनजर जिले के तमाम विधान सभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अथवा लोजपा से गठबंधन होने की स्थिति में भी जमुई राजद के लिए सुरक्षित है. यहां लालटेन ही रहेगा चाहे प्रत्याशी कोई हो. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हूं.

दरअसल आगामी लोक सभा चुनाव में जमुई सीट की उम्मीदवारी को ले लोजपा–कांग्रेस व राजद में खींचतान की स्थिति बनी हुई है. चूंकि 2009 के लोक सभा चुनाव में राजद प्रत्याशी का प्रदर्शन कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में काफी बेहतर रहा था यही वजह है कि राजद जमुई छोड़ने को तैयार नहीं. हालांकि इस मामले में पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव पूर्व विधायक विजय प्रकाश तथा विधान पार्षद संजय प्रसाद ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जमुई राजद की रणनीति का खुलासा आनेवाले कुछ हफ्तों में हो ही जाएगा. दूसरी तरफ गोपाल गुप्ता का कहना है कि विनोद चौधरी जमुई के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे. उनकी बेदाग छवि और गरीबों के लिए काम करने की उनकी ललक पार्टी को काफी फायदा पहुंचाएगी. इस मामले में विनोद चौधरी का कहना है कि हम तो सिपाही हैं पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा वह मेरे लिए सर्व मान्य होगा. इसका हर हाल में पालन होगा. चौधरी ने कहा कि जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता से मुझे बहुत प्यार मिलता है इसलिए यहां की सेवा करना तो मेरा फर्ज है. मैं इस काम में लगा हूं. ■

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया संसदीय क्षेत्र

सेनापति की खोज में जुटे सभी दल

मनेन्द्र/नन्द किशोर

आगामी लोकसभा चुनाव में किला फतह करने को लेकर खगड़िया संसदीय क्षेत्र में सभी दलों ने अपने–अपने मजबूत प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है. गांवों से लेकर शहरों के गलियारों में छुटभैये नेताओं से लेकर बड़े–बड़े सूरमाओं ने अपने–अपने दल के खेवनहार को लेकर परिचर्चा शुरू कर दी है. खगड़िया संसदीय क्षेत्र में सम्पूर्ण खगड़िया जिला के चार विधानसभा यथा खगड़िया, अलौली (सु), बेलदौर एवं परबत्ता के अलावा समस्तीपुर जिले के हसनपुर एवं सहरसा जिले के सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा हैं. वर्तमान में इस लोकसभा पर जदयू सांसद दिनेश चन्द्र यादव का कब्जा है. इस लोकसभा में 13 लाख के लगभग मतदाता हैं. जिसमें मतदाताओं की संख्या जातीय आधार पर यादव 3 लाख 25 हजार, मुस्लिम 1 लाख 10 हजार, कोइरी 1 लाख 50 हजार, कुर्मी 80 हजार, वैश्य–बनिया 1 लाख 60 हजार, अति पिछड़ा 3 लाख 40 हजार जिसमें मल्लाह, कुम्हार, नाई, कानू, बढ़ई, तांती, नागर, मालाकार, कहार सहित दर्जनों जाति हैं. वहीं मुसहर 75 हजार, पासवान 71 हजार, अन्य अनुसूचित जाति 65 हजार, सामान्य जाति 1 लाख 5 हजार हैं. सभी दल अपना–अपना जातिगत समीकरण का तर्क देकर चुनावी वैतरणी को पार करने का कयास लगा रहे हैं. [illegible]

प्रेसवार्ता का आयोजन

चार राज्यों के चुनाव परिणाम से बीजेपी के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं. वे राज्यों का चुनाव था, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का आक्रोश था और स्थानीय मुद्दा इस चुनाव में हावी था. उक्त बातें कांग्रेस प्रति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डा. विभूति यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान खगड़िया में कहीं. उन्होंने कहा कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई थी. स्व. इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 3 साल के अन्दर ही फिर अपार बहुमत से सत्ता में वापस आ गई. आज भी हमारे पास सोनिया गांधी जैसी कुशल नेत्री हैं. उनके कुशल नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में पुनः केन्द्र की सत्ता पर काबिज होगी. उन्होंने बीजेपी एवं आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की जनता साम्प्रदायिक ताकतों को देश की सत्ता देने के लिए तैयार नहीं है. इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सहुर रहमान, अजीत कुमार नटवर, प्रभु दयाल सहनी, मतीन सिरीकी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे. ■

[illegible] लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है. क्योंकि अमित राणा का क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में कोई खास पहचान नहीं है. राजद प्रत्याशी के रूप में सम्राट चौधरी परबत्ता विधायक भी प्रयासरत हैं. लेकिन यादव बाहुल्य [illegible] टंटोलने में लगे हुए हैं. इनकी भी इम्मीदवारी तय माना जा रहा है. ई. धर्मेन्द्र आपदा के समय समाज सेवा के लिए विख्यात हैं. वे साफ–सुथरी छवि वाले नई पीढ़ी में अत्यधिक लोकप्रिय माने जाते हैं. ■

अररिया में दिखने लगा लालू की रिहाई का असर

अजातशत्रु अग्रवाल

लालू प्रसाद यादव की रिहाई और इस इलाके में पप्पू यादव की सक्रियता से अररिया संसदीय क्षेत्र का चुनावी परिणाम अवश्य रूप से प्रभावित होगा. लालू प्रसाद ने अपने चुनावी शंखनाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे राज्य में किसी भी सूरत में सांप्रदायिक ताकतों का मनोबल बढ़ने नही देंगे चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े. लालू प्रसाद की रिहाई से अररिया जिले के राजद परिवार में काफी हर्ष का आलम है. राजद जिलाध्यक्ष व नरपतगंज के पूर्व विधायक अनिल यादव का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में पूरा राजद गठबंधन लालू प्रसाद के साथ है. राजद कार्यकर्ताओं में स्पष्ट रूप से यह संदेश पहुंच चुका है कि लालू प्रसाद यादव को एक रणनीति के तहत जेल पहुंचाया गया था ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में राजद की चुनावी धार कमजोर पड़ सके लेकिन इसका असर उल्टे विपक्षी दलों पर हो चुका है. राजद के कार्यकर्ता जहां एकजुट हुए हैं वहीं अररिया संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं में भी लालू प्रसाद के प्रति सहानुभूति की लहर मजबूत हो चुकी है.

वर्तमान में अररिया संसदीय क्षेत्र पर भाजपा के प्रदीप सिंह का कब्जा है. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से राजद का गठबंधन नहीं हो पाने के उपरांत राजद का गठबंधन लोकजनशक्ति पार्टी के साथ हुआ था. गठबंधन के तहत अररिया सीट लोजपा के खाते में गई थी. इस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अररिया के तत्कालीन लोजपा विधायक जाकीर अनवर खान ने अपना भाग्य आजमाया था. चुनाव के दौरान हुए मतदान में खान ने भाजपा के प्रत्याशी को तगड़ी चुनौती दी थी लेकिन विजय खान से दूर रही और जीत का सेहरा सिंह के माथे आया.

वर्तमान में अररिया संसदीय क्षेत्र का चुनावी समीकरण पिछले चुनाव से काफी बदल चुका है. वर्तमान भाजपा के सांसद भी इस वक्त राजग गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे. उन्हें जदयू कार्यकर्ताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ था. वर्तमान में यह गठबंधन टूट चुका है. भाजपा और जदयू अलग अलग हो चुके है. इसका असर भी अगले चुनाव में सामने आएगा. वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है इसके तहत सब कुछ चुनाव से पूर्व होने वाले गठबंधन पर ही निर्भर करेगा. लालू प्रसाद का चुनावी गठबंधन किस किन दलों से होता है यह सबकुछ आने वाले कुछ महीनों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री मो. तसलीमुद्दीन ने अपने एक राजनीतिक बयान में कहा भी है कि वे पार्टी के वफादार सिपाही हैं और वे पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ाएगी, लड़ने के लिए तैयार हैं. उनके इस बयान ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना जता दी है. जदयू से पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल का भी अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है.

बहरहाल किस दल का गठबंधन किस दल से होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड एवं अन्य कई दलों के संभावित उम्मीदवारों के साथ–साथ कुछ राजनेता भी निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुके है. इन सभी के द्वारा अपने–अपने स्तर पर सक्रिय रूप से जनसंपर्क प्रारंभ भी कर दिया गया है. शादी विवाह का अवसर हो या फिर आदमी के जीवन की अंतिम यात्रा का क्रम सभी में ऐसे नेतागण अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूक रहे हैं.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फारबिसगंज के वर्तमान भाजपा विधायक पद्म पराग राय वेणु की माता के निधन पर जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने उनके घर पहुंच कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की वहीं इस क्रम में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने भी वेणु के घर पहुंच कर श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री भले ही इस यात्रा के पीछे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पण की बात करते रहे लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है क्योंकि वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव होना है.

अररिया संसदीय क्षेत्र की चुनावी राजनीति में पूर्णियां के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की भी दिल–चस्पी दिखायी पड़ने लगी है. जेल से अपनी रिहाई के उपरांत पप्पू यादव ने आर्शीवाद यात्रा के बहाने पूर्णियां एवं कोशी कमिश्नरी में अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है. इनके साथ पूर्व सांसद रंजीता रंजन भी काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. ■

सीतामढ़ी में जमीन तलाशती रालोसपा

दिल्ली समेत देश के पांच राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक कवायद जोर पकड़ने लगी है. सूबे की राजनीति में खींचतान के बीच अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है. जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस व बसपा के बाद रालोसपा ने भी फतह को लेकर चुनावी तराजू पर अपनी औकात तौलना शुरू कर दिया है. सीतामढ़ी शहर के गांधी मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि पर किसान–नौजवान महारैली का आयोजन कर रालोसपा ने जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कहा कि बिहार की तकदीर अब बदलेगी...

वाल्मीकि कुमार

वर्ष 2014 के आगमन का तकरीबन सभी को इंतजार है. परंतु राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से साल के आगमन का इंतजार है. कारण कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगले साल ही लोकसभा का चुनाव होना है. बिहार में एनडीए के दो फाड़ होने के साथ ही लगभग सभी दलों ने खुद को पाक–साफ साबित करना शुरू कर दिया है. सत्ताधारी जदयू के निशाने पर जहां साथ रही भाजपा है, वहीं राजद, कांग्रेस, लोजपा व बसपा के निशाने पर सूबे की सरकार है. इस राजनीतिक तिरंदाजी के बीच सभी दल प्रदेश नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. कौन पार्टी किसके साथ मिल कर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेगी, इस बात पर बहस भी जोरों पर है. फिलहाल सीतामढ़ी जिले में सत्ता से लेकर विरोधियों ने भी राजनीति तेज कर दी है. जदयू के मुखिया व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा श्रृंखला चलाकर अपनी उपलब्धि जनता को गिनाते रहे हैं, तो भाजपा बिहार सरकार की सफलता के लिए अपनी पार्टी के उन मंत्रियों व विधायकों की पीठ ठोंक रही है जो बिहार सरकार में कुछ माह पहले तक अहम पद पर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी बिहार के विकास में केंद्र के योगदान को जनता के बीच परोस कर अपनी पुरानी राजनीतिक चौपाल को गुलजार करने की फिराक में है तो राजद भाजपा व जदयू को विफल शासक की संज्ञा देकर पुनः सत्ता पर कब्जा करने का सपना देख रही है. इसके बीच बसपा अलग–अलग कार्यक्रमों में सभी दलों की वादा खिलाफी को चुनावी हथियार बना कर जनमत को अपने पक्ष में करने पर तुली है. चुनाव में अभी वक्त है. होगा क्या, कहना मुश्किल है, लेकिन तैयारी में तकरीबन सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता जरूर लग गए हैं. बहरहाल, रालोसपा के तत्वाधान में आयोजित महारैली में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह पूर्ववत रहा. रालोसपा के जिलाध्यक्ष रामलक्ष्मण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता एवं आफताब अंजुम बिहारी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा. कहा कि सूबे में किसान व नौजवान हासिए पर खड़ा है. सरकारी स्तर पर उत्थान की घोषणा तो की जाती है, परंतु अमल कहीं नजर नहीं आता है. नतीजा है कि बिहार के किसानों को अपनी पहचान तक छुपानी पड़ रही है. सिंचाई की समस्या गंभीर बनी है. खाद–बीज के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन खाद–बीज की तस्करी बदस्तुर जारी है. सूबे में अन्न भंडारण के लिए बने कुल 324 में से 150 स्टोरेज बंद पड़े हैं. वहीं समर्थन मूल्य के नाम पर सरकारी राशि की लूट मची है. कुशवाहा

ने कहा कि बिहार में किसान व नौजवानों पर खतरे की तलवार लटकी है. बेरोजगारी की मार से बेहाल नौजवानों का जीवन समय से पूर्व ही चौपट हो रहा है. इसमें सुधार के लिए ईमानदार पहल करनी होगी. कारण कि परिवर्तन के बाद भी बिहार की स्थिति सुधरी नहीं है. सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति बदतर हो गई है. शिक्षकों के वेतन में असमानता के कारण शिक्षा व्यवबिलख रही है. राज्य सरकार ने अब सेवा निवृत शिक्षकों की बहाली करने का मन बनाया है. ऐसे में नौजवानों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है. कहा कि मुख्यमंत्री की सच्चाई से लोग अवगत हो चुके है. अब सरकार पर किसी को भरोसा नही रह गया है. जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समस्या निदान असंभव है. कुशवाहा ने सभी तबके के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि रालोसपा ही बिहार की तकदीर बदल सकती है. पूर्व सांसद व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार मॉल बना कर माल कमाने की परिपाटी चला दी है. संघर्ष के साथियों की सलाह नीतीश कुमार को कड़वी लगने लगी है और दलाल व आयातित लोग उनके प्रिय होने लगे. कहा कि सूबे में 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई का प्रबंधन था जो अब 9 लाख हेक्टेयर तक सिमट गया है. सूबे की सरकार अखबारों में कृषि रोडमैप बना रही है. बिहार के प्रदूषित पानी की रिपोर्ट को दबा दिया गया है. सरकार में बेईमानों की टोली सक्रिय हो गई है. शिक्षा का सर्वनाश हो रहा है. कॉलेजों में डिग्रिया बांटी जा रही है. लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप ताकत दें तो हम विकल्प देने को तैयार है. कार्यक्रम के दौरान मुकेश कुमार सिंह, चंद्रकला देवी व शिव शंकर प्रसाद यादव ने रालोसपा की सदस्यता ग्रहण की. इस क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय वर्मा, अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नूर हसन आजाद, विनोद कुमार चौधरी, राम पुकार सिन्हा, राघवेंद्र कुमार रवि, राज किशोर उर्फ दारा सिंह, अवधेश कुशवाहा, विशाल कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, श्रीनिवास कुमार मिश्रा, प्रो श्याम कुमार, सुनील पासवान, अमन कुमार सिंह, शिवजी राम, इमेश कुमार, नथुनी अंसारी, मनोज राय व अमरेंद्र सिंह समेत अन्य ने अपना विचार व्यक्त किया. कुल मिला कर रालोसपा ने सीतामढ़ी जिले में अपनी मजबूती के लिए कोई कसर नही छोडी है.■

सीतामढी : सत्याग्रह से सुलग रही आंदोलन की चिंगारी

पिछले 10 दिसंबर को एक ओर सारा देश विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने की तैयारी में लगा था, वहीं सीतामढ़ी जिले में जन समस्याओं के निदान को लेकर संघर्ष यात्रा के तत्वाधान में आमरण अनशन का संकल्प लिया जा रहा था. ऐसा भी नहीं कि यह कार्यक्रम अचानक आयोजित किया गया. परंतु हद तो यह है कि 14 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे लोगों को सरकारी तंत्र ने कोई नोटिस तक लेना मुनासिब नही समझा. अनशन के 7 वें दिन तक सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नही किए जाने के कारण जिले में वृहद आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी है...

वाल्मीकि कुमार

भारत–नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिले से पावन लक्ष्मणा नदी प्रवाहित होती रही है. हाल के दशक में नदी की धारा ने दूसरी दिशा में रास्ता बना ली. नतीजतन नदी की मुख्य धारा में जल प्रवाह पूर्णतः बंद हो गया. आरंभ के साल दो साल तक तो लोग नदी की धारा में पानी का प्रवाह होने की आस लगाए रहे. लेकिन जब बरसात के दिनों में भी नदी के गर्भ में पानी का बहाव नहीं हुआ तो लोगों की चिंता बढ़ने लगी. समय गुजरने के साथ ही नदी एक नारकीय नाले का पर्याय बन कर रह गई है. इस बीच जब किसी सामाजिक कार्यकर्ता अथवा संगठन द्वारा सरकार व प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया गया तो केवल झूठे आश्वासनों पर आंदोलनों को दबाया जाता रहा. हालात यह हो ऐसे हो गए हैं कि किसानों के लिए फसल की सिंचाई से लेकर पशु तक को पानी पिलाने की समस्या गंभीर बन गई और तो और पर्व त्योहार के मौके पर लोगों को नदी की बजाए तालाब अथवा अन्य विकल्प का सहारा लेने की विवशता बन गई. इतने के बाद भी राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में हाजिरी लगाने में माहिर माने जाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या के निदान को लेकर ईमानदार पहल नही की. कुछ ने पहल की भी तो वह महज एक राजनीतिक दिखावा बन कर रह गया. समस्या की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक संगठन लोक चेतना मंच, अमन परिषद और राजद नेत्री शाहीन परवीन एवं संघर्ष यात्रा के तत्वाधान में अलग–अलग तो कभी संयुक्त रूप से धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया जाता रहा. सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आलम रहा कि उक्त आंदोलन स्थानीय अखबारों तक ही सिमट कर रह गया. वर्ष 2002 से समस्या निदान को लेकर आंदोलन की श्रृंखला चलाने वाले संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने याचना नही अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा के संकल्प के साथ आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया है. पिछले 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर समस्या निदान को लेकर आमरण अनशन शहर स्थित लखनदेई पुल के समीप नदी के तट पर ही शुरू कर दिया. कार्यक्रम के 7वें दिन तक आंदोलनकारी के पास प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष दूत का आगमन नहीं हो सका. एक मात्र एसडीओ महेंद्र कुमार ने संवदिया की भूमिका में आकर इतना बता दिया कि डीएम डॉ. प्रतिमा सरकार को इस संबंध में लिखेगी. इसके अलावा किसी भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने अनशन स्थल पर पहुंचना तक मुनासिब नहीं समझा. प्रशासनिक निर्देश के आलोक में चिकित्सा जांच को आने वाले सदर अस्पताल के चिकित्सक व कर्मी महज एक खानापूर्ति ही कर रहे हैं. शशि शेखर के अनुसार, वे डायबिटिज मरीज है, लेकिन समुचित चिकित्सा जांच नहीं की जा रही है. साथ ही प्रशासनिक स्तर पर न ही सुरक्षा की व्यवस्था अनशन स्थल पर की गई है. वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली के जल वैज्ञानिक एकलव्य प्रसाद, लोकअभियोजक अरुण कुमार सिंह, भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद व सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह, बसपा के डॉ. महेश कुमार, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह, जदयू

के गोपेशनंदन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिंह व प्रो. श्याम किशोर सिंह, डॉ. एचपी सिन्हा, सुनील कुमार सुमन, अधिवक्ता श्री–गोपाल, श्रीनिवास मिश्रा, सीता अराधना के दिनेशचंद्र द्विवेदी, डॉ . राजीव रंजन गोपाल, कांग्रेस नेता राम कृपाल शर्मा व संजीव कुमार सिंह समेत दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल पहुंच कर मांगों को जायज करार दिया है. अनशनकारी संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर के साथ बाबा इंद्रदास, राजद की शाहीन परवीन, नरोत्तम व्यास, राजनारायण दास समेत दर्जनों संत व सामाजिक कार्यकर्ता दैनिक रूप से शामिल हो रहे हैं. अनशनकारी की मांगों में सोनबरसा के छोटी भासर दुलारपुर से कटरा तक पुरानी धारा लक्ष्मणा नदी व धुमहा नाला में जल प्रवाह कराने, अघवारा समूह की झीम – जमुरा नदी पर तटबंध निर्माण की उपयोगिता का जांच कराने के बाद ही निर्माण कराने, तटबंध निर्माण व मरम्मत कराने वाली मेसर्स ब्रह्मपुत्र कंस्ट्रक्शन एवं मेसर्स अवन्तिका धडा रेडी एण्ड ब्रदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, बागमती एवं अघवारा समूह की नदियों पर दोनो तटबंध के बीच परने वाली समस्त जमीन का मुआवजा देने, अघवारा व बागमती पर हुए तटबंध निर्माण में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा नए कानून के अनुसार किसानों को देने, तटबंध से सटा कर मिट्टी कटाई की जांच कर कार्रवाई करने, अघवारा समूह की नदी पर दोनो तटबंध के बीच पड़ने वाले गांव की जानकारी छुपाकर भारतीय जल आयोग से योजना की स्वीकृति कराए जाने की जांच कराने, निर्माण कंपनी के आपराधिक गिरोहों से सांठ–गांठ की जांच कराने, सत्याग्रहियों पर किए गए बथनाहा कांड संख्या– 115/13 एवं सीतामढ़ी कांड संख्या – 1057/13 को समाप्त कराने, बढ़ते नक्सल–वाद के फैलाव पर रोक लगाने एवं बागमती व अघवारा नदी में 2 सौ करोड़ के मिट्टी घोटाला की उच्च स्तरीय जांच के साथ कार्रवाई कराने समेत अन्य मांगें शामिल हैं. वैसे उक्त मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी है. लोग आते और जाते है. परंतु लक्ष्मणा नदी की दुर्दशा एवं तटबंध निर्माण मामले को लेकर अब जिले में लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है. आंदोलन जैसे–जैसे आगे बढ़ रहा है जनमानस में सरकार व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है. समय रहते सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर अगर सत्याग्रह से सुलग रही आंदोलन की चिंगारी पर गौर नही किया गया तो संभव है कि आने वाले दिनों में जिला वृहद आंदोलन का केंद्र बन सकता है. कारण कि एक ओर नदी में जल प्रवाह का अभाव किसानों के लिए मुसीबत बनी है तो दूसरी ओर तटबंध निर्माण एजेंसी की मनमानी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है. किसानों का हितैषी होने का दंभ भरने वाली राज्य सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि इस सुलगते जनआंदोलन को गंभीरता से लेती है अथवा नहीं, यह तो समय ही बताएगा. परंतु इतना तो तय है कि समय रहते कारगर पहल नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में यह एक गंभीर मुद्दा बन कर सत्ता से विपक्ष तक को सांसत में डाल सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

शिक्षक सम्मेलन का आयोजन

स्वामी विवेकानंद सार्धशती वर्ष के अवसर पर लोक शिक्षा समिति के तत्वाधान में जिला शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया. सीतामढ़ी शहर के मध्य स्थित राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डीईओ कुमार सहजानंद व संचालन आचार्य विद्यानंद झा ने किया. मौके पर विभाग निरीक्षक अखिलेश मिश्र, विद्या मंदिर के प्राचार्य अजय कुमार मिश्रा, पूर्व प्राचार्य किरण प्रसाद, डॉ. लक्ष्मण झा, डॉ. वसंत मिश्रा, अभय कुमार गर्ग, ललन कुमार झा, जयराम सिंह, प्रो. वीरेंद्र सिंह, महंत अशोक दास, विकास कुमार मिश्र, नागेंद्र तिवारी, डॉ अनिता झा, रमेश झा, प्रमोद राय, अमरेश चौबे, हरि किशोर पाठक, चुनचुन सिंह, नीतेश भारद्वाज, घनश्याम मिश्र व सुरेश जालान समेत अन्य थे.

–वाल्मीकि

विवाह भवन का उद्घाटन

ख्यातिप्राप्त संत तपस्वी नारायण दास जी महाराज के शिष्य रामाज्ञा दास ने पिछले दिनों पुपरी स्थित कृष्णा कॉम्पलेक्स मार्केट में विवाह भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उद्घाटन किया. मौके पर पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार यादव, कृष्ण कुमार, नगर अध्यक्ष मनोज यादव, वार्ड आयुक्त श्याम राज, मदन साह, रामवृक्ष यादव, राजद जिलाध्यक्ष मो शफीक खां, तारकेश्वर प्रसाद यादव, मो. अमजद अली समेत अन्य थे.

–गोविंद कुमार

पानी की कमी से जूझता जिला समाहरणालय

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित समाहरणालय परिसर में पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है. संपूर्ण जिले को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की योजना बनाने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी खुद ही प्यासे रहने को बाध्य है. कारण कि समाहरणालय परिसर में लगाए गए करीब आधा दर्जन हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हैं. एक बचा भी है तो पिछले हिस्से में होने के कारण कोई खास महत्व का नहीं रह गया है. आलम है कि समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों के अलावा जिले के कोना–कोना से आने वाले आम लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए समाहरणालय परिसर से बाहर भटकने की विवशता बनी रहती है.

–वाल्मीकि

जमुई में हृदय जांच

स्कॉट हार्ट हॉस्पीटल, नई दिल्ली एवं जमुई की अग्रणी स्वयं सेवी संस्था नलिनी फाउन्डेशन के संयक्त तत्वाधान में जमुई में दो दिवसीय हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन नागेश्वर काम्पलेक्स में किया गया. इस जांच शिविर व हृदय रोग से बचाव पर परिचर्चा का उद्घाटन अशोक नगर भवन में माननीय जिलाधिकारी श्री शशिकांत तिवारी ने दीप प्रज्जवलित कर किया. उन्होंने इस तरह के जांच शिविर एवं हृदय रोग से बचाव पर परिचर्चा आयोजित करने के लिए नलिनी फाउन्डेशन के सचिव निर्मल कुकार की प्रशंसा की. जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रकार की जांच शिविर ग्रामीण इलाके में भी लगाने को कहा ताकि ग्रामीण इलाके में रह रहे लोग भी अपने स्वास्थ्य की वेहतर जांच करा सकें. जिला विधि संकाय के अध्यक्ष निरंजन कुमार सिंह, सचिव, शकलदेव यादव, अधिवक्ता रंजीत कुमार एवं ठाकुर नवीन सिंह एवं उत्तम जी ने इस जांच शिविर के लिए नलिनी फाउन्डेशन की तारीफ की. स्कॉट हॉस्पीटल के कॉर्डियोलॉजिस्ट डा. अरविन्द एवं डा. शहजाद ने बताया कि इस जांच शिविर में 300 रोगयों की हृदय संबंधी जांच की गई.

–इमरान खान

लालजी प्रसाद सिंह की पुस्तक का लोकार्पण

प्रसिद्ध कथाकार डा. लालजीप्रसाद सिंह की 39वीं पुस्तक 'शुभी की दीवाली'का लोकार्पण–मार्च अनोखे अन्दाज में कारगिल चौक से जेपी गोलम्बर, गांधी मैदान(पटना)तक गाजे–बाजे, लाउडस्पीकर एवं तिरंगे के साथ शंख, डमरू, झाल–करताल एवं घड़ीघंट बजाते हुए निकाला गया. उक्त अवसर पर प्राचार्य डॉ. आर्य ने कहा कि कथाकार डॉ. सिंह की किताबों को लेकर लोकार्पण–मार्च का जो नया और अनोखा तरीका हमने निकाला है, वह हमारे देश में कहीं भी नहीं है. उक्त अवसर पर कथाकार डा. लालजीप्रसाद सिंह ने कहा कि रोज सुबह–सबेरे स्कूल जाने की उम्र में छोटे–छोटे बच्चे–बच्चियों को कचरे पर जाते देख कर हृदय भावुक हो उठता है, फिर आक्रोश महसूस होता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम कैसा हिन्दुस्तान गढ़ रहे हैं. उक्त लोकार्पण मार्च को सफल बनाने में प्रो. आर. एस. तिवारी, प्रो. बी.के. राय, प्रो. सी.डी. सिंह, प्रो. संजय ठाकुर, प्रो. रंजना कुमारी, उपेन्द्र कुमार, प्रो. पंकज कुमार, प्रो. नवीन कुमार, मनोज कुमार, डॉ. सुषमा सिन्हा, प्रो. रीना सिन्हा, प्रो. मीरा कुमारी, दीपक कुमार, प्रो. धर्म नाथ सिंह तथा छात्र–छात्राओं में सिमरन, बबीता कुमारी, पूजा रानी, सलमान खान, नेहा कुमारी, हनी रानी, रौशन मिश्रा, ज्योतिका कुमारी, कर्ण कुमार, विक्रांत कुमार, अनामिका कुमारी, यशकीर्ति कुमारी, रश्मि कुमारी, कुणाल कुमार, श्वेता कुमारी, राज कुमार, विशाल कुमार इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

–अमृता कुमारी

डॉ. देवेन्द्र प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष मनोनीत

मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई में 12–14 दिसम्बर, 2013 के दौरान आयोजित भूगोलवेत्ताओं की राष्ट्रीय स्तर की लब्ध प्रतिष्ठ शोध संस्था नेशनल एसोशिएसन ऑफ ज्योग्राफर्स, इंडिया के 35वें तीन दिवसीय भूगोल कांग्रेस में प्रो. डॉ. देवेन्द्र प्रसाद सिंह को नागी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है. प्रोफेसर सिंह लम्बे समय से नागी की तमाम गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं. प्रोफेसर सिंह नैक द्वारा ग्रेड ए एवं यू.जी.सी द्वारा सी.पी.ई. प्रतिष्ठा प्राप्त स्थानीय ए.एन. कॉलेज, पटना में भूगोल के स्नातकोत्तर केंद्र के विभागाध्यक्ष हैं एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की अनेक भौगोलिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका में हैं. उन्होंने लगभग छह दर्जन अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की भौगोलिक गोष्ठियों–संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, एवं सम्मेलनों में अपने शोध–पत्र प्रस्तुत किए हैं. उनके कई दर्जन शोध–पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं. उन्होंने इंटरमीडिएट से एम.ए. स्तर तक की भूगोल की लगभग एक दर्जन पुस्तकों का लेखन का भी किया है.

–अमृता कुमारी

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

गंदे पानी से बचें
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
AREX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
REPL
9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित